

भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 13]

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 1, 1995/चैत्र 11, 1917

No. 13]

NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 1, 1995/CHAITRA 11, 1917

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सार्वधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(other than the Ministry of Defence)

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय
(विधि कार्य विभाग)
(न्यायिक अनुभाग)

नई दिल्ली, 23 मार्च, 1995

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY
AFFAIRS

(Department of Legal Affairs)

(Judicial Section)

New Delhi, the 23rd March, 1995

का.प्रा. 837.—केन्द्रीय सरकार ने नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा 10 के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जांच करने पर यह पाया है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त नोटरी श्री नारायण राम ने अपने कदाचार के कारण स्वयं को नोटरी के रूप में कार्य करने के अयोग्य बना दिया है ;

अतः, नोटरी नियम, 1956 के नियम 13 के साथ पठित नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार श्री नारायण राम को फतेहपुर, जिला सांकर, राजस्थान में नोटरी के रूप में कार्य करने के लिए दिए गए व्यवसाय-प्रमाणपत्र (पंजीकरण संख्या 354) को रद्द करती है और उन्हें नोटरी के रूप में कार्य करने से विवर्जित करती है।

[सं. एफ-5(14)/91-न्यायिक]
पी. सी. कण्णन, सक्षम प्राधिकारी

S.O. 837.—Whereas the Central Government upon the inquiry under the powers conferred by Clause (d) of Section 10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) found that Shri Narayan Ram, a Notary appointed by the Central Government rendered himself unfit to practice as a Notary for his misconduct ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 10 of the Notaries Act, 1952 (read with Rule 13 of the Notaries Rules, 1956, the Central Government hereby order the cancellation of Certificate of Practice (Regd No. 354) granted to Shri Narayan Ram as Notary at Fatehpur, District Sikar, Rajasthan and also debar him from practice as a Notary.

[No. F. 5(14)/91-Judl.]
P. C. KANNAN, Competent Authority

गृह मंत्रालय
(पुनर्वास प्रभाग)

नई दिल्ली, 1 मार्च, 1995

का. आ. 838 :—निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रबंध अधिनियम, 1950 (1950 का 31) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के भूमि एवं भवन विभाग, निष्क्रान्त सम्पत्ति सैल, में सहायक बन्दोबस्त अधिकारी, श्री एस. के. गुलिया को, अपने स्वयं के दायित्वों के जतिरिक्त, उक्त अधिनियम के द्वारा अथवा उसके अधीन सहायक बन्दोबस्त अभिरक्षक को सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करने के उद्देश्य से, तत्काल प्रभाव से निष्क्रान्त सम्पत्ति के सहायक अभिरक्षक के रूप में नियुक्त करती है।

[सं. 1 (6) /93—बन्दोबस्त (ख)]

आर. एस. आहुजा, अवसरसचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(Rehabilitation Division)

New Delhi, the 1st March, 1995

S.O. 838.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 6 of the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (31 of 1950), the Central Government hereby appoints Shri S. K. Gulia, Assistant Settlement Officer in the Land and Building Department, Evacuee Property Cell, Government of the National Capital Territory of Delhi as Assistant Custodian of Evacuee Property, in addition to his own duties, for the purpose of performing the functions assigned to such Assistant Custodian by or under the said Act, with immediate effect.

[No. 1(6)/93-SETTLEMENT(B)]

R. S. AHUJA, Under Secy.

नई दिल्ली, 1 मार्च, 1995

का. आ. 839 :—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर एवं पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के भूमि एवं भवन विभाग निष्क्रान्त सम्पत्ति सैल में सहायक बन्दोबस्त अधिकारी श्री एस. के. गुलिया को अपने स्वयं के दायित्वों के जतिरिक्त क्षतिपूर्ति पूल के भाग के रूप में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्थित अधिग्रहित निष्क्रान्त शहरी एवं ग्रामीण सम्पत्तियों तथा भूमियों के प्रबन्ध और निपटान के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम के द्वारा अथवा उसके अधीन, एक प्रबंध अधिकारी को सौंपे गए कार्यों के निष्पादन के उद्देश्य से प्रबंध अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

[1 (6)/93—बंदोबस्त (क)]

आर. एस. आहुजा, अवसरसचिव

New Delhi, the 1st March, 1995

NOTIFICATION

S.O. 839.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 3 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954), the Central Government hereby appoints Shri S. K. Gulia, Assistant Settlement Officer in the Land and Building Department, Evacuee Property Cell, Government of the National Capital Territory of Delhi as Managing Officer in addition to his own duties, for the purpose of performing the functions assigned to a Manager Officer by or under the said Act, in respect of management and disposal of acquired evacuee urban and rural properties and lands situated in national Capital Territory of Delhi forming a part of the Compensation Pool.

[No. 1(6)/93-SETTLEMENT(A)]

R. S. AHUJA, Under Secy

कामिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कामिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 15 मार्च, 1995

का.आ. 840.—केन्द्रीय सरकार, आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारक) अधिनियम, 1987 (1987 का 28) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री ए.वी. सोमसुन्दरम, अधिवक्ता, सं. 8, तीसरा तल, एस. एम. प्लाजा, 45 अरमेनियन स्ट्रीट, मद्रास-1 को, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन द्वारा संस्थित मामला सं. आर. सी. 16(एस)/93/सी.बी. आई./एस.सी.बी./मद्रास (आर.एस.एस. मुख्यालय-मद्रास बम विस्फोट मामला), उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन अभिहित न्यायालय, तमिलनाडु, मद्रास और अपील एवं पुनरीक्षण न्यायालय में उपरोक्त उक्त मामले में उद्भूत होने वाली किसी अन्य कार्यवाहियों का संभालन करने के लिए भी ऊपर लोक अभियोजक नियुक्त करती है।

[संख्या 225/40/94-ए. वी. बी.-II]

एस. सौन्दर राजन, अवसर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, P. G. AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 15th March, 1995

S.O. 840.—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of Section 13 of the Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act, 1987 (Act No. 28 of 1987), the Central Government hereby appoints Shri A. V. Somasundaram, Advocate, No. 8, 3rd Floor, S. M. Plaza, 45 Armenian Street, Madras-1 as Additional Public Prosecutor for conducting the case No. RC. 16(S)/93-CBI-SCB/Madras (R.S.S. Headquarters—Madras Bomb Blast Case) instituted by Delhi Special Police Establishment in the designated Court, Tamil Nadu, Madras under section 9 of the said Act, and also any other proceedings arising out of the above said case in Appellate or Revisional court.

[N. 225/40/94-AVD.II]

S. SOUNDAR RAJAN, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

आयकर महानिदेशक (छूट) का कार्यालय

कलकत्ता, 10 जनवरी, 1995

(आयकर)

का. आ. 841:—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, प्रौद्योगिकी भवन" न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली—110016 को भेजेगा, और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

सेन्ट्रल कौंसिल फोर रिसर्च इन आयुर्वेद एंड सिद्धा,
एस-10, ग्रीन पार्क एक्सटेन्शन मार्केट,
नई दिल्ली-16

यह अधिसूचना दिनांक 3-2-90 से 31-3-92 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी :—1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को मुद्दाब दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें

अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करनी है।

[संख्या: 1310 (एफ. स. म. नि./भा. क. (छूट) एन. डि-67/35 (1) (ii)/90—भा. क. (छूट)]

भार. सिंह, उप निदेशक आयकर (छूट)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

Office of the Director General of Income tax (Exemptions)
Calcutta, the 10th January, 1995

(INCOME TAX)

S.O. 841.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purpose of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited income and expenditure account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Central Council for Research in Ayurveda and Siddha,
S-10, Green Park, Extension Market,
New Delhi-16.

This Notification is effective for the period from 3-2-1990 to 31-3-92.

Notes:

1. Condition (i) above will not apply to organisation categorised as associations.
2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1310/F. No. DG/IT(E)/ND-6735(1)(ii)/90-IT(E)]
R. SINGH, Dy. Director, of Income tax (Exemptions)

कलकत्ता, 10 जनवरी, 1995

का. आ. 842:—आयकर सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।

(ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, प्रौद्योगिकी भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली—110016 को भेजेगा, और

(iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (1) में दी गई रिमर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

सेन्ट्रल काउंसिल फ़ॉर रिसर्च इन आयुर्वेद एण्ड सिद्ध,
एस-10, ग्रीन पार्क, एक्सटेन्शन मार्केट,
नई दिल्ली-16

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-92 से 31-3-95 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी :—1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करनी है।

[संख्या : 1311 (एफ. सं. म. नि/आ. क. छूट)/

एन. डि.—67/35 (1) (ii)/90-आ. क. (छूट)]

आर. सिंह, उप निदेशक आयकर (छूट),

Calcutta, the 10th January, 1995

(INCOME TAX)

S.O. 842.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purpose of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, Technology

Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and

(iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited income and expenditure account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961.

NAMING OF THE ORGANISATION

Central Council for Research in Ayurveda and Siddha,
S-10, Green Park Extension Market,
New Delhi-16.

This Notification is effective for the period from 1-4-1992 to 31-3-1995.

Notes :

1. Condition (i) above will not apply to organisation categorised as associations.
2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval to the Director General of Income-tax (Exemption), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1311/F. No. DG/IT(E)/ND-67/35(1)(ii)/90-IT(E)]

R. SINGH, Dy. Director of Income-tax (Exemptions)

कलकत्ता, 10 जनवरी, 1995

(आयकर)

का. आ. 843 :—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है:—

(i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए भलग लेखा बहियां रखेगा।

(ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, प्रौद्योगिकी भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली—110016 को भेजेगा, और

(iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (1)

में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

सेन्ट्रल कोसिल फोर रिसर्च इन आयुर्वेद एण्ड सिद्धा,
एस-10, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन मार्केट,
नई दिल्ली—16

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-95 से 31-3-96 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी :—1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को मुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या: 1312 (एफ. सं. म. नि./आ. क. (छूट)/एन. डि.-67 (35) (1) (ii) / 90—आ. क. (छूट)]

आर. सिंह, उप निदेशक, आयकर (छूट)

Calcutta, the 10th January, 1995

(INCOME TAX)

S.O. 843.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purpose of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited income and expenditure account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Central Council for Research in Ayurveda and Siddha,
S-10, Green Park Extension Market,
New Delhi-16.

This Notification is effective for the period from 1-4-1995 to 31-3-1996.

Notes:

1. Condition (i) above will not apply to organisation categorised as associations.
2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1312/F No. DG/IT(E)/ND-67/35(1)(ii)/90-IT(E)]
R. SINGH, Dy. Director of Income-tax (Exemptions)

कलकत्ता, 10 जनवरी, 1995

(आयकर)

का. आ. 844:—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है:—

- (1) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 तई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन" न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली—110016 को भेजेगा, और
- (3) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

स्माल इंडस्ट्रीज टेस्टिंग एण्ड रिसर्च सेन्टर,
25 ए, अवरमपलायम रोड,

के. आर. पुरम पो. ओ., कोयमम्बटूर—641006

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-92 से 31-3-93 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी :—1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या : 1313 (एफ. सं. म. नि/आ. क. (छूट)/टि. एन.--26/35 (1) (ii)/89--आ. क. (छूट)]

आर. सिंह, उप निदेशक आयकर (छूट)

Calcutta, the 10th January, 1995

(INCOME TAX)

S.O. 844.--It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purpose of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited income and expenditure account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Small Industries Testing & Research Centre,
25A, Avarampalayam Road,
K. R. Puram P.O.,
Coimbatore-641006.

This Notification is effective for the period from 1-4-1992 to 31-3-1993.

Notes:

1. Condition (i) above will not apply to organisation categorised as associations.
2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1313/F. No. DG/IT(E)/TN-26/35(1)(ii)/89-IT(E)]
R. SINGH, Dy. Director of Income-tax (Exemptions)

कलकत्ता, 10 जनवरी, 1995

(आयकर)

का.आ. 845.--सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" संवर्ग के अधीन अनुमादित किया गया है:--

(i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अनग लेखा बहियां रखेगा।

(ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन" न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और

(iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 को धारा 35(1) में दी गई रिमिच किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-उपय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

स्माल इंडस्ट्रीज टेस्टिंग एंड रिसर्च सेंटर

25ए अवरम पलायम रोड, के. आर. पुरम पो. ओ.
कोयम्बटूर 641008

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-93 से 31-3-95 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी: 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या : 1314 (एफ. सं. म. नि/आ. क. (छूट)/टि.एन.26/35(1) (ii)/89--आ. क. (छूट)]

आर सिंह,
उप निदेशक आयकर (छूट)

Calcutta, the 10th January, 1995
(INCOME TAX)

S.O. 845.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purpose of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, Technology Bhawan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited income and expenditure account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961.

NAMF OF THE ORGANISATION

Small Industries Testing & Research Centre,
25A, Avarampalayam Road,
K. R. Puram P.O.,
Coimbatore-641006.

This Notification is effective for the period from 1-4-1993 to 31-3-1995.

Notes:

1. Condition (i) above will not apply to organisation categorised as associations.
2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1314/F. No. DG/IT(E)/TN-26/35(1)(ii)/89-IT(E)]
R. SINGH, Dy. Director of Income-tax (Exemptions)

कलकत्ता, 10 जनवरी, 1995

(आयकर)

का. आ. 846.—मर्यादाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है:—

(i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा;

(ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रायोगिकी भवन" न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा; और

(iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

हर्मोन रिसर्च फाउण्डेशन,
ए-22, फ्रीडम फाईटर्स, कल्चरल सेंटर,
नेवसराय, नई दिल्ली-110068.

यह अधिगूचना दिनांक 1-4-96 से 31-3-97 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी: 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करे, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या: 1315/एफ. सं. म.नि./आ.क. (छूट) एन.डि.-[II/
35(1) (ii)/आ.क. (छूट)]

आर. सिंह, उपनिदेशक आयकर (छूट).

Calcutta, the 10th January, 1995

(INCOME TAX)

S.O. 846.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purpose of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, Technology Bhawan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited income and expenditure account in respect of its research activities for which exemption was

granted under sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Hormone Research Foundation,
A-22, Freedom Fighter's Cultural Centre Nebasara,
New Delhi-110068.

संगठन का नाम

नेशनल हॉर्मोन्युट आफ बैंक मैनेजमेंट
कोन्डवे खुर्द, पोस्ट बॉक्स नं.-1,
पुणे-411022

This Notification is effective for the period from 1-4-1996 to 31-3-1997.

Notes :

1. Condition (i) above will not apply to organisation categorised as associations.
2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1315 F. No. DG/IT(E)/ND-III/35(1)(ii)/91-IT(P)]

R. SINGH, Dy. Director of Income-tax (Exemptions)

कलकत्ता, 10 जनवरी, 1995

आयकर

का.आ. 847—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के लिये, आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" संवरी के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

(i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए प्रलग लेखा बहियां रखेगा।

(ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिक भवन" न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और

(iii) यह प्रत्येक वर्ष की 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की एक प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है, और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा (1) 35 में दी गई रिस्वें किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को प्रस्तुत करेगा।

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-91 से 31-3-94 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संघर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या 1316 (एफ.सं. म. नि./आ.क. (छूट)/एम-99/35(1)(iii)/90-आ.क. (छूट)]

आर. सिंह, उप निदेशक आयकर (छूट)

Calcutta, the 10th January, 1995

(INCOME TAX)

S.O. 847.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purpose of clause (iii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities ;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year ; and

- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions). (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited income and expenditure account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

संगठन का नाम

National Institute of Bank Management,
Kondhwa Khurd,
Post Bag No. 1,
Pune-411022.

नेशनल इंस्टीट्यूट आफ बैंक मैनेजमेंट,
कोन्डवे खुर्द, पोस्ट बैग नं. 1,
पुणे-411022

This Notification is effective for the period from 1-4-1991 to 31-3-1994.

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-94 से 31-3-95 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

Notes :

1. Condition (i) above will not apply to organisation categorised as associations.
2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1316/F. No. DG/IT(E)-M-99/35(1)(iii)-90-IT(E)]
R SINGH, Dy. Director of Income tax (Exemptions)

कलकत्ता, 10 जनवरी, 1995
(आयकर)

का.आ. 848 :—सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) खण्ड (iii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (1) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, प्रौद्योगिकी भवन" न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (3) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिमाब को भी प्रस्तुत करेगा।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्तें (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

- 2 संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संवर्ध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या : 1317 (एफ.सं. म.नि./आ.क. (छूट)/एम-99/35 (1) (ii)/90-आ.क. (छूट)]

आर. सिंह, उप निदेशक आयकर (छूट)

Calcutta, the 10th January, 1995

(INCOME-TAX)

S.O 848.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purpose of clause (iii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited income and expenditure account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

National Institute of Bank Management,
Kondhwe Khurd,
Post Bag No. 1,
Pune-411022.

This Notification is effective for the period from 1-4-1994 to 31-3-1995.

Notes :

1. Condition (i) above will not apply to organisation categorised as associations.
2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1317/F. No. DG/IT(E)/M-99/35(1)(iii)/90-IT(E)]
R. SINGH, Dy. Director of Income-tax (Exemptions)

कलकत्ता, 10 जनवरी, 1995

(आयकर)

का.आ. 849.—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित, किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (iii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर “संस्थान” संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है:—

(i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।

(ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, प्रौद्योगिकी भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और

(iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया, संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

कर्वे इंस्टीच्यूट आफ सोशल सर्विस,
हिलसाइड, 18ए, कर्वे नगर,
पुणे-411052.

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-93 से 31-3-95 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी: 1. उपर्युक्त शर्त (1) ‘संघ’ जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में किए आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या: 1318/एफ. सं. म.नि./आ.क. (छूट)/एम-124/
35(1)(iii) 90-आक (छूट)]

आर० सिंह, निदेशक आयकर छूट

Calcutta, the 10th January, 1995

(INCOME-TAX)

S.O. 849.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purpose of clause (iii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category “Institution” subject to the following conditions:

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, ‘Technology Bhawan’, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited income and expenditure account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Karve Institute of Social Service,
Hillside, 18-A, Karve Nagar,
Pune-411052.

This Notification is effective for the period from 1-4-1993 to 31-3-1995.

Notes :

1. Condition (i) above will not apply to organisation categorised as associations.
2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies

of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1318/F. No. DG/IT(E)/M-125/35(1)(iii)/90-IT(E)]

R. SINGH, Dy. Director of Income-tax (Exemptions)

कलकत्ता, 10 जनवरी, 1995

(आयकर)

का.आ. 850:—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संघ" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :-

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, प्रौद्योगिकी भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (1) में दो गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

एम.एल.साह रिसर्च फाउंडेशन फॉर स्टोन इंडस्ट्रीज,
नोबल-ए, 3 वीं मंजिल,
नेहरू ब्रिज के पीछे, आश्रम रोड,
अहमदाबाद-380009

यह अधिवृत्त दिनांक 1-4-93 से 31-3-95 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी: 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने

के संबंध में किए आवेदन-पत्र को 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या : 1319/एफ.सं.म.नि./आ.क. (छूट)/
जि. 20/35 (i) (ii)/89-आ.क. (छूट)]

आर.सिंह, उप निदेशक आयकर (छूट)

Calcutta, the 10th January, 1995

(INCOME-TAX)

S.O. 850.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purpose of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions:

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited income and expenditure account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

M. L. Shah Research Foundation for Stone Industries,
Nobles-A, 3rd Floor,
Opp. Nehru Bridge, Ashram Road,
Ahmedabad-380009.

This Notification is effective for the period from 1-4-1993 to 31-3-1995.

Notes:

1. Condition (1) above will not apply to organisation categorised as associations.
2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1319/F. No. DG/IT(E)/G-20/35(1)(ii)/89-IT(E)]
R. SINGH, Dy. Director of Income-tax (Exemptions)

कलकत्ता, 12 जनवरी, 1995

(आयकर)

का.आ. 851:—पर्वसाधारण को एन.द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खण्ड (iii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :-

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए खलग लेखा बहिया रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, प्रौद्योगिकी भवन, एम्. मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (1) में दी गई रिमच किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

एशियन सेंटर फॉर ऑर्गनाइजेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट,
सी-126, ग्रेटर किलाश-1,
नई दिल्ली-110048

यह अधिसूचना दिनांक 1-1-90 में 31-3-92 तक को अवधि के लिए प्रभावी है।

- टिप्पणी 1. उपयुक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।
2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या : 1320 (एफ.सं.स.नि./आ.क. (छूट)/
एन.डि.-18/35 (1) (iii)/90-आ.क. (छूट)]

आर. सिंह, उपा निदेशक आयकर (छूट)

Calcutta, the 12th January, 1995

(INCOME-TAX)

S.O. 851.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purpose of clause (iii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited income and expenditure account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Asian Centre for Organisation Research & Development,
C-126, Greater Kailash-I,
New Delhi-110048.

This Notification is effective for the period from 1-4-1990 to 31-3-1992.

Notes:

1. Condition (i) above will not apply to organisation categorised as associations.
2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1320/F. No. DG/IT(E)/ND-48/35(1)(iii)/90-IT(E)]
R. SINGH, Dy. Director of Income tax (Exemptions)

कलकत्ता, 12 जनवरी, 1995

(आयकर)

का.आ. 852:—पर्वसाधारण को एन.द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :-

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए खलग लेखा बहिया रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, प्रौद्योगिकी भवन,

न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और

of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961.

- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (1) में दी गई रिमर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिमात्र को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

एशियन सेंटर फॉर ऑर्गनाइजेशन रिसर्च फंड डेवलपमेंट,
मो-126, ग्रेटर कैलाश-I,
नई दिल्ली 110048

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-92 से 31-3-94 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी: 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संध" जैसा संवग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियां में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या : 1321 (एफ. नं. म. नि./आ. क. (छूट)/
एन. डि-48/35 (i) (iii)/90-आ. क. (छूट)]

आर. सिंह, उप निदेशक, आयकर (छूट)

Calcutta, the 12th January, 1995

(INCOME TAX)

S.O. 852.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purpose of clause (iii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:

- The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, Technology Bhawan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited income and expenditure account in respect

NAME OF THE ORGANISATION

Asian Centre for Organisation Research & Development,
C-126, Greater Kailash I, New Delhi-110048.

This Notification is effective for the period from 1-4-92 to 31-3-94.

Notes : 1. Condition (i) above will not apply to organisation categorised as associations.

2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1321 (F. No. DG/IT(E)/ND-48/35(1)(iii)/90-IT(E)]
R. SINGH, Dy. Director of Income Tax (Exemptions)

कलकत्ता, 25 जनवरी, 1995

(आय-कर)

का.आ. 853:-सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के लिये आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है:—

(i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिये अलग लेखा बहियां रखेगा।

(ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन" न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और

(iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट) (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा (35) (1) में दी गई रिमर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिमात्र को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

एसोसिएशन आफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, ए.आई.
यू हाउस, 16 कोटला मार्ग, नई दिल्ली-110002

यह अधिसूचना दिनांक 4-5-92 से 31-3-93 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

टिप्पण : 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिये लागू नहीं होगा।

कलकत्ता, 25 जनवरी, 1995

(आय-कर)

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किये आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या 1322 (एफ. सं. म. नि./आ. क. (छूट)
एन.डी. 115/35(1) (iii)]

आर. सिंह, उप निदेशक आयकर (छूट),

Calcutta, the 25th January, 1995

(INCOME TAX)

S.O. 853.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purpose of clause (iii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; &
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited income and expenditure account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Association of Indian Universities AIU House, 16 Kolla Marg, New Delhi-110002.

This Notification is effective for the period from 4-5-92 to 31-3-93.

Notes : 1. Condition (i) above will not apply to organisation categorised as associations.

2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1322 (F. No. DG/IT(E)/ND-115/35(1)(iii)/93]

R. SINGH, Dy. Director of Income Tax (Exemptions)

का.आ. 854:—संवर्गसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के लिये आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है:—

(i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिये अलग लेखा बहियां रखेगा।

(ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन" न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा; और

(iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

एसोसिएशन आफ इंडियन यूनिवर्सिटीज ए.आई. यू. हाउस, 16, कोल्ला मार्ग, नई दिल्ली।

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-93 से 31-3-95 के लिये प्रभावी है।

टिप्पणी :—1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिये लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या, 1323(एफ. सं. म. नि./आ. क. (छूट)/
एन.डी. 115/35(1) (iii)]

आर सिंह, उप निदेशक आयकर (छूट)

Calcutta, the 25th January, 1995
(INCOME TAX)

S.O. 854.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purpose of clause (iii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited income and expenditure account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Association of Indian Universities AIU House, 16, Kotla Marg, New Delhi-110002.

This Notification is effective for the period from 1-4-93 to 31-3-95.

Notes : 1. Condition (i) above will not apply to organisation categorised as associations.

2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1323/F. No. DG/IT(F)/Cal./ND-115/35(I)(iii)90-91]
R. SINGH, Dy. Director of Income Tax (Exemptions)

कलकत्ता, 25 जनवरी, 1995

(आयकर)

का. आ. 855.—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संघ" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है:—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग "प्रौद्योगिकी भवन" न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली 110016 को भेजेगा, और

(iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर, तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक छूट, (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिमर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा—परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

अहमदाबाद टेक्स्टाइल इंडस्ट्रीज रिमर्च एसोसिएशन,
पोलीटेक्नीक अहमदाबाद-380015

यह अभिसूचना दिनांक 1-4-91 से 31-3-92 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी:—1 उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता का तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या 1324/एफ.सं.सं.नि./आ. क. (छूट)/नि. 33/
35(1) (ii) 90-91]

आर० सिंह, उप निदेशक आयकर (छूट)

Calcutta, the 25th January, 1995

(INCOME TAX)

S.O. 855.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purpose of clause (iii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions:

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year a copy of its

audited Annual Accounts and also a copy of audited income and expenditure account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Ahmedabad Textile Industries Research Association, Polytechnic, P.O. Ahmedabad 380015.

This Notification is effective for the period from 1-4-91 to 31-3-92.

Notes : 1. Condition (i) above will not apply to organisation categorised as associations.

2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1324/F. No. DG/IT(E)/cal./G-33/35(1)(ii)/90-91]
R. SINGH, Dy. Director of Income Tax (Exemptions)

कलकत्ता, 25 जनवरी, 1995

(आयकर)

का.आ. 856.—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संघ" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, प्रोद्योगिकी भवन" न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (1) में दी गई रिमर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिमाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

अहमदाबाद टेक्स्टाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च

एसोसिएशन, पोलिटेक्नीक पी.ओ.

अहमदाबाद-380015

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-92 से 31-3-95 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार संगठन में पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र को 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या 1325/एफ.सं.म.नि./आ.क. (छूट)/जि-33/35
(1)(ii)]

आर. सिंह, उप निदेशक आयकर (छूट)

Calcutta, the 25th January, 1995

(INCOME TAX)

S.O. 856.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purpose of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities ;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, "Technology Bhawan" New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited income and expenditure account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Ahmedabad Textile Industries Research Association, Polytechnic, P.O. Ahmedabad-380015.

This Notification is effective for the period from 1-4-92 to 31-3-95.

Notes : 1. Condition (i) above will not apply to organisation categorised as associations.

2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1325/F. No. DG/IT(E)/Cal/G-33/35(1)(ii)/90-91]
R. SINGH, Dy. Director of Income Tax (Exemptions)

कलकत्ता, 25 जनवरी, 1995

(आयकर)

का.आ. 857.—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित

प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रायोगिकी भवन" न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिमर्स किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिमाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

सरदार पटेल इंस्टीच्युट आफ इकोनोमिक एंड सोशल रिमर्स, थाततेज रोड,
अहमदाबाद-380054

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-93 से 31-3-96 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी: 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या : 1326(एफ सं.म.नि./आ.क. (छूट)/जि-42/35(1)(iii)]

आर. सिंह, उप निदेशक आयकर (छूट)

Calcutta, the 25th January, 1995

(INCOME-TAX)

S.O. 857.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purpose of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; &
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited income and expenditure account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Sardar Patel Institute of Economic and Social Research,
Thaltej Road, Ahmedabad-380054.

This Notification is effective for the period from 1-4-1993 to 31-3-1996.

Notes : 1. Condition (i) above will not apply to organisation categorised as associations.

2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No 1326/F. No. DG/IT(E)/Cal./G-42/35(1)(iii)]

R SINGH, Dy. Director of Income Tax (Exemptions)

कलकत्ता, 25 जनवरी, 1995

(आयकर)

का.आ.858.—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रायोगिकी भवन" न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार

में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

साइंस एंड टेक्नोलॉजी एन्टरप्रायर्स पार्क,
गुरु नानक इंजीनियरिंग कालेज,
लुधियाना-141006.

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-94 से 31-3-95 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी: 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2 संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनु-मोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर, महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या : 1327(एफ.सं.म.नि./आ.क. (छूट) पि०-5/35 (I)(ii)]

आर. सिंह, उप निदेशक आयकर (छूट)

Calcutta, the 25th January, 1995

(INCOME TAX)

S.O. 858.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purpose of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax (Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited income and expenditure account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Science & Technology Entrepreneur's Park, Guru Nanak Engineering College, Ludhiana-141006.

This Notification is effective for the period from 1-4-94 to 31-3-95.

Notes : 1. Condition (i) above will not apply to organisation categorised as associations.

2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1327/F. No. DG/IT(E)/P./35(1)(ii)/90-91]

R. SINGH, Dy. Director of Income Tax (Exemptions)

कलकत्ता, 25 जनवरी, 1995

(आयकर)

का.आ. 859.—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

(i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।

(ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन," न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और

(iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

इंडियन स्टेडीस्टीकल इंस्टीच्यूट,
203, बी. टी. रोड, कलकत्ता-700035

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-93 से 31-3-96 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी: 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनु-मोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों

में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना ।

[संख्या : 1328/एफ.सं. म.नि./आ.क. (छूट)/डबलू.बि. 40/35(1) (iii)]

आर. सिंह, उप निदेशक आयकर (छूट)

Calcutta, the 25th January, 1995

(INCOME TAX)

S.O. 859.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purpose of clause (iii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities ;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year ; &
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited income and expenditure account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Indian Statistical Institute, 203, B. T. Road, Calcutta-700035.

This Notification is effective for the period from 1-4-93 to 31-3-96.

Notes : 1. Condition (i) above will not apply to organisation categorised as associations.

2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1328 (F. No. DG/IT(E)/Cal/WB-40/35(1)(iii)/90-91]

R. SINGH, Dy. Director of Income Tax (Exemptions)

कलकत्ता, 25 जनवरी, 1995

(आयकर)

का.आ. 860.—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित

प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संघ" संघों के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा ।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, प्रौद्योगिकी भवन" न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में भी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को प्रस्तुत करेगा ।

संगठन का नाम

खसपर,
रिसर्च इंस्टीच्यूट, फोर्ट नं. 1,
अदारह हाऊसिंग सोसाईटी,
क्रोस रोड, नं. 2,
मलाड (प.) बम्बई-400064,

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-92 से 31-3-95 तक की अवधि के लिए प्रभावी है ।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संघों के लिए लागू नहीं होगा ।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है ।

[(संख्या : 1329(एफ.सं.म.नि./आ.क. (छूट)/एम-6/35 (1)(ii)]

आर. सिंह, उप निदेशक आयकर (छूट)

Calcutta, the 25th January, 1995

(Department of Economic Affairs)

(INCOME TAX)

(Banking Division)

New Delhi, the 13th March, 1995

S.O. 860.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purpose of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions:

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; &
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited income and expenditure account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

ASPEE, Research Institute, Plot No. 1, Adarsh Housing Society, Cross Road, No. W. Malad (West), Bombay-400064.

This Notification is effective for the period from 1-4-92 to 31-3-95.

Notes : 1. Condition (i) above will not apply to organisation categorised as associations.

2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1329 (F. No. DG/IT(E)/Cal/M-6/35(I)(ii)/90-91]
R. SINGH, Dy. Director of Income Tax (Exemptions)

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 13 मार्च, 1995

का.आ. 861.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 के खण्ड 5 के उपखण्ड (1), खण्ड 7 और खण्ड 8 के उपखण्ड (1) के साथ पठित खण्ड 3 के उपखण्ड (क) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करने के पश्चात्, एतद्वारा, श्री एस गोपाल कृष्णन को 8 दिसम्बर, 1993 से 31 दिसम्बर, 1995 तक की अवधि के लिए इंडियन बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त करती है।

[स. एफ. 9/35/93-बी.ओ. I]

के. के. मंगल, अवर सचिव

S.O. 861.—In pursuance of sub-clause (n) of clause 3 read with sub-clause (1) of clause 5, clause 7 and sub-clause (1) of clause 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby reappoints Shri M. Gopalakrishnan, as Chairman and Managing Director, Indian Bank, for the period from 8th December, 1993 and upto 31st December, 1995.

[No. 9/35/93-BO. I]

K. K. MANGAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 14 मार्च, 1995

का.आ. 862.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 के खण्ड 5 के उपखण्ड (1), खण्ड 7 और खण्ड 8 के उपखण्ड (1) के साथ पठित खण्ड 3 के उपखण्ड (क) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करने के पश्चात्, एतद्वारा, सिडिकेब बैंक के वर्तमान कार्यपालक निदेशक डा. एन. के. थिंगालिया को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 30 नवम्बर, 1997 तक की अवधि के लिए सिडिकेब बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेश के रूप में नियुक्त करती है।

[स. एफ. 9/42/94-बी.ओ. I]

के. के. मंगल, अवर सचिव

New Delhi, the 14th March, 1995

S.O. 862.—In pursuance of sub-clause (a) of clause 3 read with sub-clause (1) of clause 5, clause 7 and sub-clause (1) of clause 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby appoints Dr. N. K. Thingalaya, presently Executive Director, Syndicate Bank as the Chairman and Managing Director, Syndicate Bank for the period from the date of his taking charge and upto 30th November, 1997.

[F. No. 9/42/94-BO. I]

K. K. MANGAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 14 मार्च, 1995

का.आ. 863.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 के खण्ड 5 के उपखण्ड (1), खण्ड 7 और खण्ड 8 के उपखण्ड (1) के साथ पठित खण्ड 3 के उपखण्ड (क) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करने के पश्चात्, एतद्वारा युनाइटेड बैंक आफ इंडिया के वर्तमान कार्यपालक निदेशक श्री रमेश मिश्रा को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 29 फरवरी, 2000 तक की अवधि के लिए देना बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेश के रूप में नियुक्त करती है।

[स. एफ. 9/40/94-बी.ओ. I]

के. के. मंगल, अवर सचिव

New Delhi, the 14th March, 1995

S.O. 863.—In pursuance of sub-clause (a) of clause 3 read with sub-clause (1) of clause 5, clause 7 and sub-clause (1) of clause 8 of the Nationalised Bank (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby appoints Shri Ramesh Mishra, presently Executive Director, United Bank of India as the Chairman and Managing Director, Dena Bank for the period from the date of his taking charge and upto 29th February, 2000.

[No. F. 9/40/94-BO. I]

K. K. MANGAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 15 मार्च, 1995

का.आ. 864.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1980 के खण्ड 9 के साथ पठित खण्ड 3 के उपखण्ड (ग) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से सलाह करने के पश्चात्, एतद्वारा श्री टी. जगन्नाथ हेगड़े, वर्तमान अध्यक्ष, अखिल भारत विजया बैंक अधिकारी संघ (वरिष्ठ प्रबंधक, विजया बैंक, बैतारयणपुरा शाखा, बैंगलूर के रूप में कार्यरत) को दिनांक 15 मार्च, 1995 से 14 मार्च, 1998 तक के लिए या जब तक वे विजया बैंक के एक अधिकारी के रूप में अपनी सेवा छोड़ नहीं देते हैं, इनमें से जो भी पहले हो, श्री कृष्णराज भट्ट के स्थान पर विजया बैंक के निदेशक मण्डल में निदेशक नियुक्त करती है।

[स. 9/22/94-जीओ-1]

के. के. मंगल, अवर सचिव

New Delhi, the 15th March, 1995

S.O. 864.—In pursuance of sub-clause (c) of clause 3 read with clause 9 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby appoints Shri T. Jagannath Hegde, presently President of the All India Vijaya Bank Officers' Association (working as Senior Manager, Byatarayanapura Branch, Vijaya Bank, Bangalore), vice Shri T. Krishnaraj Bhat, as a Director on the Board of Vijaya Bank with effect from the 15th March, 1995 and upto 14th March, 1998 or until he ceases to be an officer of Vijaya Bank, whichever is earlier.

[F. No. 9/22/94-B.O. I]

K. K. MANGAL, Under Secy.

उद्योग मंत्रालय

(भारी उद्योग विभाग)

नई दिल्ली, 2 मार्च, 1995

का.आ. 865.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में निम्नलिखित कार्यालय को,

जिसके 80 प्रति. कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है :—

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड,
तन्तु प्रकाश परियोजना,
यू.पी.एस.आई.डी.सी.
औद्योगिक क्षेत्र
डाक-खरसरा (करछना),
इलाहाबाद-212301 (उत्तर प्रदेश)

[संख्या ई-11012/(1)/92-हिन्दी]

ओ.पी.शरवर, उप सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Heavy Industry)

New Delhi, the 2nd March, 1995

S.O. 865.—In pursuance of sub-rule (4) of rule 10 of the Official Languages (Use for Official Purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following office whereof 80 per cent staff have acquired the working knowledge of Hindi :—

Hindustan Cables Limited,
Fibre Optics Project,
UPSIDC Industrial Area,
P.O. Kharsara (Karchana),
Allahabad-212301 (U.P.).

[No. E. 11012(1)/92-Hindi]

O. P. SHARVAR, Dy. Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

(डी.ई.एम.-2 अनुभाग)

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1995

का.आ. 866.—मैसर्स इस्सर गुजरात लिमिटेड, चतुर्थ तल, एक्सप्रेस बिल्डिंग, चर्च गेट, बम्बई-400020 को 207,68,00,000/- (100 रु. = 3.315 अमेरिकी डालर) के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के लिये दिनांक 26-6-93 को विशेष अग्रदाय लाइसेंस स. पी/एल/1525371 इस शर्त के साथ प्रदान किया गया था कि लाइसेंस के जारी होने की तारीख से 12 महीने की वैधता के साथ डी.ई.ई. सी बुक सं. 078346 दिनांक 26-6-93 [भाग 1(आयात) भाग 2(निर्यात)] सहित 297,85,29,350 रु. का निर्यात आभार दिया गया था। अब फर्म ने इस आशय के साथ विशेष अग्रदाय लाइसेंस (केवल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतिलिपि) की डुप्लीकेट प्रतिलिपि जारी करने का अनुरोध किया है कि उक्त प्रतिलिपि कहीं गुम/अस्थानास्थ हो गई है। फर्म ने आवश्यक शपथपत्र प्रस्तुत किया है कि उपरोक्त विशेष अग्रदाय लाइसेंस बम्बई सीमांशुक प्राधिकारियों के पास पंजीकृत करवाया गया था तथा 786078155 रु के लिये ही उपयोग किया गया था तथा 1,29,07,21,845-रुपये (3.315 अमेरिकी डालर = 100 रुपये) लाइसेंस/डी ई ई सी बुक का लागत बीमा भाड़ा मूल्य का उपयोग

नहीं किया गया है। गणपयत्र में इस आशय की घोषणा भी शामिल की गई है कि यदि उपरोक्त लाइसेंस (मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति) बाद में कहीं से मिल जाता है तो वह उसे जारीकर्ता प्राधिकारी को लौटा देगा।

2. इस संतुष्टि पर कि मूल विशेष अग्रदाय लाइसेंस (केवल विदेशी मुद्रा विनिमय प्रतिलिपि) गम हो गया है, अधोहस्ताक्षरी निदिष्ट करता है कि आवेदक को विशेष अग्रदाय लाइसेंस (केवल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतिलिपि) को डुप्लीकेट प्रतिलिपि जारी कर दी जाये। विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 9 की उप-धारा (4) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करने हुए अधोहस्ताक्षरी एतद्द्वारा मूल विशेष अग्रदाय लाइसेंस स. पी/एल/1525371 दिनांक 26-6-93 (केवल विदेश मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतिलिपि) को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

[फाइल सं. 01/82/42/12/ए एम-94/डी ई एस-2/3424]

आर.के. सूद, उप महानिदेशक विदेश
व्यापार कृते महानिदेशक विदेश
व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE
(Directorate General of Foreign Trade)
(DES. II Section)
New Delhi, the 24th March, 1995

S.O. 866.—M/s. Essar Gujarat Limited, 4th floor, Express Building, Churngate, Bombay-400020 were granted a Special Imprest Licence No. P/L/1525371 dated 26-6-1993 for CIF value of Rs. 207,68,00,000 (Rs 100=US \$ 3.315) with an Export Obligation of Rs. 297,85,29,350 alongwith DEEC Book No. 0/8346 dated 26-6-1993 [Part I (Import) and II (Export)] with a validity of 12 months from the date of issue of the licence. Now the firm have applied for grant of duplicate of Special Imprest licence (Exchange Control copy only) on the ground that the same has been lost/misplaced. The firm have furnished necessary affidavit according to which the aforesaid Special Imprest Licence was registered with Bombay Customs Authority and was utilised for Rs. 786078155 and the balance CIF value against the licence/DEEC Book is Rs. 129,07,21,845. A declaration has also been incorporated in the affidavit to the effect that if the said licence (Exchange Control Copy) is traced or found later on, it will be returned to the Issuing Authority.

2. On being satisfied that the original Special Imprest Licence (Exchange Control copy only) has been lost, the undersigned directs that duplicate Special Imprest Licence (Exchange Control copy only) should be issued to the applicant. The undersigned also, in exercise of the powers conferred in sub-clause (4) of clause 9 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 hereby cancel the Original Special Imprest Licence No. P/L/1525371 dated 26-6-1993 (Exchange Control copy only).

[F. No. 01/82/42/12/AM. 94/DES. II/3424]

R. K. SOOD, Dy. Director General
of Foreign Trade,
for Director General of Foreign Trade

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

भारतीय मानक ब्यूरो

नई दिल्ली, 7 मार्च, 1995

का. आ. 867.—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड "ख" के अनुसरण से भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि नीचे दिये गये मानक(कों) में संशोधन किया गया है/किये गये हैं:

अनुसूची

क्र.सं.	संशोधित भारतीय मानक की संख्या और वर्ष	संशोधन की संख्या और तिथि	संशोधन लागू होने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आईएस 101 (भाग 8/खंड 5) : 1993	संशोधन सं. 1, अक्तूबर 1994	1994-10-31
2.	आईएस 302-2-3 (1992)	संशोधन सं. 4, अक्तूबर 1994	1994-10-31
3.	आईएस 302-2-7 (1994)	संशोधन सं. 1, अक्तूबर 1994	1994-10-31
4.	आईएस 302-2-201 (1992)	संशोधन सं. 3, अक्तूबर, 1994	1999-10-31
5.	आईएस 398 (भाग 2) : 1976	संशोधन सं. 4, अक्तूबर 1994	1994-10-31
6.	आईएस 781 : 1984	संशोधन सं. 2, नवंबर 1994	1994-11-30
7.	आईएस 1606 : 1979	संशोधन सं. 2, दिसंबर 1994	1994-12-31
8.	आईएस 1715 : 1986	संशोधन सं. 4, अक्तूबर 1994	1994-10-31
9.	आईएस 1875 : 1992	संशोधन सं. 2, नवंबर 1994	1994-11-30

(1)	(2)	(3)	(4)
10.	आईएस 1909:1992	संशोधन सं 1, दिसंबर 1994	1994 12 31
11.	आईएस 2152:1972	संशोधन सं 1, नवंबर 1994	1994 11 30
12.	आईएस 2581:1989	संशोधन सं. 1, अक्टूबर 1994	1994 10 31
13.	आईएस 2653:1993	संशोधन सं. 1, नवंबर 1994	1994 11 30
14.	आईएस 3076:1985	संशोधन सं. 1, दिसंबर 1994	1994 12 31
15.	आईएस 3196 (भाग 2):1992	संशोधन सं 2, दिसंबर 1994	1994 12 31
16.	आईएस 3224:1979	संशोधन सं. 7, दिसंबर 1994	1994 12 31
17.	आईएस 4159:1983	संशोधन सं 6, अक्टूबर 1994	1994 10 31
18.	आईएस:4367:1991	संशोधन सं. 1, नवंबर 1994	1994 11 30
19.	आईएस 4452:1967	संशोधन सं. 1, दिसंबर 1994	1994 12 31
20.	आईएस 4898:1989	संशोधन सं 1, दिसंबर 1994	1994 12 31
21.	आईएस 5150:1969	संशोधन सं. 1, दिसंबर 1994	1994 12 31
22.	आईएस 5613 (भाग 2/खंड 2):1985	संशोधन सं. 1, अक्टूबर 1994	1994 10 31
23.	आईएस 6911:1992	संशोधन सं. 1, अक्टूबर 1994	1994 10 31
24.	आईएस 7312:1993	संशोधन सं 1, दिसंबर 1994	1994 12 31
25.	आईएस 9301:1990	संशोधन सं. 3, नवंबर 1994	1994 11 30
26.	आईएस 10049:1981	संशोधन सं. 1, दिसंबर 1994	1994 12 31
27.	आईएस 10322 (भाग 5/खंड 2):1985	संशोधन सं. 1, जनवरी 1995	1995 01 31
28.	आईएस 10359:1982	संशोधन सं. 1, दिसंबर 1994	1994 12 31
29.	आईएस 10360:1982	संशोधन सं. 1, नवंबर 1994	1994 11 30
30.	आईएस 11197:1985	संशोधन सं. 2, नवंबर 199	1994 11 30
31.	आईएस 11601(भाग 1):1986	संशोधन सं. 1, सितम्बर 1994	1994 09 30
32.	आईएस 11646 (भाग 2):1986	संशोधन सं. 1, अक्टूबर 1994	1994 10 31
33.	आईएस 11708:1986	संशोधन सं. 2, सितम्बर 1994	1994 09 30
34.	आईएस 12039:1986	संशोधन सं. 1, जनवरी 1995	1995 01 31
35.	आईएस 13019:1991	संशोधन सं. 1, फरवरी 1995	1995 02 28
36.	आईएस 13056:1991	संशोधन सं 3, नवंबर 1994	1994 11 30
37.	आईएस 13213:1991	संशोधन सं. 1, दिसंबर 1994	1994 12 31
38.	आईएस 13238:1991	संशोधन सं. 1, दिसंबर 1994	1994 12 31
39.	आईएस 13239:1991	संशोधन सं 1, अक्टूबर 1994	1994 10 31
40.	आईएस 13287:1992	संशोधन सं 2, नवंबर 1994	1994 11 30
41.	आईएस 13334 (भाग 1):1992	संशोधन सं. 2, नवंबर 1994	1994 11 30
42.	आईएस 13387:1992	संशोधन सं 1, नवंबर 1994	1994 11 30
43.	आईएस 13663:1993	संशोधन सं. 1, नवंबर 1994	1994 11 30
44.	आईएस 13644:1992	संशोधन सं. 1, नवंबर 1994	1994 11 30

(1)	(2)	(3)	(4)
45	आईएस 13800 (भाग 1) : 1993	संशोधन सं. 1, नवम्बर 1994	1994 11 30
46.	आईएस 13895 : 1994	संशोधन सं. 1, नवम्बर 1994	1994 11 30
47.	आईएस 14001 : 1994	संशोधन सं. 1, दिसम्बर 1994	1994 12 31
48.	आईएस 14002 : 1994	संशोधन सं. 1, दिसम्बर 1994	1994 12 31
49.	आईएस 14003 : 1994	संशोधन सं. 1, दिसम्बर 1994	1994 12 31

इन संशोधनों की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 और क्षेत्रीय कार्यालयों, बम्बई, कलकत्ता, चंडीगढ़ तथा मद्रास और शाखा कार्यालयों, अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, हैदराबाद जयपुर, कानपुर, पटना और त्रिवेंद्रम, गाजियाबाद तथा फरीदाबाद में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

[सं. केप्रवि/13: 5]

पी. एस. दास, अपर महानिदेशक

MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS & PUBLIC DISTRIBUTION
BUREAU OF INDIAN STANDARDS

New Delhi, the 7th March, 1995

S.O. 867. —In pursuance of clause (b) of Sub-rule (1) or Rule 7 of Department of Indian Standards Rules 1987, the Bureau of Indian Standards, hereby notifies that amendment(s) to the Indian Standard(s) given in the schedule hereto annexed has/have been issued.

THE SCHEDULE

Sl. No. and year of the Indian No. Standard amended	No. and date of the amendment	Date from which the amendment shall have effect
(1)	(2)	(3)
1. IS 101 (Part 8 Sec 5): 1993	Amendment No. 1, October 1994	1994-10-31
2. IS 302-2-3 (1992)	Amendment No. 4, October 1994	1994-10-31
3. IS 302-2-7 (1994)	Amendment No. 1, October 1994	1994-10-31
4. IS 302-2-201(1992)	Amendment No. 3, October 1994	1994-10-31
5. IS 398 (Part 2): 1976	Amendment No. 4 October 1994	1994-10-31
6. IS 781 : 1984	Amendment No. 2, November 1994	1994-11-30
7. IS 1606 : 1979	Amendment No. 2, December 1994	1994-12-31
8. IS 1715 : 1986	Amendment No. 4, October 1994	1994-10-31
9. IS 1875 : 1992	Amendment No. 2, November 1994	1994-11-30
10. IS 1909 1992	Amendment No. 1, December 1994	1994-12-31

(1)	(2)	(3)	(4)
11. IS 2152 : 1972	Amendment No. 1, November 1994	1994-11-30	
12. IS 2581 : 1989	Amendment No. 1, October 1994	1994-10-31	
13. IS 2653 : 1993	Amendment No. 1, November 1994	1994-11-30	
14. IS 3076 : 1985	Amendment No. 1, December 1994	1994-12-31	
15. IS 3196 (Part 2) : 1992	Amendment No. 2, December 1994	1994-12-31	
16. IS 3224 : 1979	Amendment No. 7, December 1994	1994-12-31	
17. IS 4159 - 1983	Amendment No. 6, October 1994	1994-10-31	
18. IS 4367 : 1991	Amendment No. 1, November 1994	1994-11-30	
19. IS 4452 : 1967	Amendment No. 1, December 1994	1994-12-31	
20. IS 4898 : 1989	Amendment No. 1, December 1994	1994-12-31	
21. IS 5150 : 1969	Amendment No. 1, December 1994	1994-12-31	
22. IS 5613 (Part 2/Sec 2) : 1985	Amendment No. 1, October 1994	1994-10-31	
23. IS 6911 : 1992	Amendment No. 1, October 1994	1994-10-31	
24. IS 7312 : 1993	Amendment No. 1, December 1994	1994-12-31	
25. IS 9301 : 1990	Amendment No. 3, November 1994	1994-11-30	
26. IS 10049 : 1981	Amendment No. 1, December 1994	1994-12-31	
27. IS 10322 (Part 5/Sec 2) : 1985	Amendment No. 1, January 1995	1995-01-31	
28. IS 10359 : 1982	Amendment No. 1, December 1994	1994-12-31	
29. IS 10360 : 1982	Amendment No. 1, November 1994	1994-11-30	
30. IS 11197 : 1985	Amendment No. 2, November 1994	1994-11-30	
31. IS 11601 (Part 1) : 1986	Amendment No. 1, September 1994	1994-09-30	
32. IS 11646 (Part 2) : 1986	Amendment No. 1, October 1994	1994-10-31	
33. IS 11708 : 1986	Amendment No. 2, September 1994	1994-09-30	
34. IS 12039 : 1986	Amendment No. 1, January 1995	1995-01-31	
35. IS 13019 : 1991	Amendment No. 1, February 1995	1995-02-28	

(1)	(2)	(3)	(4)
36. IS 13056 : 1991	Amendment No. 3, November 1994	1994-11-30	
37. IS 13213 : 1991	Amendment No. 1, December 1994	1994-12-31	
38. IS 13238 : 1991	Amendment No. 1, December 1994	1994-12-31	
39. IS 13239 : 1991	Amendment No. 1, October 1994	1994-10-31	
40. IS 13287 : 1992	Amendment No. 2, November 1994	1994-11-30	
41. IS 13334 (Part 1) : 1992	Amendment No. 2, November 1994	1994-11-30	
42. IS 13387 : 1992	Amendment No. 1, November 1994	1994-11-30	
43. IS 13663 : 1993	Amendment No. 1, November 1994	1994-11-30	
44. IS 13644 : 1992	Amendment No. 1, November 1994	1994-11-30	
45. IS 13809 (Part 1) : 1993	Amendment No. 1, November 1994	1994-11-30	
46. IS 13895 : 1994	Amendment No. 1, November 1994	1994-11-30	
47. IS 14001 : 1994	Amendment No. 1, December 1994	1994-12-31	
48. IS 14002 : 1994	Amendment No. 1, December 1994	1994-12-31	
49. IS 14003 : 1994	Amendment No. 1, December 1994	1994-12-31	

Copies of these Amendments are available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 and Regional Offices : Bombay, Calcutta, Chandigarh and Madras and also Branch Offices : Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Patna and Trivandrum.

[No. CMD/13 · 5]

P.S. DASS, Addl. Director General

भारतीय मानक ब्यूरो

नई दिल्ली, 14 मार्च, 1995

का.आ. 868 : - भारतीय मानक ब्यूरो (प्रमाणन) विनियम, 1988 के विनियम 5 के उपविनियम (6) के अनुसरण में एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि जिन प्रमाणन मुहर साइसेंसों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, उनको अधिध समान हो गई है :

अनुसूची

क्रम संख्या	लाइसेंस सं. (सांख्यिक/एल)	लाइसेंसधारी का नाम	आई एस संख्या	अधिध समाप्ति की तिथि	समाप्ति का कारण
1	2	3	4	5	6
1.	0522939	प्रताप स्टील रोलिंग मिल्स लि., इंडस्ट्रियल एरिया, पाटनचेर 502320	आईएस 6914:1978	93-05-16	सुहरांकन शुल्क भुगतान नहीं किया।
2.	0523032	प्रताप स्टील रोलिंग मिल्स लि., इंडस्ट्रियल एरिया, पाटनचेर 502320	आईएस 6915:1978	93-06-01	सुहरांकन शुल्क का भुगतान नहीं किया।

(1)	(2')	(3)	(4)	(5)	(6)
3. 0534441	ए.के.सी. स्टील इंडस्ट्रियल लि., मल्कापुरम, विशाखापटनम 530011	आईएम 6915:1978	93-07-16	लाइसेंसधारी अनइच्छुक	
4. 0535039	ए.के.सी. स्टील इंडस्ट्रियल लि., मल्कापुराम् विशाखापटनम 530011	आईएस 6914:1970	93-07-16	लाइसेंसधारी अनइच्छुक	
5. 0536142	यू.के.पेंट्स इंडस्ट्रीज, 19, डीडीए कामर्शियल कॉम्प्लेक्स, कैलाश कालोनी एक्सटेंशन, जमरुदपुर, नई दिल्ली-110048	आईएस 419:1957	93-07-16	लाइसेंसधारी अनइच्छुक	
6. 0600933	एस.ए. निर्दिष्ट मिल्स, 88 (एफ) 17, कामराज रोड, तिरुपुरा 638604	आई एस 4964:1980	93-04-01	सूहरांकन शुल्क नहीं दिया	
7. 0619550	राठी एल्वाय एण्ड स्टील लि., 204, मल्स्य इंड. एरिया, अल्वर 301030	आई एस 6914:1978	93-07-01	लाइसेंसधारी अनइच्छुक	
8. 0619651	राठी एल्वाय एण्ड स्टील लि., 204 मल्स्य इंड. एरिया, अल्वर 301030	आई एस 6915:1978	93-08-16	लाइसेंसधारी अनइच्छुक	
9. 0622842	ओरिजनल निर्दिष्ट कं., रामनगर 111, स्ट्रीट, तिरुपुरा 677602	आईएस 4964:1980	93-07-16	आवेदन नहीं किया	
10. 0626749	श्रीराम टाइल्स, प्लॉट नं. 10 इंड. एस्टेट श्रीराम पुर, रेलवे स्टेशन (मी आर) जिला ग्रहमबाबाद 413709	आईएस:1237:1980	93-09-16	लाइसेंस प्रचालित नहीं	
11. 0643950	प्रालिप्त इजी. कं., दिव्य इंडस्ट्रियल कॉम्पाउंड, अजी इंडस्ट्रियल एस्टेट, 80 फीट रोड, राजकोट 360003	आईएस 10001:1981	93-09-16	सूहरांकन शुल्क की अदायगी नहीं की।	
12. 0647353	हाफी एलइकतारा प्रा.लि., पोस्ट बाक्स नं. 132, सम्मुख ठाणे गौदबंदर रोड, कबेसार, बागवेलू ठाणे 400601	आईएस 4894:1987	93-11-01	फर्म की रुचि नहीं	
13. 0757259	मिनरवा इंडस्ट्रीज 6/5 गली बड़ा भाई बेलनगंज, भागरा 282004	आईएस 10001:1981	93-07-01	प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ	
14. 0828963	न्यूकेम प्लास्टिक्स लि. 20/6 मधुरा रोड, फरीदाबाद 212006	आई एस 848:1974	93-08-16	फर्म की रुचि नहीं	
15. 0979378	सागां पेट्रोकेम नं. 23, बी.सी.इंड. एस्टेट, 7 वां मील ओल्ड मद्रास रोड, बंगलौर 560016	आईएस 398 (भाग 1): 1976	93-07-16	लाइसेंसधारी अनइच्छुक	
16. 1053632	इलेक्ट्रिकल मैनुफे. कं. लि., ई एम सी गार्डन, 136, जैसोर रोड, कलकत्ता 700055	आईएस 398 (भाग 1) 1976	93-06-01	आवेदन प्राप्त नहीं हुआ	
17. 1068140	खेतान इलेक्ट्रिकल लि., प्लॉट नं. 14, सैक्टर, 6, रफरीबाबाद 121006	आईएस 2312:1967	93-06-01	प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18. 1070733	यूनियन ट्रेक्टर वर्कशॉप 8-बी, फेस 3, मायापुरी इंड. एरिया, नई दिल्ली-110064	आईएस 9020:1979	93-08-16	लाइसेंसधारी अनइच्छुक	
19. 1080736	मद्रास इलेक्ट्रिकल कंक्टर्स प्रा. लि., 37, आरकट रोड, पोस्ट बॉक्स नं. 2256 मद्रास 600026	आईएस 398 (भाग 1) 1976	93-04-01	लाइसेंसधारी अनइच्छुक	
20. 1100312	एम पी स्टील वल फैक्टरी प्रा. लि. डॉ-850 न्यू फेबस कालोनी, नई दिल्ली 110014	आईएस 398 (भाग 1) 1976	93-08-16	प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ	
21. 1107427	अशोक बूट फैक्टरी, 17/300, सबर भाट्टी, आगरा 282003	आईएस 1989 (भाग 2) 1986	93-08-16	प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ	
22. 1130422	प्रताप स्टील रोलिंग मिल्स प्रा. लि., इंडस्ट्रियल एरिया, पाटनचेरु 502320	आईएस 8051:1976	92-09-16	आवेदन नहीं किया	
23. 1185548	इंसेक्टी साइड्स एण्ड एलाइड केमिकल्स, 87/16, आरकट रोड, मद्रास 600026	आईएस 2567:1978	93-05-01	आवेदन प्राप्त नहीं हुआ	
24. 1194551	जे. के. बी. एम. लि., 133-134 जी आई बी सी इंडस्ट्रियल एरिया, अंकलेश्वर, जिला बरोच 393002	आईएस 8445:1977	93-10-01	लाइसेंसधारी अनइच्छुक	
25. 1209233	एसोसिएटेड सीमेंट कं. लि., (फेसर इन्वेस्टमेंट लि.), शाहबाद सीमेंट वर्क्स, शाहबाद, जिला गुलबर्गा, कर्नाटक 585229	आईएस 269:1989	93-07-01	मुहरांकन शुल्क का भुगतान नहीं किया	
26. 1209334	एसोसिएटेड सीमेंट कं. लि., (फेसर इन्वेस्टमेंट लि.), शाहबाद सीमेंट वर्क्स, शाहबाद, जिला गुलबर्गा, कर्नाटक 585229	आईएस 1489:1979	93-07-01	लाइसेंसधारी अनइच्छुक	
27. 1209536	लोकापुर सीमेंट प्रा. लि., लोकापुर 587122, जिला बीजापुर, कर्नाटक राज्य	आईएस 269:1989	93-07-01	अनइच्छुक	
28. 1222326	गोदरेज सोप्स लि., 1-बी, इंडस्ट्रियल एस्टेट, अम्मात्तूर, मद्रास 600098	आईएस 2052:1979	93-07-16	आवेदन प्राप्त नहीं हुआ	
29. 1309439	पी.जी. कंक्टर्स पिपलीय कालान 306307 जिला पाली, राजस्थान	आईएस 398 (भाग 1) 1976	93-05-16	लाइसेंसधारी अनइच्छुक	
30. 1310424	माकून पेंट्स वर्क्स, 242/ए, मानिक टोला मेन रोड, कलकत्ता 700054	आईएस 133:1975	93-05-01	आवेदन प्राप्त नहीं हुआ	
31. 1318344	श्याम इंजी. वर्क्स, 218, जयंतीपुर सुलेम सारी, हलाहाबाद	आईएस 458:1988	93-07-01	फर्म का रुचि नहीं	
32. 1324638	ईस्ट इंडिया कार्मेशियल कॉ. जूट लि., सेसी, श्री कृष्ण जूट मिल्स, एलुर-534002	आईएस 2580:1982	93-08-01	लाइसेंसधारी अनइच्छुक	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33. 1330894	ग्राम्हा सीमेंट कं. लि., दुर्गा सीमेंट वर्क्स, दुर्गा पुरम, वाचीपल्ली पोस्ट 522414 गूडूर जिला	आईएस 1489:1976	93-10-01	लाइसेंसधारी अनइच्छुक	
34. 1367049	अनन्तर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि., कैलाश रोड, भोगराबाड़ी, बलसाङ 396001	आईएस 1293:1988	93-02-01	फर्म अनइच्छुक	
35. 1411531	इलेक्ट्रिकल्स मै. फौ. कं. लि., ई एम सी गार्डन, 136, जैसोर रोड, कलकत्ता 700055	आईएम 398 (भाग 4): 1976	93-06-01	आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ	
36. 1431234	सागर सीमेंट लि., मातमपल्ली 508204, हजूर नगर तालुक, नलगोंडा जिला	आईएस 269:1989	93-07-01	लाइसेंसधारी अनइच्छुक	
37. 1436345	इम्स एण्ड ब्रेल्स (मद्रास) प्रा. लि., 5 ए, विद्यानाथ स्ट्रीट, टोंडीपारपेट, मद्रास 600081	आईएस 3575:1977	93-07-16	रूचि नहीं	
38. 1440554	जीपिका केमिकल्स (इंडिया) प्रा. लि., जीपिका हाउस, जीपिका स्ट्रीट दोलतगंज, ग्वालियर,	आईएम 427:1965	93-09-01	लाइसेंसधारी अनइच्छुक	
39. 1419655	जीपिका केमिकल्स (इंडिया) प्रा. लि., जीपिका हाउस, जीपिका स्ट्रीट, दोलतगंज, ग्वालियर,	आईएस 428:1969	93-09-01	लाइसेंसधारी अनइच्छुक	
40. 1455147	आसवाल धायल एण्ड बनस्पति इंडस्ट्रीज, 107 कोचरानी बासन रोड, मद्रास 600021	आईएस 10633:1986	93-10-01	लाइसेंसधारी अनइच्छुक	
41. 1555353	एचू कनटिक टिन फैक्टरी, बोर्ड नं. सी-33, इंड. एस्टेट, गोकुल रोड, दुधसी-30	आईएम 10325:1989	93-04-16	लाइसेंसधारी अनइच्छुक	
42. 1562350	अशोक मेटल बाक्स इंडस्ट्रीज, एफ-778, बोर्ड नं. 13, बी. के.आई. एरिया, जयपुर 302013	आईएस 10325:1989	93-05-16	लाइसेंसधारी अनइच्छुक	
43. 1567865	हासोमारा इंडस्ट्रीज लि., पी.ओ. अय्यपुर, जिला 24 परगना	आईएस 2580:1982	93-06-01	आवेदन प्राप्त नहीं हुआ ।	
44. 1573052	ब. बी. इंटरप्राइसेस, 302/2/एच/8, आचार्य प्रफूल चन्द्र रोड, कलकत्ता 700007	आईएस 2573:1986	93-07-01	आवेदन प्राप्त नहीं हुआ ।	
45. 1576967	गणेश प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, कल्याण रमन स्ट्रीट, अगन्नाथपुरम, आचार्यमंगलम, तिरुचिरपल्ली	आईएस 10840:1986	93-06-16	रूचि नहीं	
46. 1588570	जिबुरा जूट मिल्स लि., हेपमाई ,पोस्ट अरुघति नगर, अमरतला 799003, त्रिपुरा	आईएस 3984:1967	93-08-01	आवेदन प्राप्त नहीं हुआ	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
47. 1596872	राजदूत पेंट्स प्रा. लि., ए-33, इंड. एरिया, गाजियाबाद-बुलंदशहर रोड, सिकन्दराबाद 203205	आईएस 9862:1981	93-09-01	लाइसेंसधारी को रुचि नहीं	
48. 1628051	उषय इलेक्ट्रिकल्स, प्लॉट नं. 448, फेज 2, समीप बिजोल गाँव, जीआईडीसी एस्टेट, वातवा ग्रहमवाबाद	आईएस 9079:1989	92-12-01	आवेदन प्राप्त नहीं हुआ	
49. 1639965	कोयम्बतूर रोलिंग मिल्स, नरसिम्हा किमफ लायस, कोयम्बतूर 641031	आईएस 226:1975	93-01-16	लाइसेंसधारी अनइच्छुक	
50. 1697676	न्यू स्टार इंड. यूनिट नं. 22, ग्राउंड फ्लोर, भगरोड इंड एस्टेट, एस.बी. रोड, दहिसार (ई), नम्बई	आई एस : 8808-1986	93-06-16	आवेदन प्राप्त नहीं हुआ	
51. 1771359	ग्रापटीमा सेम्पस प्रा. लि., 12वां किमी बूसूर रोड, बंगलौर 560068	आई एस 418:1978	91-12-16	—	
52. 1829162	खेतान इलेक्ट्रिकल्स लि., प्लॉट नं. 14, सेक्टर 6, फरीदाबाद 121006	आई एस 4283:1981	93-06-01	आवेदन प्राप्त नहीं हुआ	
53. 1836159	मास्टर इंजीनियरिंग कं., लीलजपुर रोड, बोलका 387810 जिला ग्रहमवाबाद	आई एस 8034:1989	93-06-16	प्रशासन का बदलना	
54. 1838567	रेवती इंटरप्राइसेस, देव, प्लॉट नं. 30 (एम पी) इंड. एस्टेट, गुंडी, मद्रास 600032	आई एस 398 (भाग 2): 1976	93-06-01	सूचकांक शुल्क का भुगतान नहीं किया	
55. 1838971	प्रभात स्पन पाइप्स, सेमरा मगहर, खलीलाबाद, बस्ती	आई एस 458:1988	93-07-01	आवेदन प्राप्त नहीं हुआ	
56. 1882673	बैकटेक्स्टराय कंडक्टर प्रा. लि., एफ-20, सिपकोट इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, गुवालीपूंजी 601 201	आई एस 3601:1984	93-10-01	रुचि नहीं	
57. 1884178	जे. के. बी. एम. लि., 133-134 जी आई बी सी इंडस्ट्रियल एस्टेट, अंकलेश्वर, जिला भड़ोच 393 002	आई एस 4766:1982	93-10-01	कर्म की रुचि नहीं है	
58. 1894877	संकला अपलायेंस प्रा. लि., प्लॉट नं. 64, सेक्टर 24, फरीदाबाद 121055	आई एस 11480:1985	93-09-01	कर्म की रुचि नहीं है	
59. 1899789	बी. एम. इंडस्ट्रीज	आई एस 10805:1986	92-11-16	लाइसेंसधारी अनइच्छुक	
60. 1968883	फिंग कारपोरेशन आफ राजस्थान एच-686, बासनी 2 फेज, जोधपुर 340001	आई एस 1475:1978	93-05-01	लाइसेंसधारी अनइच्छुक	
61. 1982473	भारती रसायनिक उद्योग, सबर बाजार, धमतारी	आई एस 8960:1978	93-06-01	लाइसेंसधारी अनइच्छुक	
62. 1988697	अलायंस मिल्स (लेसीस) प्रा. लि., 18 नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता 700001	आई एस 12154:1987	93-06-16	आवेदन प्राप्त नहीं हुआ	
63. 1988788	अलायंस मिल्स (लेसीस) प्रा. लि., 18 नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता 700001	आई एस 7407 (भाग 2): 1980	93-06-16	आवेदन प्राप्त नहीं हुआ	

1	2	3	4	5	6
64. 1988899	प्रलायंस मिल्स (लेसीस) प्रा. लि., 18 नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता 700 001	आई एस 7407 (भाग 3): 1980	93-06-16	आवेदन प्राप्त नहीं हुआ	
65. 1999490	बुर्गा भगवती एग्रीकल्चर 11/47 डी, रामबाग, आगरा 282 006	आई एस 6595: 1980	93-07-16	कार्य संतोषजनक नहीं	
66. 2005929	फोर्ट विलियम कं. लि., 10 ब्लाई रौ, तीसरी मंजिल, कलकत्ता 700 001	आई एस 7407 (भाग 3) 1980	93-08-01	आवेदन प्राप्त नहीं हुआ	
67. 2008228	सनरे एग्रीकैम इंडस्ट्रीज, आगरा मथुरा रोड, कलकत्ता, आगरा	आई एस 562: 1978	93-09-16	लाइसेंसधारी अनहस्तुक	
68. 2014627	रिलायंस जूट एंड इंडस्ट्रीज लि., 9 आबोर्न रोड, कलकत्ता 700 001	आई एस 7407 (भाग 2)	93-08-16	आवेदन प्राप्त नहीं हुआ	
69. 2021220	केपिटल सेटर्स प्रा. लि., प्लॉट नं. 17, ब्लाक ए, सेक्टर 9, नोएडा 201 301	आई एस 722 (भाग 3): 1986	93-09-01	लाइसेंसधारी अनहस्तुक	
70. 2027030	पार्लेयटस एक्स्ट्रूशन प्रा. लि., सी-57, एम आई डी सी इंड एरिया, मीरजोल, रतनगिरि 415 639	आई एस 4985: 1988	93-09-16	सुश्रूतकन शुल्क का भुगतान नहीं किया	
71. 2067547	जे. के. जूट मिल कं. लि., काल्पी रोड, फजल गंज, कानपुर	आई एस 7407 (भाग 3)	93-04-01	कार्य संतोषजनक नहीं	
72. 2099762	वीना इंडरप्राइसेस प्लॉट नं. 61, फेज 3, आटोनगर, बिजयबाड़ा 520 007	आई एस 7466: 1974	94-04-01	लाइसेंसधारी अनहस्तुक	
73. 2113326	अभियेक स्टील्स लि., गुंडला पोखम पलायम बाया हकीम पेट, मेडवल मंडल, रंगारेड्डी जिला 500 014	आई एस 226: 1975	93-05-16	भारतीय मानक बापस	
74. 2113831	अभियेक स्टील्स लि., गुंडला पोखम लाम, बाया हकीम पेट, मेडवल मंडल, रंगारेड्डी जिला 500 014	आई एस 1977: 1975	93-05-16	आवेदन प्राप्त नहीं हुआ	
75. 2126032	मैनुअल फीडस कारपोरेशन, चेरुपुकाळ पो. ओ., पलई कोट्टायाम (केरला) 636584	आई एस 1374: 1979	93-06-16	रुचि नहीं	
76. 2134940	एग्री केमिकल इंडस्ट्री, शेड नं. 213 एस आई डी सी ओ इंडस्ट्रियल एस्टेट, अम्बापुर, मद्रास 600 098	आई एस 9356: 1980	93-07-16	आवेदन प्राप्त नहीं हुआ	
77. 2143698	न्यूकेम प्लास्टिक्स लि., 20/6 मधुरा रोड, फरीदाबाद 121 006	आई एस 9103: 1979	93-08-16	कर्म की रुचि नहीं	
78. 2153742	शिष केमिकल्स, 356 कृष्ण कमल निवास, मारवाड़ी गली, पोस्ट तालुका सेवा संघ, जिला अहमदाबाद 414 502	आई एस 1065: 1989	93-10-01	कर्म की रुचि नहीं	
79. 2176249	विणाल इंजी. वर्क्स, जं. सी. बैगाड कॉम्प्लेक्स, समीप कमला विद्यालय, गोरो मिनेमा, सी. टी. एम. रोड, ओषम अहमदाबाद 382 415	आई एस 9079: 1989	93-01-01	आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ	

1	2	3	4	5	6
80. 2282233	जैन इंड. कारपोरेशन खमरा नं. 386, नांगल रोड, ओसवाड़ा, जयपुर 302 012	आई एस 10325 : 1989	93-04-01	लाइसेंसधारी की रशि नहीं	
81. 2287249	हिल्सगार्स लि., घाटेंड बैंक बिल्डिंग, कलकत्ता-70001	आई एस 10647 : 1983	93-07-01	आवेदन प्राप्त नहीं हुआ	
82. 2265248	सिद्धार्थ उद्योग, ग्राम पारसीय, पो.ओ. : जिला सिद्धार्थ नगर 272 205	आई एस 458 : 1988	93-08-01	आवेदन प्राप्त नहीं हुआ	
83. 2267050	एस.बी. इंडस्ट्रियल एलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि., बी-52/53 जी आई डी सी इलेक्ट्रॉनिक्स एस्टेट, सेक्टर 25, गांधीनगर, (गुजरात) 382023	आई एस : 3854 : 1988	93-09-01	आवेदन प्राप्त नहीं हुआ	
84. 2270645	भारवा इस्पात लि., कम्पार्ड रोड, नागपुर 440 026	आई एस 2879 : 1975	93-08-16	लाइसेंसधारी अनइच्छुक	
85. 2272346	जम्मू फूड्स (प्रा.) लि., 185, ए/डी गांधी नगर, जम्मू (जम्मू एण्ड कश्मीर)	आई एस 1165 : 1986	93-08-16	आवेदन प्राप्त नहीं हुआ	
86. 2275251	अनुपम इंडस्ट्रीज, खमरा नं. 894, अलीपुर ग्राही, दिल्ली-110 036	आई एस 2980 : 1986	93-08-16	लाइसेंसधारी अनइच्छुक	
87. 2277255	पीतमपुर कंजिमा प्रा. लि., 1230 मुदामा नगर, इंदौर 452 009	आई एस 398 (भाग 1) : 1976	93-09-01	लाइसेंसधारी अनइच्छुक	
88. 2277356	पीतमपुर कंजिमा प्रा. लि., 1230 मुदामा नगर, इंदौर- 452 009	आई एस 398 (भाग 2)	93-09-01	लाइसेंसधारी अनइच्छुक	
89. 2279158	एम आई सी ओ फार्म केमिकल लि., नं. 165 थाम्बू बिट्छी स्ट्रीट, खोटस कोट, मद्रास-1	आई एस 3902 : 1975	93-09-16	इच्छुक नहीं	
90. 2287359	वायरलौरी कं. लि., 21, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता 700 001	6312 : 1980	93-10-01	आवेदन प्राप्त नहीं हुआ	
91. 2292958	सुभाष सरत स्टील रोलिंग मिल्स, कोलशेस रोड, पोस्ट सनवोज बांग, थाणे 400 607	आई एस 2062 : 1984	93-10-16	लाइसेंस का त्याग	
92. 2297160	पातिरा फूड प्राइवेट प्रा. लि., 3, केवडावड़ी, राजकोट 360 002	आई एस 2639 : 1984	93-11-01	आवेदन प्राप्त नहीं हुआ	
93. 2301327	प्रताप स्टील रोलिंग मिल्स लि., इंडस्ट्रियल एरिया, पाटनबेक 502 320	आई एस 3431 : 1982	92-09-16	आवेदन प्राप्त नहीं हुआ	
94. 2365	एयर फोम इंडस्ट्रीज प्रा. लि., नं. 28 केमिकल सेक्टर इंडस्ट्रियल एस्टेट, मद्रास 600 058	आई एस 4989 (भाग 1) : 1985	93-05-16	लाइसेंसधारी अनइच्छुक	
95. 2367549	राजतूत पेंट्स प्रा. लि., ए-38 इंड एरिया, शाजियाबाव बलन्दशहर रोड, सिकन्दराबाद 203 205	आई एस 133 : 1975	93-09-01	लाइसेंसधारी अनइच्छुक	
96. 2375457	भार. पी. इंडस्ट्रीज, बागल रोड, मेरठ (उ.प्र.) 250 002	आई एस 2980 : 1986	94-06-16	लाइसेंसधारी अनइच्छुक	

1	2	3	4	5	6
97 2395564	विधि इंटरप्राइजेज, 2553, सतधरा, धर्मपुरा, (वरिवा चांदनी चौक के अन्दर) दिल्ली-110 006	आई एस 12786	1989	93-09-01	लाइसेंसधारी अनइच्छुक
98 2403032	विद्युत इंजिनियर्स, 207, वित्तिय हिल्स इंडस्ट्रियल एस्टेट, देवसरुवार उद्यो, चिच बंदर रोड, मुंबई (प.) पिनकोड 400 064	आई एस 694	1977	93-09-16	आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ
99 7001542	कुलकर्णी इंजीनियरिंग क , प्लॉट ए/100, एम आई डी सी, फेज I, डीएमवली, जिला ठाणे 421 208	आई एस 2148	1981	94-10-16	लाइसेंसधारी अनइच्छुक

[सं. के प्रा वि. 13:14]
पी.एस.वास, अपर महानिदेशक

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

New Delhi, the 14th March, 1995

S.O. 868.—In Pursuance of Sub-Regulation (6) of Regulation 5 of the Bureau of Indian Standards (Certification) Regulations, 1983, it is, hereby notified that the Certification Marks Licences, details of which are mentioned in the following Schedule, have expired:

SCHEDULE

Sl. Licence No. No.	Name of the licensee	Number of the relevant Indian Standard	Date of expiry	Reason for expiry
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. 0522939	Partap Steel Rolling Mills Ltd Industrial Area Patancheru 502320	IS 6914 : 1978	93-05-16	Marking fees not paid
2. 0523032	Parap Steel Rolling Mills Ltd. Industrial Area Patancheru 502 320	IS 6915 : 1978	93-06-01	Marking fees not paid
3. 0534441	AKC Steel Industrial Ltd. Malkapuram Visakhapatnam 530011	IS 6915 : 1979	93-07-16	Party not interested
4. 0535039	AKC Steel Industrial Ltd. Malkapuram Visakhapatnam 530011	IS 6914 : 1978	93-07-16	Party not interested
5. 0536142	U.K. Paints Industries 19, DDA, Commercial Complex Kailash Colony Extension Zamrudpur New Delhi-110048	IS 419 : 1967	93-07-16	Party not interested
6. 0600933	M.A. Knitting Mills 88 (F) 17, Kamraj Road Tirupur 638604	IS 4964 : 1980	93-04-01	Marking fees not paid
7. 0619550	Rathi Alloys & Steel Ltd. 204, Matsya Indl. Area Alwar 301030	IS 6914 : 1978	93-07-01	Party not interested
8. 0619651	Rathi Alloys & Steel Ltd. 204, Matsya Indl. Area Alwar 301030	IS 6915 : 1978	93-08-16	Party not interested

1	2	3	4	5
9 0622842	Original Knitting Co. Raman Nagar III Street Tirupur 638602	IS 4964 : 1980	93-07-16	Not applied
10 0626749	Shriram Tiles Plot no. 10 Indl. Estate Shreerampur Rly Stn. (CR) Distt. Ahmednagar 413709	IS 1237 : 1980	93-09-16	Not operated licence
11 0643850	Salient Engg. Co. Divya Industries Compound Aji Industrial Estate 80, Feet Road Rajkot 360003	IS 10001 : 1981	93-09-16	Marking fee not paid
12 0647353	Hafi Elektra Pvt. Ltd. Post Box No. 132 Off. Thane Ghoubunder Road Kavesar Waghecal Thane 400601	IS 4894 : 1987	93-11-01	Firm not interested
13 0757259	Minerva Industries 6/5, I Gali Bara Bhai, Belanganj Agra 282004	IS 10001 : 1981	93-07-01	Application not received
14 0828963	Nuchen Plastics Ltd. 20/6, Mathura Road Faridabad 121006	IS 848 : 1974	93-08-16	Firm not interested
15 0979378	Shango Petrochem No. 23, B.C. Indl. Estate 6th Mile Old Madras Road Bangalore 560016	IS 898 (Part 1): 1976	93-07-16	Party not interested
16 1053632	Electrical Mfg. Co. Ltd. EMC Garden 136, Jessore Road Calcutta 700055	IS 398 (Part 1) : 1976	93-06-01	Application not received
17 1068140	Khattan Electricals Ltd. Plot No. 14, Sector 6 Faridabad 121006	IS 2312 : 1976	93-06-01	Application not received
18 1070733	Union Tractor Workshop 8-B, Phase II Mayapuri Industrial Area New Delhi-110064	IS 9020 : 1979	93-08-16	Party not interested
19 1080736	Madras Electrical Conductors Pvt. Ltd. 37, Arcot Road Post Box No. 2256 Madras 600026	IS 398 (Part 1) : 1976	93-04-01	Party not interested
20 1100312	MP Steel Wool Factory Pvt. Ltd. D-850, New Friends Colony New Delhi-110014	IS 398 (Part 1) : 1976	93-08-16	Application not received
21 1107427	Ashoka Boot Factory 17/300, Sadar Bhatti Agra 282003	IS 1989 (Part 2) : 1986	93-08-16	Application not received

1	2	3	4	5
22 1130122	Partap Steel Rolling Mills Ltd. Industrial Area Patancheru 502320	IS 8051 : 1976	92-09-16	Not applied
23 1185548	Insecticides & Allied Chemicals 87/6, Arcot Road Madras 600026	IS 2567 : 1978	93-05-01	Application not received
24 1195551	JKEM Ltd. 133-134, GIDC Industrial Estate Ankleshwar Distt. Bhruch 393002	IS 8445 : 1977	93-10-01	Firm not interested
25 120923	Associated Cement Co. Ltd. (Fraser Investment Ltd.) Shahbad Cement Works Shahbad, Distt. Gulbarga Karnataka 585229	IS 269 : 1989	93-07-01	Marking fees not paid
26 1209334	Associated Cement Co. Ltd. (Fraser Investment Ltd.) Shahbad Cement Works Shahbad, Distt. Gulbarga Karnataka 585229	IS 1489 : 1976	93-07-01	party not interested
27 1209536	Lokapur Cements Pvt. Limited Lokapur 587122 Distt. Bijapur Karnataka State	IS 269 : 1989	93-07-01	Not interested
28 1222326	Godrej Soaps Ltd. 1-B, Industrial Estate Ambattur Madras 600098	IS 2052 : 1979	93-07-16	Application not received
29 1309439	P.G. Conduciors Pipalia-Kalan 306307 (Distt. Pali) Rajasthan	IS 398 (Part 1) : 1976	93-05-16	Party not interested
30 1310424	Modern Paint Works 242/2A, Manick-Tola Main Road Calcutta 700054	IS 133 : 1975	93-05-01	Application not received
31 1318844	Shyam Engg. Works 218, Jaintipur Sulem Sarai Allahabad	IS 458 : 1988	93-07-01	Firm not interested
32 1324637	East India Commercial Co. Jute Ltd. Lessee, Sri Krishna Jute Mills Eluru 534002	IS 2580 : 1982	93-08-01	Party not interested
33 1330834	Andhra Cement Co. Ltd. Durga Cement Works Durga Puram Dachepalli Post 522414 Guntur Distt.	IS 1489 : 1976	93-10-01	Party not interested

1	2	3	4	5
34 1367049	Andhor Electronics & Electricals Pvt. Ltd. Kailash Road Mograwadi Bulsar 396001	IS 1293 : 1988	93-02-01	Firm not interested
35 1411531	Electrical Mfg. Co. Ltd. EMC Garden 136, Jessore Road Calcutta 700035	IS 398 (Part 4) : 1976	93-06-01	Application not received
36 1431234	Sagar Cements Ltd. Mathampally 508204 Hydurnagar Taluk Nalgonda DT.	IS 269 : 1989	93-07-01	Party not interested
37 1436345	Drums & Barrels (Madras) Private Ltd. 5-A, Vaidyanathan Street Tundiarpet Madras 600081	IS 3575 : 1977	93-07-16	Not interested
38 1448554	Jepika Chemicals Industries (India) Pvt. Ltd. Jepika House Jepika Street Daulat Ganj Gwalior	IS 427 : 1965	93-09-01	Party not interested
39 1448655	Jepika Chemicals Industries (India) Pvt. Ltd. Jepika House Jepika Street Daulat Ganj Gwalior	IS 428 : 1969	93-09-01	Party not interested
40 1455147	Oswal Oils & Vanaspati Industries 107, Cochrane Basin Road Madras 600021	IS 10633 : 1986	93-10-01	Not interested
41 1555353	New Karnataka Tin Factory Shed No. C-33 Indl. Estate Gokul Road Hubli 30	IS 10325 : 1989	93-04-16	Not interested
42 1562350	Ashok Metal Box Industries F-778, Road No. 13 V.K.I. Area Jaipur 302013	IS 10325 : 1989	93-05-16	Party not interested
43 1567865	Hastmara Industries Ltd. P.O. Alipur Distt. 24-Parganas	IS 2580 : 1982	93-06-01	Application not received
44 1573052	B.B. Enterprises 302/2/H/8 Adharya Prafulla Chandra Road Calcutta 700007	IS 2573 : 1986	93-07-01	Application not received
45 1576967	Ganesh Plastic Industries Kalyanaraman Street Jaganathanpuram Ariyamanglam Tiruchirapalli	IS 10840 : 1986	93-06-16	Not interested

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
46 1588570	Tripura Jute Mills Ltd. Hapania Post : Arundhati Nagar Agartala 799003 Tripura	IS 3984 : 1967	93-08-01	Application not received
47 1596872	Rajdoot Paints Pvt. Ltd. A-38, Indl. Area Ghaziabad-Bulandshahar Road Sikandrabad 203205	IS 9862 : 1981	93-09-01	Party not interested
48 1628051	Uday Electricals Plot No. 448, Phase II Near Vinzol Village GIDC Estate Vatva, Ahmedabad	IS 9079 : 1989	92-12-01	Application not received
49 1639965	Coimbatore Pioneer Rolling Mill Narasimhanaickempalayam Coimbatore 641031	IS 226 : 1975	93-01-16	Party not interested
50 1697686	Blue Star Inds. Unit No. 22, Ground Floor Agaruda Indl Estate S.V. Road Dahisar (E) Bombay	IS 8808 : 1986	93-06-16	Application not received
51 1771359	Optima Lamps Pvt. Ltd 12th km, Hosur Road Bangalore 560068	IS 418 : 1978	91-12-16	Unsatisfactory Performance
52 1829162	Khaitan Electricals Ltd. Plot No. 14, Sector 6, Faridabad 121006	IS 4283 : 1981	93-06-01	Application not received
53 1836159	Master Engg. Co. Lilajpur Road, Dholka 387810 Distt. Ahmedabad	IS 8034 : 1989	93-06-16	Change in Management
54 1833567	Reavathee Enterprises Dev. Plot No. 30(SP) Indl. Estate Guindy Madras 600032	IS 398 (Part 2) : 1976	93-06-01	Marking fees not paid
55 1838971	Prabhat Spun Pipes Semra Maghar Khalilabad Basti	IS 458 : 1988	93-07-01	Application not received
56 1882873	Venkateshwara Conduits Pvt Ltd. F-20 Sipcot Industrial Complex Guwaidipoondi 601201	IS 3601 : 1984	93-10-01	Not interested
57 1884170	JKEM Ltd. 133-134, GIDC Industrial Estate Ankleshwar Distt. Bharuch 393002	IS 4766 : 1982	93-10-01	Firm not interested
58 1884877	Sankla Appliances Pvt. Ltd. Plot No. 64 Sector 24 Faridabad 121005	IS 11480 : 1985	93-09-01	Firm not interested

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
59 1899789	D.S. Industries	IS 10805 : 1986	92-11-16	Party not interested
50 1968883	Frig Corporation of Rajasthan H-686, Basni II Phase Jodhpur 340001	IS 1475 : 1078	93-05-01	Party not interested
6 1982473	Bharti Rasaynic Udyog Sadar Bazar Dhamtari	IS 8960 : 1978	93-09-01	Party not interested
62 1988687	Alliance Mills (Lessees) Pvt. Ltd. 18, Netaji Subhas Road Calcutta 700001	IS 12154 : 1987	93-06-16	Application not received
63 1988788	Alliance Mills (Lessees) Pvt. Ltd. 18, Netaji Subhas Road Calcutta 700001	IS 7407 (Part 2) : 1980	93-06-16	Application not received
1988889	Alliance Mills (Lessees) Pvt. Ltd. 18, Netaji Subhas Road Calcutta 700001	IS 7407 (Part 3) : 1980	93-06-16	Application not received
65 1999490	Durga Bhagwati Agriculture 11/47 D, Rambagh Agra 282006	IS 6595 : 1980	93-07-16	Performance Unsatisfactory
66 2005929	Fort William Co. Ltd. 10, Clive Row, Third Floor Calcutta 700001	IS 7407 (Part 3) : 1980	93-08-01	Application not received
67 2008228	Sunray Agrochem Industries Agra Mathura Road Runukata, Agra	IS 562 : 1978	93-09-16	Party not interested
68 2014627	Reliance Jute and Industries Ltd. 9, Brabourne Road Calcutta 700001	IS 7407 (Part 2) : 1980	93-03-16	Application not received
69 2021220	Capital Meters Pvt. Ltd. Plot No. 17, Block A Sector IX Noida 201301	IS 722 (Part 3) : 1986	93-09-01	Party not interested
70 2027030	Parleyites Extrusions Pvt. Ltd. C-57 MIDC Indl Area Mirjule Ratnagiri 415639	IS 4985 : 1988	93-09-16	Marking fees not paid
71 2067547	J.K. Jute Mills Co. Ltd. Kalpi Road Fazal Ganj Kanpur	IS 7407 (Part 3) : 1980	93-04-01	Performance Unsatisfactory
72 2099762	Veena Enterprises Plot No. 61 Phase III Auto, Nagar Vijayawada 520007	IS 7466 : 1974	93-04-01	Party not interested
73 2113326	Abhishek Steels Ltd. Gundla Pocham Pally Via Hakimpet Medchal Mandal Ranga Reddy Distt 500014	IS 226 : 1975	93-05-16	Indian standard withdrawn

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
74 2113031	Abhishek Steels Ltd Gufindla Pocham pally Via Hakimpet Medhal Mandal Ranga Reddy Distt. 500014	IS 1977 : 1975	93-05-16	Application not received
75 2126032	Manual Feeds Corporation Cherupunkal P.O. Palai Kottayam (Kerala) 686584	IS 1374 : 1979	93-06-16	Not interested
76 214940	Agro Chemical Inds. Shed No. 213 SIDCO Industrial Estate Ambattur, Madras 600008	IS 9356 : 1980	93-07-16	Application not received
77 2143638	Nuchem Plastic Ltd. 20/6, Mathura Road Faridabad 121006	IS 9103 : 1979	93-08-16	Firm not interested
78 2153742	Shiv Chemicals 356, Krishna Kamal Niwas Marwad Gali At Post Taluka Shew Gaon Distt. Ahmednagar 414502	IS 1065 : 1989	93-10-01	Firm not interested
79 2176249	Vishal Engg. Works J.C. Bangad Complex Near Kamla Vidyalaya Near Gouri Cinema C.T.M. Road, Odhav Ahmedabad 382415	IS 9079 : 1989	93-01-01	Application not received
80 2232233	Jain Indl. Corpn. Khasra No. 386 Nangal Road Jhotwara Jaipur 302012	IS 10325 : 1989	93-04-01	Party not interested
81 2257249	Heiloers Ltd. Chartered Bank Buildings Calcutta 700001	IS 10647 - 1983	93-07-01	Application not received
82 2265248	Siddharth Udyog Gram-Parsia PO Soharatgarh Distt. Sidhartha Nagar 272205	IS 458 : 1988	93-08-01	Application not received
83 2267050	H.V. Industrial Electronics Pvt. Ltd. B-52/53, GIDC Electronics Estate Sector 23 Gandhinagar (Gujarat) 382023	IS 3854 : 1988	93-09-01	Apphcation not received
84 2270645	Sharda Ispat Ltd. Kamptee Road Nagpur 440026	IS 2879 : 1975	93-08-16	Firm not interested
85 2272346	Jammu Foods (P) Ltd. 185, A/D Gandhi Nagar Jammu (J&K)	IS 1165 : 1986	93-08-16	Appliocation not received
86 2275251	Anupam Industries Khasra No. 894 Alipur Garhi Delhi 110036	IS 2980 : 1986	93-08-16	Party not interested

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
87 2277255	Pithampur Conzima Pvt. Ltd. 1230, Sudama Nagar Indore-452009	IS 398 (Part 1) : 1976	93-09-01	Party not interested
88 2277356	Pithampur Conzima Pvt. Ltd. 1230, Sudama Nagar Indore 452009	IS 398 (Part 2) : 1976	93-09-01	Party not interested
89 2279158	Mico Farm Chemicals Ltd. No. 165, Thampu Chetty Street Lotus Court Madras-1	IS 3902 : 1975	93-09-16	Not interested
90 2287309	Balmer Lawrie Co. Ltd. 21, Netaji Subhash Road P.B. No. 4 Calcutta-700001	IS 6312 : 1980	93-10-01	Application not received
91 229295	Subhash Sarat Steel Rolling Mills Koleshet Road, Post Sandoz Baug Thane 400607	IS 2062 : 1984	93-10-16	Licence surrendered
92 2297160	Patira Food Products Pvt. Ltd. 3, Kevadawdi Rajkot-02360	IS 2639 : 1984	93-11-01	Application not received
93 2301327	Partap Steel Rolling Mills Ltd. Industrial Area Patancheru 502320	IS 3431 : 1982	92-09-16	Not applied
94 2365858	Air Foam Industries Pvt. Ltd. No. 78, Chemical Sector Ambattur Indl. Estate Madras-600098	IS 4989 (Part 1) 1985	93-05-16	Application not received
95 2367458	Rajdoot Paints Pvt. Ltd. A-38, Indl. Area Ghaziabad Bulandshahr Road Sikandrabad-203203	IS 133 : 1975	93-09-01	Party not interested
96 2375457	R.P. Industries Chanderlok Baghat Road Meerut (UP)-250002	IS 2980 : 1986	03-06-16	Party not interested
97 2395564	Vidhi Enterprises 2553, Satghara Dharampura (Inside Dariba, Chandi Chowk Delhi 110006	IS 12786 : 1989	93-09-01	Party not interested
98 2403032	Vidraj Industries 207 Vinay Heavy Indl. Estate Deorukhar Wadi Chinch Bunder Road Malad (W) Bombay 400064	IS 694 : 1977	93-09-16	Application not received
99 7001542	Kulkarni Engg. Co. Plot A/100 MIDC Phase I Bombivli Distt. Thane-421203	IS 2148 : 1981	93-01-16	Firm not interested

नागरिक पूर्ति, उद्योक्ता मामले और
सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
नई दिल्ली, 22 मार्च, 1995

का.आ.869.—केन्द्रीय सरकार का विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (माडल का अनुमोदन), नियम, 1937 के उपबन्धों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि वह लगातार प्रयोग की अवधि में यथार्थता बनाये रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा करता रहेगा।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "स्लीक आई टी बी" टाइप के स्वतः सूचक गैर-स्वचालित तोलन उपकरण के माडल को (जिसे हममें इसके पश्चात् माडल कहा गया है) जिसका विनिर्माण मैक्स इन्टेग्रेटेड प्रोसेस ऑटोमेशन स्केल्स, बी-377, फर्स्ट स्टेज, पान्या इन्डस्ट्रियल एस्टेट, बंगलूर-58, द्वारा किया गया है और जिसे अनुमोदन बिन्ह आई.एन.डी./09/94/44 अनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है,

आगे, केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा (12), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि माडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अन्तर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त के अनुसार और उसी सामग्री से, जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है विनिर्मित 5 किलोग्राम/2 ग्राम की अधिकतम क्षमता वाले समरूप मेक, यथार्थता और उसी रिमीज के कार्यकरण वाले तोलन उपकरण भी हैं।

आकृति



माडल (आकृति देखिए) एक मध्यम यथार्थता (यथार्थता वर्ग 3) का तोलन उपकरण है जिसकी अधिकतम क्षमता 5 किलोग्राम और न्यूनतम क्षमता 20 ग्राम है। सत्यापन मापमान अन्तर 1 ग्राम है। इसमें एक टेयर युक्ति है जिसका व्यकलनात्मक प्रतिधारण टेयर प्रभाव 100 प्रतिशत

भवग्रही वृत्ताकार आकृति का है जिसका व्यास 200 मि.मी. है। 13 मि.मी. आकार का प्रकाश उत्सर्जन डायोड संप्रदर्श तौल परिणाम उपदर्शित करता है। यह उपकरण 230 वोल्ट, 50 हर्टज के प्रत्यावर्ती धारा विद्युत् प्रदाय पर प्रचालित होता है।

[फ.सं. डब्ल्यू एम-21(46)/92]

सुजीत बनर्जी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS,
AND PUBLIC DISTRIBUTION

New Delhi, the 22nd, March, 1995

S.O. 869.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of Model of self-indicating non-automatic weighing instrument of type "Sleek ITB" (hereinafter referred to as the Model) manufactured by H/s Integrated Process Automation Scales B 377, 1st Stage, Peenya Industrial Estate, Bangalore-58 and which is assigned the approval mark IND/09/94/44 ;

Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of the said section, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the weighing instrument of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity of 5 kilogram/2 g. made by the same manufacturer in accordance with the same principle and with the same materials with which, the approved Model has been manufactured.

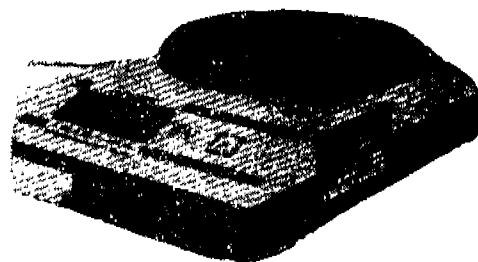


Fig.

The Model (see figure) is a medium accuracy (accuracy class III) weighing instrument with a maximum capacity of 5 kilogram and minimum capacity of 20 gram. The verification scale interval (e) is 1 gram. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The load receptor is of circular shape of dia 200 millimetre. The LED display of character size 13 millimetre indicates the weighing result. The instrument operates on 230 volts, 50 hertz alternate current power supply.

[F. No. WM-21 (46)/92]
SUJIT BANERJEE, Jt. Secy.

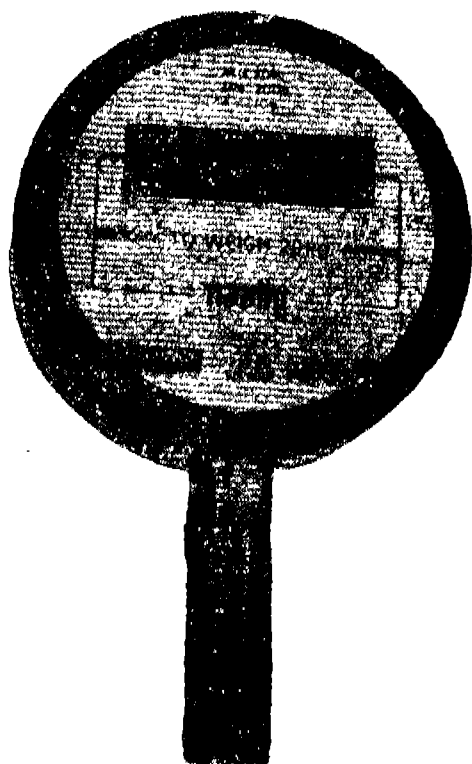
नई दिल्ली, 22 मार्च, 1995

का.आ. 870—केन्द्रीय सरकार का विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (माडल का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबन्धों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि वह लगातार प्रयोग की अवधि में यथार्थता बनाये रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा करता रहेगा।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "नीथी आई टी बी" टाइप के स्वतः सूचक गैर-स्वचालित तोलन उपकरण के माडल को (जिसे इसमें इसके

पश्चात् माडल कहा गया है), जिसका विनिर्माण मैसर्स इण्टेग्रेटेड प्रासेस आटोमेशन स्केल्स, बी-377 फस्ट स्ट्रेज, पीन्ना इण्डस्ट्रियल एस्टेट, बंगलूर-58 द्वारा किया गया है और जिसे अनुमोदन चिन्ह आई.एन.डी./09/94/45 अनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है,

आगे, केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि माडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अन्तर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त के अनुसार और उसी सामग्री से, जिसमें अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है विनिर्मित 20 किलोग्राम की अधिकतम क्षमता वाले समरूप यथार्थता और उमी मिर्रीज के कार्यकरण वाले तोलन उपकरण भी हैं।



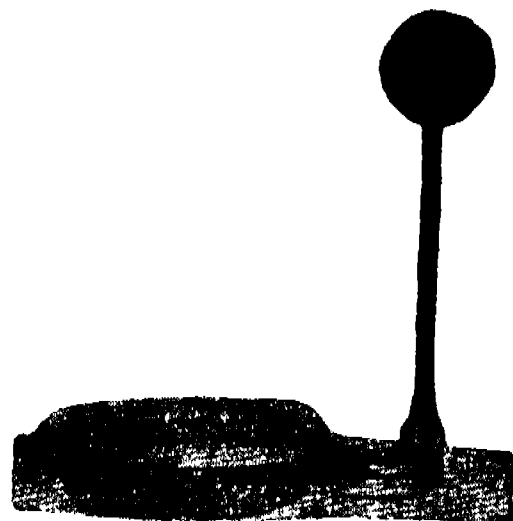
आकृति

माडल (आकृति देखिए) एक मध्यम यथार्थता (यथार्थता वर्ग 3) का तोलन उपकरण है जिसकी अधिकतम क्षमता 10 किलोग्राम और न्यूनतम क्षमता 100 ग्राम है। स्थापन मापमान अन्तर 5 ग्राम है। इसमें एक टैयर युक्ति है जिसका व्यकलनात्मक प्रतिधारण टैयर प्रभाव 100% है

भारग्राही वृत्ताकार आकृति का है जिसका व्यास 350 मि.मी. है। 13 मि.मी. आकार का प्रकाश उत्सर्जन डायोड संप्रदर्श तोल परिणाम उपदर्शित करता है। यह उपकरण 230 वोल्ट, 50 हर्ट्ज के प्रत्यावर्ती धारा विद्युत् प्रदाय पर प्रचालित होता है।

[फा.सं. डब्ल्यू.एम-2/46]/92]

सुजीत बनर्जी, संयुक्त सचिव



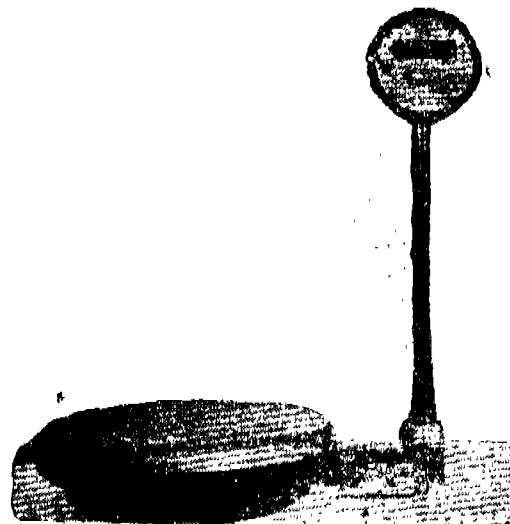
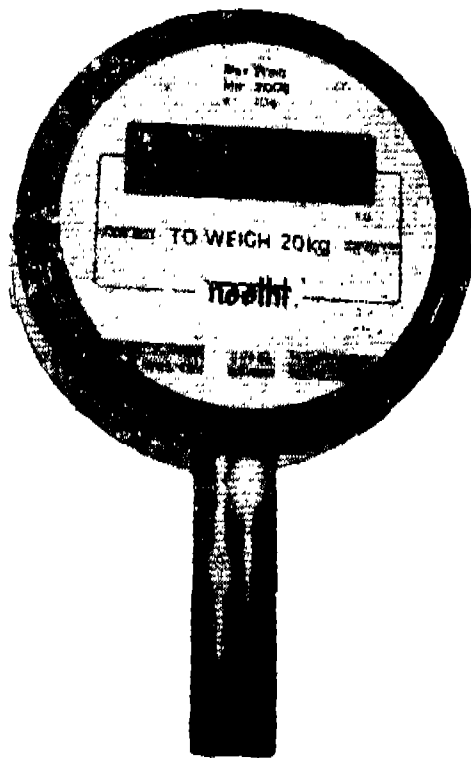
New Delhi, the 22nd March, 1995

S.O. 870.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority is satisfied that the Model described in the said report is in conformity with the provisions of the Standard of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of Model of self-indicating non-automatic weighing instrument of type "Neethi-ITB" (hereinafter referred to as the Model) manufactured by M/s. Integrated Process Automation Scales, B-377, 1st Stage, Peenya Industrial Estate, Bangalore-58 and which is assigned the approval mark IND/09/94/45 ;

Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of the said section, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the weighing instrument of similar make, accuracy

and performance of same series with maximum capacity of 20 kilogram made by the same manufacturer in accordance with the same principle and with the same materials with which, the approved Model has been manufactured.



The Model (see figure) is a medium accuracy (accuracy class III) weighing instrument with a maximum capacity of 10 kilogram and minimum capacity of 100 gram, the verification scale interval (e) is 5 gram. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The load receptor is of circular shape of dia 350 millimetre. The LED display of character size 13 millimetre indicates the weighing result. The instrument operates on 230 volts, 50 hertz alternate current power supply.

[F. No. WM-21(46)/92]

SUJIT BANERJEE, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 22 मार्च, 1995

का.आ. 871.—केन्द्रीय सरकार का विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (माडल का अनुमोदन) नियम,

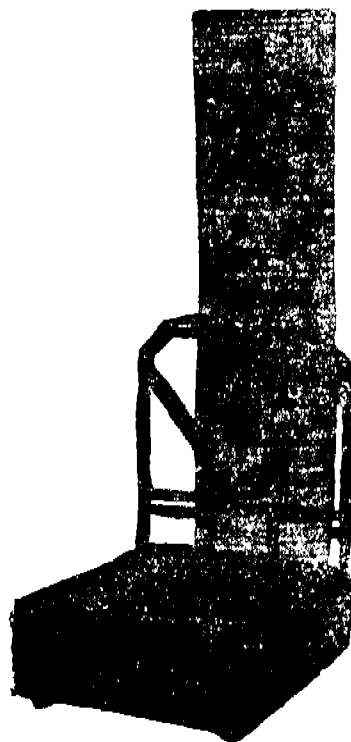
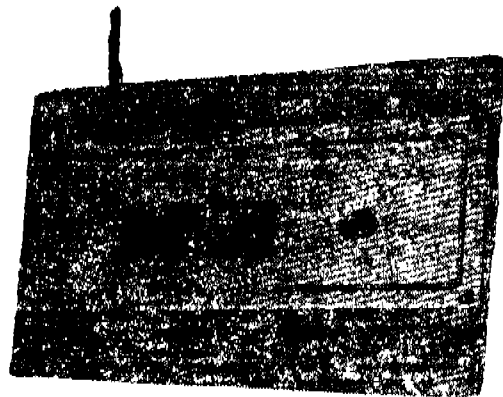
1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि वह लगातार प्रयोग की अवधि में यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा करता रहेगा;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "आई पी ए-12/51" टाइप के स्वतः सूचक गैर-स्वचालित तोलन उपकरण के माडल को (जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है) जिसका विनिर्माण के मैसर्स इंडस्ट्रियल प्रोसेस आटोमेशन स्केल्स, बी-377, फर्स्ट स्ट्रेज, पोन्त्या इंडस्ट्रियल एस्टेट, बंगलौर-58 द्वारा किया गया है और जिसे अनुमोदन चिह्न आई.एन.डी./09/94/46 अनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है;

आगे, केन्द्रीय सरकार उक्त धारा की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि माडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनि-

मर्ता द्वारा उसी सिद्धांत के अनुसार और उसी सामग्री के, जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है विनिर्मित 50 किलोग्राम, 80 किलोग्राम, 200 किलोग्राम, 300 किलो-

ग्राम, 500 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम और 2000 किलोग्राम की अधिकतम क्षमता वाले समस्त मेक, यथार्थता और उसी सिरोज के कार्यकरण वाले तोलन उपकरण भी हैं।



माडल (आकृति देखिए) एक मध्यम यथार्थता (यथार्थता वर्ग 3) का तोलन उपकरण है जिसकी अधिकतम क्षमता 100 किलोग्राम और न्यूनतम क्षमता एक ग्राम है, सत्यापन मापमान अन्तर 50 ग्राम है। इसमें एक डेयर युक्त है जिसका व्यवकलनात्मक प्रतिधारण, प्रतिधारण डेयर प्रभाव 100 प्रतिशत है। भारग्राही वर्गाकार आकृति का एक प्लेटफार्म है जिसके पार्श्व 500 मि.मी. है। 13 मि. मी. आकार का प्रकाश उत्सृजन डायोड संप्रवर्श तौल परिणाम उपदर्शित करता है। यह उपकरण 230 वोल्ट, 50 हर्ट्ज के प्रत्यावर्ती द्वारा विद्युत् प्रवाय पर प्रचालित होता है।

[फा. सं. डब्ल्यू.एम-21 (46)/92

सुजीत बनर्जी, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 22nd March, 1995

S.O. 871.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority,

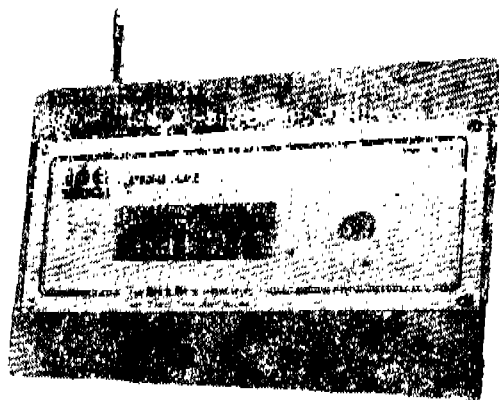
is satisfied that the Model described in the said report is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of Model of self-indicating non-automatic platform weighing instrument of type "IPS-12/SI" (hereinafter referred to as the Model manufactured by M/s. Integrated Process Automation Scales, B-377, 1st Stage, Peenya Industrial Estate, Bangalore-58 and which is assigned the approval mark IND/09/94/46 ;

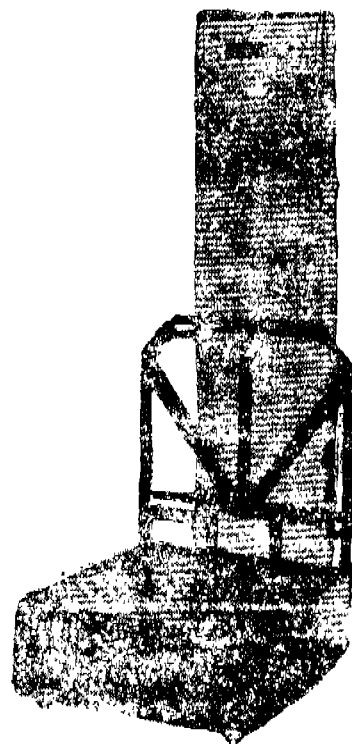
Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of the said section, the Central Government

hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the platform weighing instrument of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity of 50 kg, 80 kg, 200 kg, 300 kg, 500 kg,

1000 kg and 2000 kg made by the same manufacturer in accordance with the same principle and with the same materials with which, the approved Model has been manufactured.



The Model (see figure) is a medium accuracy (accuracy class III) weighing instrument with a maximum capacity of 100 kilogram and minimum capacity of 1 kilogram. The verification scale interval (e) is 50 gram. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The load receptor is a platform of square shape of side



500 millimetre. The LED display of character size 13 millimetre indicates the weighing result. The instrument operates on 230 volts, 50 hertz alternate current power supply.

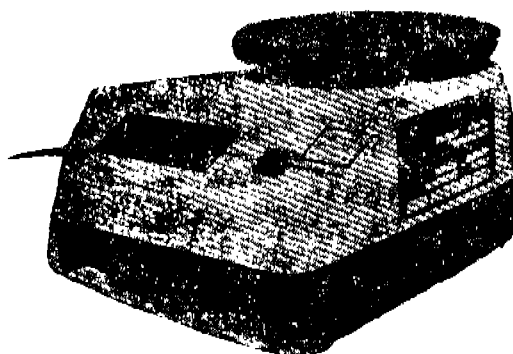
[F. No. WM-21(46)-92]
SUJIT BANERJEE, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 22 मार्च, 1995

का.आ. 872.—केन्द्रीय सरकार का विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल वाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और वाट और माप मानक (माडल का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि वह लगातार प्रयोग की अवधि में यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा करता रहेगा;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 का उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "डिग्री आई टी सी" टाइट के स्वतः सूचक गैर-स्वचालित तोलन उपकरण के माडल को (जिमें इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है) जिसका विनिर्माण मैसर्स इंटेग्रेटेड प्रोसेस प्राटो-मेशन स्कैम, बी-377, फर्स्ट स्टेज, पीन्या इंडस्ट्रियल एस्टेट, बंगलूर-58 द्वारा किया गया है और जिसे अनुमोदन चिह्न आई.पिन.नो./09/94/47 अनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है;

आगे, केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि माडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी विधान के अनुसार और उसी सामग्री से, जिसे अनुमोदन प्राप्ति का विनिर्माण किया गया है विनिर्मित 200 ग्राम/0.1 ग्राम और 2 किलोग्राम/0.5 ग्राम की अधिकतम क्षमता वाले समस्त पैक, यथार्थता और उसी मिररिज के कार्यकरण वाले तोलन उपकरण भी हैं।



माडल (आकृति देखिए) एक मध्यम यथार्थता (यथार्थता वर्ग 3) का तोलन उपकरण है जिनकी अधिकतम क्षमता 2 किलोग्राम और न्यूनतम क्षमता 20 ग्राम है। सत्यापन सामान अन्तर एक ग्राम है। इसमें एक टेयर युक्त है जिसका व्यकल-नात्मक प्रतिधारण प्रतिधारण टेयर प्रभाव 100 प्रतिशत है।

भारवाही बृत्ताकार आकृति का है जिसका व्यास 150 मि.मी. है। 13 मि.मी. आकार का प्रकाश उत्सर्जन डायोड संप्रदर्श तोल परिणाम उपदर्शित करता है। यह उपकरण 230 वोल्ट, 50 हर्ट्ज के प्रत्यावर्ती धारा विद्युत् प्रदाय पर प्रचालित होता है।

[फा. सं. डब्ल्यू एम-21(46)/92]

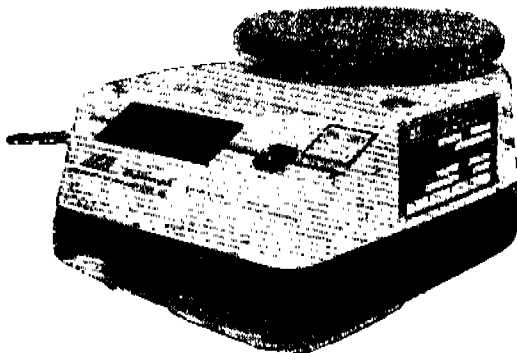
सुजीत बनर्जी, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 22nd March, 1995

S.O. 872.—Whereas the Central Government after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use to render accurate service under varied conditions ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of Model of self-indicating non-automatic weighing instrument of type "Digiweigh-ITB" (hereinafter referred to as the Model manufactured by M/s. Integrated Process Automation Scales, B-377, 1st Stage, Peenya Industrial Estate, Bangalore-58 and which is assigned the approval mark IND/09/94/47 ;

Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of the said section, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the platform weighing instrument of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity of 200 g/0.1 g. and 2 kg./0.5 g. made by the same manufacturer in accordance with the same principle and with the same materials with which, the approved Model has been manufactured.



The Model (see figure) is a medium accuracy (accuracy class III) weighing instrument with a maximum capacity of 2 kilogram and minimum capacity of 20 gram the verification scale interval (e) is 1 gram. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The load receptor is a of circular shape of dia 150 millimetre. The LED display of character size 13 millimetre indicates the weighing result. The instrument operates on 230 volts, 50 hertz alternate current power supply.

[F. No. WM-21(46)/92]

SUJIT BANERJEE, Jt. Secy.

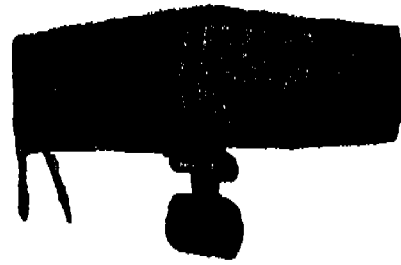
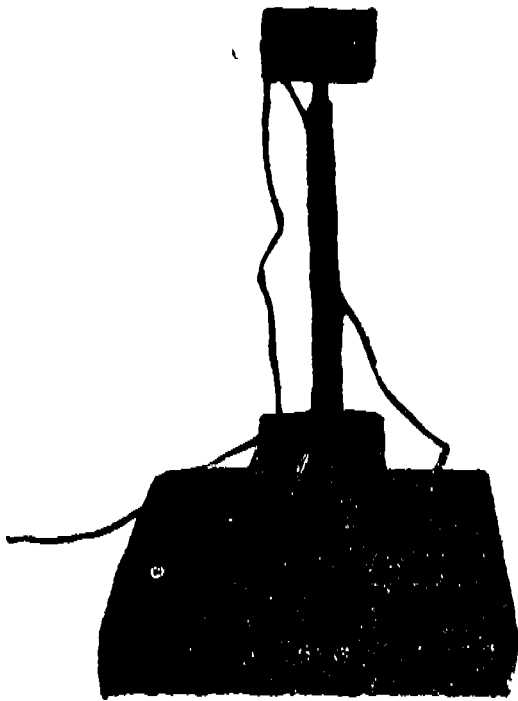
नई दिल्ली, 22 मार्च, 1995

का०आ० 873.—केन्द्रीय सरकार का विहित प्राधिकारी द्वारा उसे निवेदित रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल बाट, और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (माडल का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि वह लगातार प्रयोग की अवधियों में यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा करता रहेगा;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "ओ पी डब्ल्यू" (जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है) के स्वतः सूचक गैर-स्वचालित तोलन उपकरण के माडल का जिसका निर्माण मैसर्स ओमेगा इलेक्ट्रोनिक्स स्केल कं०, 27, तामगेनद लेन, फोर्ट, मुम्बई-400001 द्वारा किया गया है और जिसे अनुमोदन चिह्न आईएनडी/09/4/32-समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र प्रकाशित करती है।

आगे, केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि माडल के अनुमोदन के इस प्रमाण-पत्र के अन्तर्गत, उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त के अनुसार, उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है, विनिर्मित 50 किलोग्राम, 80 किलोग्राम, 180 किलोग्राम, 250 किलोग्राम, 300 किलोग्राम, 500 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम, 5000 किलोग्राम और 10000 किलोग्राम की अधिकतम क्षमता वाली मेक, यथार्थता और कार्यकरण उसी

सिरीज के तोलन उपकरण भी है।



(आकृति)

माडल (आकृति देखिए) एक मध्यम यथार्थता (यथार्थता वर्ग 3) वाला तोलन उपकरण है जिसकी अधिकतम क्षमता 100 किलोग्राम और न्यूनतम क्षमता 400 ग्राम है। सत्यापन मापमान अन्तर 20 ग्राम है। इसमें एक टेयर युक्ति है जिसका व्यकलनात्मक प्रतिधारण टेयर 100 प्रतिशत है। आधार और प्लेटफार्म मृदु स्टील का है। भारग्राही वर्गिकार आकृति का है और पार्श्व लम्बाई 600 मि०मी० है। प्रकाश उत्सर्जन डायोड संप्रदर्श तोल परिणाम उपदर्शित करता है। यह उपकरण 230 वोल्ट, 50 हर्ट्ज के प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर प्रचालित होता है।

[फा० सं० डब्ल्यू०एस०-21(19)/93]

मुजीन बनर्जी, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 22nd March, 1995

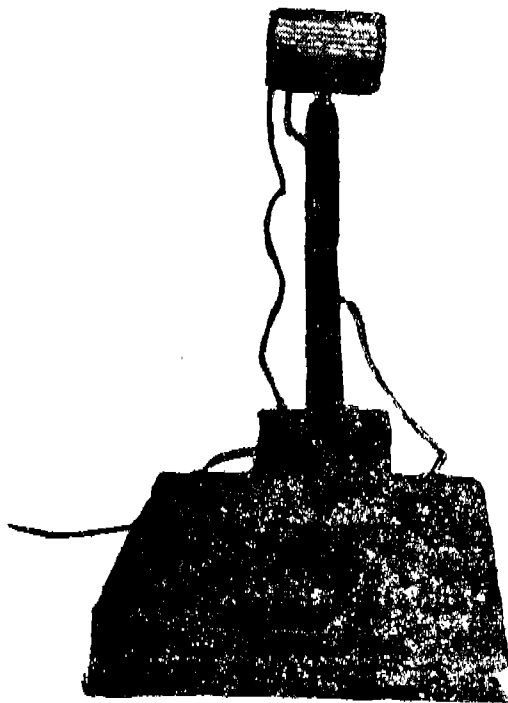
S.O. 873.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority,

is satisfied that the Model described in the said report is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of Model of self-indicating non-automatic weighing instrument of type OPW (herein after referred to as the Model) manufactured by M/s. Omega Electronics Scale Co., 27, Tamarind Lane, Fort, Bombay-400001 and which is assigned the approval mark IND/09/94/32;

Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of the said section, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the weighing instrument of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity of 50 kilogram, 80 kilogram, 180 kilogram, 250 kilogram 300 kilogram, 500 kilogram, 1000 kilogram, 5000 kilogram and 1000 kilogram manufactured by the same manufacturer in

accordance with the same principle and with the same materials with which, the approved Model has been manufactured.



(Figure)

The Model (see figure) is a medium accuracy (accuracy class III) weighing instrument with a maximum capacity of 100 kilogram and minimum capacity of 400 gram. The verification scale interval (e) is 20 gram. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The base and the platform are of mild steel. The load receptor is of square shape with side of length 600 millimetre.

The LED display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 volts, 50 hertz alternate current power supply.

[F. No. WM-21(19)/93]
SUJIT BANERJEE, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 22 मार्च, 1995

कां०श्रा० 874.—केन्द्रीय सरकार का विहित प्राधिकारी द्वारा उसे निवेदित रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (माडल का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और दूरा बात की संभावना है कि वह लगातार प्रयोग की अवधियों में यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा करता रहेगा;

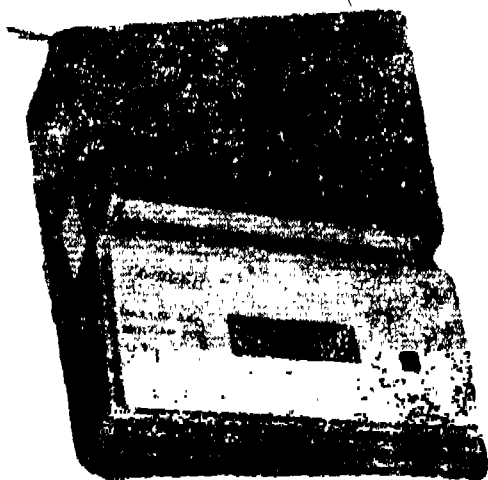
अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "ओ०टी०डब्ल्यू" (जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है) के स्वतः सूचक गैर-स्वचालित तोलन उपकरण के

माडल का जिसका निर्माण मैसर्स ओमेगा इलेक्ट्रॉनिक्स स्कूल कं० 27, तामारीन्द लेन, फोर्ट, मुम्बई-400001 द्वारा किया गया है ओर जिसे अनुमोदन चिह्न आईएनडी/09/4/33 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र प्रकाशित करती है।

आगे, केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि माडल के अनुमोदन के इस प्रमाण-पत्र के अन्तर्गत, उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त के अनुसार, उसी सामग्री से जिसमें अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है, विनिर्मित 1.8 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 8 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 18 किलोग्राम, 25 किलोग्राम और 40 किलोग्राम की अधिकतम क्षमता वाली मेक, यथार्थता और कार्यकरण उसी सिरीज तथा 100 ग्राम, 500 ग्राम और 1 किलोग्राम

की अधिकतम क्षमता के साथ "ओ.एस.डब्ल्यू" सिरीज के न्यून उपकरण भी हैं।

gram, 25 kilogram and 40 kilogram and "OSW" series with maximum capacity of 100g, 500g and 1 kg manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle and with the same materials with which, the approved Model has been manufactured.



(आकृति)

माडल (आकृति) देखिए (एक मध्यम यथार्थता वर्ग 3) वाला तोलन उपकरण है जिसकी अधिकतम क्षमता 5 किलोग्राम और न्यूनतम क्षमता 20 ग्राम है। सत्यापन माप-मान अंतर 1 ग्राम है। इसमें एक टेयर युक्ति है जिसका व्यकलनात्मक प्रतिधारण टेयर प्रभाव 100 प्रतिशत है। आधार और प्लेटफार्म मृदु स्टील का है। भारग्राही वर्गीकार आकृति का है और पाथर्व लम्बाई 200 मि.मी. है। प्रकाश उत्सर्जन हायोड संप्रदर्शन तोल परिणाम उपदर्शित करता है। यह उपकरण 230 वोल्ट, 50 हर्ट्ज के प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर प्रचालित होता है।

[फा.सं. डब्ल्यू.एम.-21(19)/93]

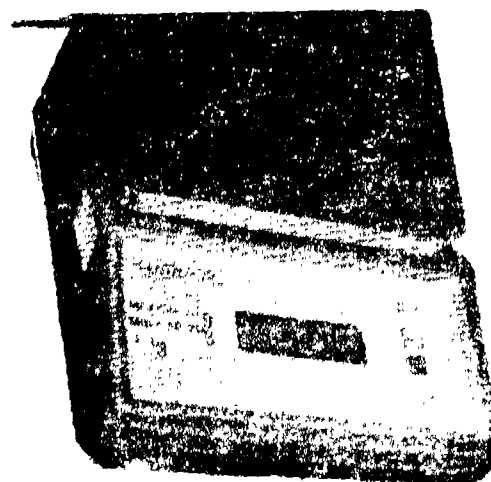
सुजीत बनर्जी, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 22nd March, 1995

S.O. 874.—Whereas the Central Government after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of Model of self-indicating non-automatic weighing instrument of type "OTW" (herein after referred to as the Model) manufactured by M/s. Omega Electronics Scale Co. 27, Tamarind Lane, Fort, Bombay-400001 and which is assigned the approval mark IND/09/94/33;

Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of the said section, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the weighing instrument of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity of 1.8 kilogram, 2 kilogram, 8 kilogram, 10 kilogram, 18 kilo-



(Figure)

The Model (see figure) is a medium accuracy (accuracy class III) weighing instrument with a maximum capacity of 5 kilogram and minimum capacity of 20 gram. The verification scale interval (e) is 1 gram. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The base and the platform are of mild steel. The load receptor is of square shape with side of length 200 millimetre. The LED display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 volts, 50 hertz alternate current power supply.

[F. No. WM-21(19)/93]

SUJIT BANERJEE, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 22 मार्च, 1995

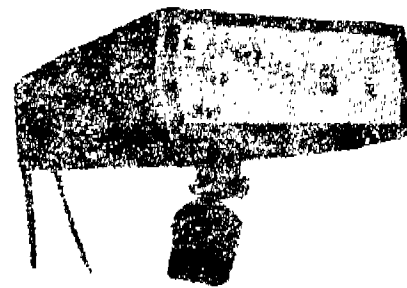
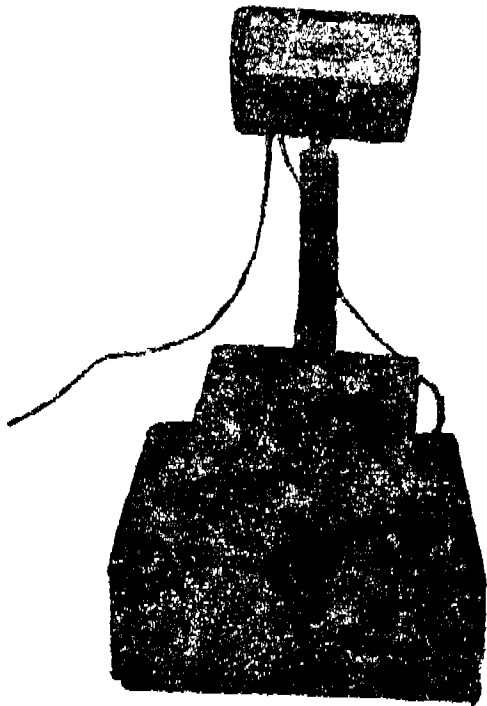
का.आ. 875.—केन्द्रीय सरकार का विहित प्राधिकारी द्वारा उसे निवेदित रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल वाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और वाट और माप मानक (माडल का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि वह लगातार प्रयोग की अवस्थितियों में यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा करता रहेगा:

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "ओ.सी.डब्ल्यू." टाइप (जिसे इसने इसके पश्चात् माडल कहा गया है) के स्वतः सूचक गैर-स्वचालित तोलन उपकरण के माडल का जिसका निर्माण सैमर्स ओमेगा इलेक्ट्रॉनिक्स स्केल कं. 27, तामारीन्द लेन, फोर्ट, मुम्बई-400001 द्वारा किया गया है और जिसे अनुमोदन चिह्न आईएनडी/09/94/34-समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र प्रकाशित करती है।

आगे, केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा (12) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि माडल के अनुमोदन के इस प्रमाण-पत्र के अन्तर्गत, उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त के अनुसार, उसी सामग्री से

प्रमाणित मापन का विनिर्माण किया गया है
विनिर्माण 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 25 किलोग्राम और

40 किलोग्राम की प्रतिष्ठापन क्षमता वाली मेट्रिक, पश्चात्त
और कार्यकरण उसी सिरीज के तालन उपकरण भी है



(आकृति)

मापन (आकृति देखिए) एक मध्यम यथार्थता (यथार्थता
वर्ग 3) वाला तालन उपकरण है जिसकी अधिकतम क्षमता
30 किलोग्राम और न्यूनतम क्षमता 100 ग्राम है। स्थापन
माप मान अंतर 5 ग्राम है। इसमें एक टेयर युक्ति है जिसका
व्यकलात्मक प्रतिधारण टेयर 100 प्रतिशत है। आध्वार
और प्लेटफार्म मृदु स्टील का है। भारग्राही वर्गाकार आकृति

का है और पार्श्व लम्बाई 300 मि०मी० है। प्रकाश उत्पन्न
डायोड संप्रदर्श तोल परिणाम उपदर्शित करता है। यह
उपकरण 230 वोल्ट, 50 हर्ट्ज के प्रत्यावर्ती द्वारा विद्युत
प्रदाय पर प्रचालित होता है।

[फाइल सं० डब्ल्यू०एम० 21(19)/93]

गुजीत बनर्जी, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 22nd March, 1995

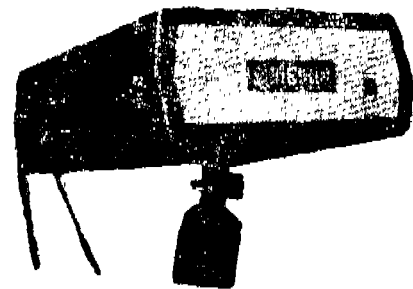
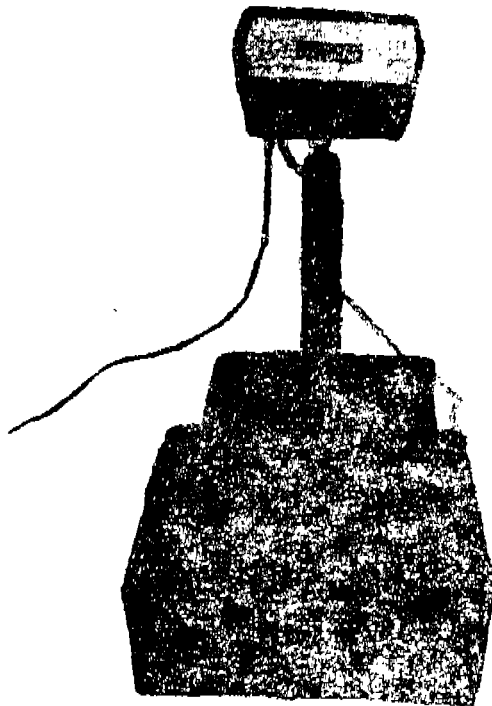
S.O. 875.—Whereas the Central Government after con-
sidering the report submitted to it by the prescribed authority,
is satisfied that the Model described in the said report is in
conformity with the provisions of the Standards of Weights
and Measures Act 1976 (60 of 1976) and the Standards of
Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and
the said Model is likely to maintain accuracy over periods
of sustained use and to render accurate service under varied
conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by
sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central
Government hereby publishes the certificate of approval of
Model of self-indicating non-automatic weighing instrument
of type "OBW" (herein after referred to as the Model)
manufactured by M/s Omega Electronics Scale Co 27,
Tamarind Lane, Fort, Bombay-400001 and which is assigned
the approval mark IND/09/94/31;

Further, in exercise of the powers conferred by sub-section
(12) of the said section, the Central Government hereby de-
clares that this certificate of approval of the Model shall

also cover the weighing instrument of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity of 10 kilogram, 18 kilogram, 25 kilogram and 40 kilogram

manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle and with the same materials with which, the approved Model has been manufactured.



The Model (see figure) is a medium accuracy (accuracy class III) weighing instrument with a maximum capacity of 30 kilogram and minimum capacity of 100 gram. The verification scale interval (e) is 5 gram. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The base and the platform are of mild steel. The load receptor is of square shape with side of length 300 millimetre. The

LED display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 volts, 50 hertz alternate current power supply.

[F. No. WM-21(19)/93]

SUJIT BANERJEE, Jr. Secy.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(महिला एवं बाल विकास विभाग)

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(Department of Women and Child Development)

पूर्व विन्यास अधिनियम, 1890 (1890 का 6) के मामले में
राष्ट्रीय बाल कोष, नई दिल्ली के मामले में
नई दिल्ली, 10 मार्च, 1995

IN THE MATTER OF THE NATIONAL CHILDREN'S
ACT, 1890
(6 of 1890)

IN THE MATTER OF THE NATIONAL CHILDREN'S
FUND, NEW DELHI

New Delhi, the 10th March, 1995

का.अ. 876.—पूर्व विन्यास अधिनियम, 1890 (1890 का 6) की धारा 10 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आदेश देती है कि भारत के लिए पूर्व विन्यास के खजांची भूतपूर्व वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग, नार्थ ब्लॉक ए नई दिल्ली में निहित तथा सचिव खजांची (राष्ट्रीय बाल कोष) के नामे जमा रु. 10,00,000 (दस लाख रुपये केवल मात्र) नीचे दिए गए अधिनियम के अनुसरण के अंकित मूल्य को निम्नलिखित प्रतिभूतियों संबंधी प्रतिदान आय को सचिव खजांची (राष्ट्रीय बाल कोष) के नामे अन्तरित कर दिया जाए।

S.O. 876.—In pursuance of Section 10 of the Charitable Endowments Act, 1890 (6 of 1890), the Central Government do hereby order that the redemption proceeds in respect of the following securities of the face value of Rs. 10,00,000 (Rupees Ten lakh only) as per details given below, held in the name of Secretary-Treasurer (NCF) and vested in the Treasurer of Charitable Endowments for India erstwhile Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, North Block, New Delhi be transferred to the Secretary-Treasurer (NCF).

प्रतिभूतियों का विवरण	अंकित मूल्य	जिस तिथि को देय है
पंचवर्षीय डेपोजिट	रु. 5,00,000/-	16-02-95
आवधिक जमा योजना		
—नवंबर—	रु. 5,00,000/-	21-02-95

Description of Securities	Face Value	Maturing on
1. Five Year's Post Time Deposit Scheme	Rs. 5,00,000	16-02-1995
2. do-	Rs.5,00,000	21-02-1995

[संख्या : 13-6/95 टी.-आर.]

रतन चन्द, अधीक्षक सचिव

[F. No. 13-6/95-TR]
RATTAN CHAND, Under Secy.

जन-भूतल परिवहन मंत्रालय

(नावहन पक्ष)

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1995

क्रा. प्रा. 877.—दीपघर केन्द्रीय सलाहकार समिति (प्रक्रियात्मक) नियमावली 1976 के नियम 3, 4 और 11 के साथ पठित दीपघर अधिनियम, 1927 (1927 का 17) की धारा 4 की उपधारा 1 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा 20 फरवरी, 1995 से 2 वर्ष की अवधि के लिए एक केन्द्रीय दीपघर सलाहकार समिति को नियुक्त करती है जिसमें निम्न-लिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:—

अध्यक्ष:

1. सचिव, जन-भूतल परिवहन मंत्रालय पदेन

सदस्य:

2. भारत सरकार के नौवाहन मन्त्रालय, पदेन
कार, जहाज भवन, बालचंद
हिराचंद मार्ग, बम्बई।
3. अवर सचिव एवं वित्त सलाहकार पदेन
जन-भूतल परिवहन मंत्रालय।
4. भारत सरकार के मुख्य जल पदेन
सर्वेक्षक, नौसेना जन सर्वेक्षण
कार्यालय।
5. एक संसद सदस्य (राज्य सभा) ।
। नामों की प्रतीक्षा है
6. एक संसद सदस्य (लोक सभा) ।
7. श्री दिलीप के. डी. अध्यक्ष एवं पद निदेशक, नौवादीप शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रा. लि.
एन. सिटीड चेम्बर्स
ऑफ कामर्स एंड
इंडस्ट्री ऑफ इंडिया
के प्रतिनिधि
8. कैप्टन जे. एस. गिल, कंपनी मास्टर मैरीनर्स ऑफ
अफ मास्टर मैरीनर्स ऑफ इंडिया, जो. पी. ओ., पा. वा.
सं. 1633, बम्बई-900001 इंडिया, बंबई के प्रति-
निधि।
9. श्री एम. उमरुदराज, महासचिव, कोयला एवं खनन अंतर्गत एनो-
नियुक्त पूर्वी तट के लिए
सेलिंग बेसेल्स हिता के
प्रतिनिधि
10. श्री अर्जुन एम. शिरकावार, अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ इंडिया
मैनिंग बेसेल्स इंडस्ट्री एसोसिएशन। पश्चिमी तट के लिए
सेलिंग बेसेल्स हिता के
प्रतिनिधि।
11. कैप्टन वी. एस. कुमार, उप महा प्रबंधक, नावहन एंड टूबरो गि.
(नावहन ग्रुप) भारतीय राष्ट्रीय जहाज
मालिक संघ के प्रति-
निधि।

12. कैप्टन डी. के. निवार्ग, उप
महाप्रबंधक, (पोर्ट सर्विस),
भारतीय नौवहन निगम

13. कैप्टन एस. एम. कारिन कुरवे, आई. पी. ए. के प्रति-
उप संरक्षक विभागापत्तनम पत्तन निधि।
न्यास

14. कैप्टन वी. एस. कुमार, एम्मार फेडरेशन ऑफ इंडियन
शिपिंग कंपनी, बम्बई चैम्बर ऑफ कामर्स
एंड इंडस्ट्री।

15. दीपघर तथा दीपपोत महानिदेशक पदेन (सदस्य सचिव)

[सं. एल एच-11015/1/94-एसएस]
मृण्नीराम, अवर सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Shipping Wing)

New Delhi, the 24th March, 1995

S.O. 877 :—In pursuance of sub-Section (1) of Section 4 of the Lighthouse Act, 1927 (17 of 1927) read with rules 3, 4 and 11 of the Central Advisory Committee for Lighthouses (Procedural) Rules, 1976, the Central Government hereby appoints for a period of two years with effect from 20th February, 1995 a Central Advisory Committee for Lighthouses, consisting of the following persons namely:—

CHAIRMAN :

1. Secretary, Ex-Officio
Ministry of Surface Transport

MEMBERS :

2. Nautical Adviser to the Ex-Officio
Government of India,
Jahaz Bhavan,
Walchand Hirachand Marg,
Bombay.
3. Additional Secretary and Ex-Officio
Financial Adviser,
Ministry of Surface Transport.
4. Chief Hydrographer to the Ex-Officio
Government of India,
Naval Hydrographic Office
5. One Member of Parliament (Rajya Sabha) Names awaited
6. One Member of Parliament (Lok Sabha)
7. Shri Dilip K. De, Chairman & Representative of the
Managing Director, Associated Chambers
Ranadip Shipping and Transport of Commerce & In-
Company Pvt. Ltd. dustry of India.
8. Capt. J.S. Gill, Representative of
Company of Master Mariners Master Mariners of
of India, Bombay
G.P.O. Post Box No. 1633,
Bombay-900001

- | | |
|---|---|
| 9. Shri S. Ural-Hraj,
General Secretary,
Coastal Sail Vessels
Owners Association. | Representative of
Sailing Vessels In-
terests for East Coast |
| 10. Shri Amin N. Sikkawala,
President,
Federation of All India Sailing
Vessels Industry Association. | Representative of
Sailing Vessels In-
terests for West Coast. |
| 11. Capt. R. Khosla,
Dy. General Manager,
Larson & Tourbo Ltd.
(Shipping Group) | Representative of
Indian National Ship-
owners Association |
| 12. Capt. D.K. Tiwari,
Dy. General Manager,
(Fleet Personal),
Shipping Corporation of India. | |
| 13. Capt. S.M. Karim Kurve
Dy. Conservator,
V.P.T. | Representative of
I.P.A. |
| 14. Capt. B.S. Kumar,
ESSAR
Shipping Company,
Bombay. | Federation of Indian
Chambers of Com-
merces & Industry. |
| 15. Director General of Lighthouses
& Lightships. | Ex-officio
(Member Secretary.) |

[No. LH-11015/1/94-SL]
MUNSHI RAM, Under Secy.

(ii) उक्त अधिसूचना में, इस प्रकार पुनः दर्शाए गए क्रम सं. 7 से 12 के सामने निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उससे संबंधित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी; अर्थात्:—

- | | |
|---|--------------------------------|
| 7. कैप्टन पी पी राधाकृष्णन,
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
भा. ना. नि., बम्बई | } जहाज मालिकों के
प्रतिनिधि |
| 8. श्री दीपक चौगुले,
संयुक्त प्रबंध निदेशक,
चौगुले स्टीमशिप लि., बम्बई | |
| 9. श्री अरुण मेहता,
प्रबंधक निदेशक,
वरुण शिपिंग कम्पनी, बम्बई | |
| 10. डा. ली. रेस्नेज,
भारतीय जहाज मालिक संघ,
बम्बई | } नाविकों के प्रतिनिधि |
| 11. कैप्टन यू. एस. आदम,
मेरीटाइम यूनियन आफ इंडिया,
बम्बई। | |
| 12. डा. एम के पाण्डे,
उप-प्रधान
फारवर्ड शीमेन यूनियन आफ
इंडिया, कलकत्ता। | |

(iii) मौजूदा क्रम सं. 3 और उससे संबंधित प्रविष्टि को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
“डा. जे. के. बागची, अपर सचिव, वाणिज्य मंत्रालय”

[फा. सं. एस एस-18011/2/94-एम एन]

मंजीराम, अव्वर सचिव

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1995

का.आ. 878.—राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड नियम, 1960 के नियम 3 के साथ पठित वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, भारत सरकार जल-मूलक परिवहन मंत्रालय (नौवहन पक्ष) की अधिसूचना सं. का.आ. 65 (अ.) दिनांक 30-1-95 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

(i) उक्त अधिसूचना में क्रम सं. “7 से 11” में दी गई मौजूदा प्रविष्टियों को पुन “7 से 15” के रूप में क्रमांकित किया जाएगा।

New Delhi, the 24th March, 1995

S.O. 878. -In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) read with Rule 3 of the National Shipping Board Rules, 1960, the Government hereby makes the following amendments in the notification of Govt. of India, Ministry of Surface Transport (Shipping Wing) S.O. No. 65(F) dt. 30-1-95, namely:—

(i) In the said notification, the existing entry at Sl. No. “7 to 11” shall be renumbered as “7 to 15” respectively.

(ii) In the said notification, against Sl. No. 7 to 12 so re-numbered, the following Sl. No. and entry relating thereto shall be inserted namely:—

- | | |
|---|------------------------------------|
| 7. Capt. P.P. Radhakrishnan,
Chairman & Managing Director,
Shipping Corpn. of India,
Bombay. | } Representative of
Shipowners. |
| 8. Shri Deepak Chowgule,
Jt. Managing Director,
Chowgule Steamship Ltd.,
Bombay. | |
| 9. Shri Arun Mehta.,
Managing Director,
Varun Shipping Co. Ltd.,
Bombay | |

- | | |
|--|--------------------------------|
| 10. Dr. Leo Barnes,
National Union of Seafarers of
India,
Bombay | } Representatives of
Seamen |
| 11. Capt. U.S. Adam,
The Maritime Union of India,
Bombay. | |
| 12. Dr. M.K. Pandha,
Vice President,
Forward Seafarers Union of India
Calcutta. | |

(iii) For the existing Sl. No. 3 and entry relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

“Dr. J.K. Bagchi, Addl. Secretary, Ministry of Commerce”

[File No. SS-18011/2/94-SL]

MUNSHI RAM, Under Secy.

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, 8 मार्च, 1995

का.आ. 879.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे जगाबद्ध अनुसूची में उल्लिखित भूमि में कोयला अभिप्राप्त किए जाने की संभावना है ;

अतः केन्द्रीय सरकार कोयला धारक क्षेत्र (प्रजन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957) का 20, की धारा 4 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस क्षेत्र में कोयले का पूर्वावलोकन करने के अपने आशय की सूचना देती है :

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांक सं. एस. ई. सी. एन./बी. एस. पी./जी. एस.(पी. एल. जी.)/लैड/137 तारीख 23 अगस्त, 1994 का निरीक्षण कलक्टर, सरगुजा (मध्य प्रदेश) के कार्यालय में या कोयला निपटक, 1, कार्डमिल हाउस स्ट्रीट कलकत्ता-700 001 या साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (राजस्व अनुभाग) सीपत रोड बिलासपुर 495001 (मध्य प्रदेश) के कार्यालय में किया जा सकता है।

अस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि में हितवद्ध सभी व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) में निर्दिष्ट सभी नक्शों, चार्टों और अन्य दस्तावेजों को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन का तारीख से नव्वे दिनों के भीतर भारसाधक अधिकारी/विभागाध्यक्ष (राजस्व) साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि., सीपत रोड, बिलासपुर-495 001 (मध्य प्रदेश) को भेजेंगे।

अनुसूची

चिरीमिरी कोनियरी भा पणिवसी खंड --- 1

चिरीमिरी क्षेत्र

जिला—नरगजा (मध्य प्रदेश)

(रेखांक सं. एम ई सी एल/वी एम पी/जी एम्/(पी एल जी))

नैड / 137 तारीख 23 अगस्त, 94

(पूर्वक्षण के लिए अधिसूचित भूमि वर्णित हुए)

वन भूमि

क्रम संख्या	वन कम्पाटमेंट संख्या	रेज	प्रभाग	क्षेत्र हैक्टर में	टिप्पणियां
1. 536		चिरीमिरी (पराडोल)	(आरक्षित वन) कोरिया	1.53	भाग
2. 537		चिरीमिरी (पराडोल आरक्षित वन)	कोरिया	103.27	भाग
कुल :— : 104.80 हैक्टर (लगभग)					
या 258.96 एकड़ (लगभग)					

सीमा वर्णन :

क—ख—ग—रेखा वन कम्पाटमेंट संख्या 537 में बिन्दु "क" से आरंभ होती है और वन कम्पाटमेंट संख्या 537, 536 में होकर जाती है और बिन्दु "ग" पर मिलती है।

ग—क रेखा वन कम्पाटमेंट संख्या 536, 537 में होकर जाती है, इसके बाद भागन: चिरीमिरी कोनियरी और वन कम्पाटमेंट संख्या 537 की सम्मिलित सीमा के साथ-साथ जाती है और इसके बाद वन कम्पाटमेंट संख्या 537 में होकर आगे बढ़ती है और आरम्भिक बिन्दु "क" पर मिलती है।

[संख्या 13015/21/94--एल एस डब्ल्यू]

नरेन्द्र भगत, निदेशक

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 8th March, 1995

S.O. 879.—Whereas it appears to the Central Government that coal is likely to be obtained from the lands mentioned in the Schedule hereto annexed;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal therein.

The plan bearing No. SECL/BSP/GM(PLG)LAND/137 dated the 23rd August, 1994, of the area covered by this notification can be inspected in the Office of the Collector, Surguja (Madhya Pradesh) or in the Office of the Coal Controller, 1 Council House Street, Calcutta-700001 or in the Office of the South Eastern Coalfields Limited (Revenue Section), Sceptat Road, Bilaspur-495001 (Madhya Pradesh).

All persons interested in the land covered by this notification shall deliver all maps, charts and other documents referred to in sub-section (7) of section 13 of the said Act to the Officer in Charge/Head of the Department (Revenue), South Eastern Coalfields Limited, Sceptat Road, Bilaspur-495001 (Madhya Pradesh) within ninety days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

WEST OF CHIRIMIRI COLLIERY BLOCK I

CHIRIMIRI AREA

DISTRICT SURGUJA (MADHYA PRADESH)

(Plan No. SECL/BSP/GM(PLG)/LAND/137

dated 23rd August, 1994)

(Showing land notified for prospecting)

FOREST LAND I

Sl. No.	Forest compartment number	Range	Division	Area in hectares	Remarks
1. 536		Chirimiri (Paradol Reserved Forest)	Korea	1.53	Part
2. 537		Chirimiri (Paradol Reserved Forest)	Korea	103.27	Part
Total:—				104.80 hectares (approximately) or 258.96 acres (approximately)	

Boundary description :

A-B-C Line starts from point 'A' in forest compartment number 537 and passes through forest compartment numbers 537, 536 and meets at point 'C'.

C-A Line passes through forest compartment numbers 536, 537 then partly along the common boundary

of Chirimiri Colliery and forest compartment number 537, then proceeds through forest compartment number 537 and meets at the starting point 'A'.

[No. 43015/21/94-LSW]

N. BHAGAT, Director.

नई दिल्ली, 8 मार्च, 1995

का. आ. 880.—केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 20) को जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र भाग 2 खंड 3 उपखंड (ii) तारीख 7 मई, 1994 में प्रकाशित भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1062 तारीख 11 अप्रैल, 1994 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की भूमि में जिसका माप 2218-012 हेक्टर (लगभग) या 5480.70 एकड़ लगभग है, कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी;

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त भूमि के भाग में कोयला अभिप्राप्य है।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उनमें संलग्न अनुसूची में वर्णित 218.12 हेक्टर (लगभग) या 5480.70 एकड़ (लगभग) माप की भूमि में खनिजों के खनन बंद करने उनको खूदाई और खोज करने, उन्हें प्राप्त करने, उन पर कार्य करने और उन्हें ले जाने के अधिकारों का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना देती है।

टिप्पणः—1 इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांक सं. एस ई सी एल/बी एस पी/जी एम (पी एन जी) भूमि 135 तारीख 1 अगस्त 1994 का निरीक्षण कलकत्ता बिलासपुर (मध्य प्रदेश) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1 काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता 700 001 के कार्यालय में या साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (राजस्व अनुभाग) सोराठ रोड, बिलासपुर—495 001 (मध्य प्रदेश) के कार्यालय में किया जा सकेगा।

टिप्पण 2:—उक्त अधिनियम की धारा 8 के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिनमें निम्नलिखित उपबंध हैं:—

अर्जन की शक्ति प्राप्तियां

“(3) कोई व्यक्ति जो किसी भूमि में जिसकी बाबत धारा 7 के अधीन अधिसूचना निकाली गई है, हितबद्ध है, अधिसूचना निकाले जाने की तीस दिन के भीतर सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में या उन पर के किन्हीं अधिकारों का अर्जन किए जाने के बारे में आपत्ति कर सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के अर्थानुसार यह आपत्ति नहीं मानी जाएगी कि कोई व्यक्ति किसी भूमि में कोयला उत्पादन के लिए स्वयं खनन संक्रियाएं करना चाहता है और ऐसी संक्रियाएं केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए।

(3) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में की जाएगी और सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को स्वयं सुने जाने का या विधि व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के पश्चात् और ऐसी अनिवार्य जांच यदि कोई हो, करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझता है वह या तो धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित भूमि के या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न टुकड़ों या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में आपत्तियों पर अपनी सिफारिशों और उसके द्वारा की गई कार्यवाई के अभिलेख सहित विभिन्न रिपोर्टें केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए देगा।

(3) इस धारा के प्रायोजन के लिए वह व्यक्ति किसी भूमि में हितबद्ध समझा जाएगा जो प्रतिकर में हित का दावा करने का हकदार होता यदि भूमि या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकार इस अधिनियम के अधीन अर्जन कर लिए जाते हैं।

टिप्पणः—3 केन्द्रीय सरकार ने कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट कलकत्ता पिन-700001 को अधिसूचना का. आ. 905, तारीख 20 मार्च, 1987 द्वारा जो भारत के राजपत्र भाग 2 खंड 3 उपखंड (ii) तारीख 4 अप्रैल, 1987 के पृष्ठ 1397 से 1400 पर प्रकाशित की गई थी उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है।

अनुसूची

राजगमर द्वितीय उत्तर विस्तार ब्लॉक कोरवा कोलफील्ड्स
जिला—बिलासपुर (मध्य प्रदेश)

खनन अधिकार

(अर्जित भूमि के आशय को दर्शाते हुए)

क्रम संख्यांक	ग्राम	पटवारी हल्का संख्यांक	तहसील/रेंज	जिला	क्षेत्र हेक्टर में	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7
6. बेला (जिमका सर्वेक्षण किया गया)		8	कोरवा	बिलासपुर	2100.060	सम्पूर्ण
2. केमला		7	कोरवा	बिलासपुर	24.281	भाग
3. आरक्षित वन कम्पार्टमेंट संख्यांक 505		—	रेंज कोरवा	कोरवा वन प्रभाग कोरवा	71.435	भाग
4. आरक्षित वन कम्पार्टमेंट संख्यांक 595		—	रेंज कोरवा	कोरवा वन प्रभाग कोरवा	22.236	भाग
कुल					2218.012	
					(लगभग) 5480.70	
					एकड़ (लगभग)	

1. बेला ग्राम में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्यांक (सम्पूर्ण) : सर्वेक्षण नहीं किया गया।

2. केमला ग्राम में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्यांक (भाग) : 50 (भाग)।

3. अर्जित किए जाने वाले आरक्षित वन कम्पार्टमेंट संख्यांक : 585 (भाग)।

4. अर्जित किए जाने वाले आरक्षित वन कम्पार्टमेंट संख्यांक : 595 (भाग)।

सीमा वर्णन :-

क—ख रेखा बिन्दु "क" ग्राम बेला, डोनडो, केमला के त्रिजंक्शन बिन्दु से आरम्भ होती है और बेला - डोनडो बेला-मरायपालि की सम्मिलित सीमाओं के साथ-साथ जाती है, और बिन्दु "ख" पर मिलती है।

ख—ग— रेखा ग्राम बेला और आरक्षित वन कम्पार्टमेंट संख्यांक 631 की सम्मिलित सीमा के साथ-साथ जाती है, फिर आरक्षित वन कम्पार्टमेंट संख्यांक 595 से होकर जाती है और बिन्दु "ग" पर मिलती है।

ग—घ रेखा वन कम्पार्टमेंट संख्यांक 585 से होकर जाती है और फिर ग्राम बेला और आरक्षित वन कम्पार्टमेंट संख्यांक 585 बेला तथा पतरापालि की सम्मिलित सीमाओं के साथ-साथ जाती है और बिन्दु "घ" पर मिलती है।

घ—क—रेखा ग्राम बेला और गोरमा, बेला और केमला की सम्मिलित सीमाओं के साथ-साथ जाती है फिर प्लॉट संख्यांक 50 से होकर ग्राम केमला से जाती है और प्रारम्भिक बिन्दु "क" पर मिलती है।

[संख्या 43015/20/93-एल एस डब्ल्यू]

नरेन्द्र भगत, निदेशक

New Delhi, the 8th March, 1995

S.O. 880.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal number S.O. 1062, dated the 11th April, 1994 issued under sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act) and published in Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, dated the 7th May, 1994, the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in 2218.012 hectares (approximately) or 5480.70 acres (approximately) of the lands in the locality specified in the Schedule annexed to that notification;

And, whereas, the Central Government is satisfied that coal is obtainable in a part of the said lands;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby gives notice of its intention to acquire the rights to mine, quarry, bore, dig and search for, win, work and carry away minerals in the lands measuring 2218.012 Hectares (approximately) or 5480.70 acres (approximately) described in the Schedule appended hereto;

Note 1.—The plan bearing No. SECL/BSP/GM(PLG)/LAND/135, dated the 1st August, 1994 of the area covered by this notification may be inspected in the office of the Collector, Bilaspur (Madhya Pradesh) or in the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta-700001 or in the office of the South Eastern Coalfields Limited (Revenue Section), Seepat Road, Bilaspur-495001 (Madhya Pradesh).

Note 2.—Attention is hereby invited to the provisions of section 8 of the said Act, which provides as follows:

Objection to acquisition:

"S(1) Any person interested in any land in respect of which a notification under section 7 has been issued may, within thirty days of the issue of the notification, object to the acquisition of the whole or any part of the land or of any rights in or over such land.

Explanation.—It shall not be an objection within the meaning of this section for any person to say that he himself desires to undertake mining operations in the land for the production of coal and that such operations should not be undertaken by the Central Government or by any other person.

(2) Every objection under sub-section (1) shall be made to the competent authority in writing, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by a legal practitioner and shall, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any as he thinks necessary, either makes a report in respect of the land which has been notified under sub-section (1) of section 7 or of rights in or over such land, or make different reports in respect of different parcels of such land or of rights in or over such land, to the Central Government, containing his recommendations on the objections, together with the record of the proceedings held by him, for the decision of that Government.

(3) For the purpose of this section, a person shall be deemed to be interested in land who would be entitled to claim an interest in compensation if the land or any rights in or over such land were acquired under this Act."

Note 3.—The Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta-700001, has been appointed by the Central Government as the competent authority under section 3 of the said Act, vide notification number S.O. 905, dated the 20th March, 1987, published in Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, dated the 4th April, 1987, at pages 1397 to 1400.

SCHEDULE

RAJGAMAR 2ND NORTH EXTENSION BLOCK
KORBA COALFIELD
DISTRICT BILASPUR (MADHYA PRADESH)

(Showing intention to acquire lands)

MINING RIGHTS

Sl. No.	Village	Patwari Halka number	Tahsil/Range	District	Area in hectares	Remarks
1.	Bela (unsurveyed)	8	Korba	Bilaspur	2100.060	Full
2.	Kesla	7	Korba	Bilaspur	24.281	Part
3.	Reserved forest compartment number 585	—	Range	Korba forest division	71.435	Part
4.	Reserved forest compartment number 595	—	Range	Korba forest division	22.236	Part
				Korba	Korba	
Total:—					2218.012 hectares (approximately) or 5480.70 acres (approximately)	

1. Plot numbers to be acquired in village Bela (Full): Unsurveyed.	B-C Line passes along the common boundary of village Bela and Reserved forest compartment number 631,
2. Plot number to be acquired in village Kesla (Part): 50 (part).	then through Reserved forest compartment number 595 and meets at point 'C'.
3. Reserved forest compartment number to be acquired: 585 (part).	C-D Line passes through forest compartment number 585 then along the common boundaries of village Bela and Reserved forest compartment number 585, Bela and Patrapali and meets at point 'D'.
4. Reserved forest compartment number to be acquired: 595 (part).	D-A Line passes along the common boundaries of villages Bela and Gorma, Bela and Kesla, then through village Kesla through plot number 50 and meets at the starting point 'A'.
Boundary description :	
A-B Line starts from point 'A' on the trijunction point of villages Bela Dondro, Kesla and passes along the common boundaries of villages Bela-Dondro, Bela-Saraipali and meets at point 'B'.	

[No. 43015/20/93-LSW]
N. BHAGAT, Director

नई दिल्ली, 8 मार्च, 1995

का.आ. 881.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में उल्लिखित भूमि में कोयला अभि-
प्राप्त किए जाने की संभावना है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस क्षेत्र में कोयले का पूर्वोक्त करने के अपने आशय की सूचना देती है—

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांक सं. एस. ई. सी.एल./बी.एस.पी./जी.एम. (पी.एल.जी.)/लैण्ड/136, तारीख 17 अगस्त 1994 का निरीक्षण कलक्टर, बिलासपुर (मध्य प्रदेश) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता-700 001 के कार्यालय में या साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (राजस्व अनुभाग) सीपत रोड, बिलासपुर-745 001 (मध्य प्रदेश) के कार्यालय में किया जा सकता है।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाले भूमि में हितबद्ध सभी व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) में निर्दिष्ट सभी नक्शों, चार्टों और अन्य दस्तावेजों को, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर, भारसाधक अधिकारी/विभागाध्यक्ष (राजस्व), साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि., सीपत रोड, बिलासपुर-495 001 (मध्य प्रदेश) को भेजेंगे।

अनुसूची

करताली खंड

कोरबा कोलफील्ड्स

जिल — बिलासपुर (मध्य प्रदेश)

रेखांक सं. एस. ई. सी.एल./बी.एस.पी./जी.एम. (पी.एल.जी.)/लैण्ड/136, तारीख 17 अगस्त, 1997 (पूर्वोक्त के लिए अधि-
सूचित भूमि को दर्शाते हुए)।

क्र. सं.	ग्राम का नाम	पटवारी हल्का संख्यांक	तहसील	जिला	हेक्टर में क्षेत्र	टिप्पणियां
1.	डोमिया	25	कटघोरा	बिलासपुर	456.228	पूर्ण
2.	डोंगानाला	26	कटघोरा	बिलासपुर	445.302	पूर्ण
3.	गणेशपुर (असर्वोक्षित)	26	कटघोरा	बिलासपुर	171.738	पूर्ण
4.	करताला	26	कटघोरा	बिलासपुर	1310.274	पूर्ण
5.	तेंदुभाठा	26	कटघोरा	बिलासपुर	154.131	पूर्ण
कुल					2537.673	हेक्टर लगभग
					या	
					6270.59	एकड़ लगभग

सीमा वर्णन :

क-ख रेखा ग्राम करताला, पुता और वन के त्रिविंदु पर बिंदु "क" से आरंभ होती है और ग्राम करताला, गणेशपुर, डोंगानाला की दक्षिणी सीमाओं के साथ-साथ आगे बढ़ती है तथा बिंदु "ख" पर मिलती है।

- ख-ग रेखा ग्राम डोंगानाला, डोपिया की पश्चिमी सीमाओं के साथ-साथ जाती है और बिंदु "ग" पर मिलती है।
 ग-घ रेखा ग्राम डोमिया, तेंदुभाठा, करताला की उत्तरी सीमाओं के साथ-साथ जाती है और बिंदु "घ" पर मिलती है।
 घ-क रेखा ग्राम करताला की पूर्वी सीमा के साथ-साथ जाती है और आरम्भिक बिंदु "क" पर मिलती है।

[संख्या : 43015/19/94-एल.एस.डब्ल्यू]

नरेन्द्र भगत, निदेशक

New Delhi, the 8th March, 1995

S.O. 881.—Whereas it appears to the Central Government that coal is likely to be obtained from the lands mentioned in the Schedule hereto annexed;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development), Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal therein.

The plan bearing No. SECL/BSP/GM(PLG)/Land/136 dated the 17th August, 1994, of the area covered by this notification can be inspected in the Office of the Collector, Bilaspur (Madhya Pradesh) or in the Office of the Coal Controller, 1 Council House Street, Calcutta-700001 or in the Office of the South Eastern Coalfields Limited (Revenue Section), Seepat Road, Bilaspur-495001 (Madhya Pradesh).

All persons interested in the land covered by this notification shall deliver all maps, charts and other documents referred to in sub-section (7) of section 13 of the said Act to the Officer-in-Charge/Head of the Department (Revenue), South Eastern Coalfields Limited, Seepat Road, Bilaspur-495001 (Madhya Pradesh) within ninety days from the date of publication of this notification in the Official Gazette

SCHEDULE

KARTALI BLOCK

DISTRICT BILASPUR (MADHYA PRADESH)

KORBA COALFIELDS

Plan No. SECL/BSP/GM(Plg)/Land/136
 dated the 17th August, 1994
 (Showing land notified for
 prospecting)

Sl. No.	Name of village	Patwari Halka Number	Tehsil	District	Area in Hactare	Remarks
1.	Domia	26	Katghora	Bilaspur	456.228	Full
2.	Donganala	26	Katghora	Bilaspur	445.302	Full
3.	Ganeshwpur (Unsurveyed)	26	Katghora	Bilaspur	171.738	Full
4.	Kartala	26	Katghora	Bilaspur	1310.275	Full
5.	Tandubhatha	26	Katghora	Bilaspur	154.131	Full
Total					2537.673 hactares (approximately)	
					Or	
					6270.59 acres (approximately)	

Boundary description :

A-B Line starts from 'A' on the trijunction of villages Kartala, Puta and Forest and proceeds along the southern boundaries of villages Kartala, Ganeshpur and Donganala and meets at point 'B'.

B-C Line passes along the western boundaries of villages Donganala and Domia and meets at point 'C'.

C-D Line passes along the northern boundaries of villages Domia, Tendubhatha and Kartala and meets at point 'D'.

D-A Line passes along the eastern boundary of village Kartala and meets at the starting point 'A'.

[No. 43015/19/94-LSW]

N. BHAGAT, Director

नई दिल्ली, 10 मार्च, 1995

क्र. आ. 882.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में उल्लिखित भूमि में कोयला अभि-प्राप्त किए जाने की संभावना है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियाँ का प्रयोग करते हुए, उस क्षेत्र में कोयले की पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना देता है।

इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांक सं. एस. ई. सी. एल./बी.एस.पी./जी.एम. (पी.एल.जी.)/भूमि/143, तारीख 4 जनवरी, 1995 का निरीक्षण कलक्टर, बिलासपुर (मध्य प्रदेश) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, काउमिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता-700 001 के कार्यालय में या साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (राजस्व अनुभाग), सीपत रोड, बिलासपुर-495001 (मध्य प्रदेश) के कार्यालय में किया जा सकता है।

इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाली भूमि में हितबद्ध सभी व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) में निर्दिष्ट सभी तथ्यों, चार्टों, और अन्य दस्तावेजों को, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के नव्वे दिन के भीतर, भारसाधक अधिकारी/विभागाध्यक्ष (राजस्व), साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सीपत रोड, बिलासपुर-495001 (मध्य प्रदेश)

अनुसूची

विजय खंड

मेदुरगढ़ कोयला क्षेत्र

जिला—बिलासपुर (मध्य प्रदेश)

चिरीमिटरी क्षेत्र

रेखांक सं. एम.ई.सी.एल./बी.एस.पी./जी.एम.

(पी.एल.जी.)/भूमि/143, तारीख 4 जनवरी, 1995

(पूर्वेक्षण के लिए अधिसूचित भूमि दर्शाते हुए)

वन भूमि

क्र.सं.	वन कंपार्टमेंट संख्या	रेंज	प्रभाग	क्षेत्र हेक्टेयर में	टिप्पणियाँ
1.	190	पसान	बिलासपुर	3.238	भाग
2.	191	पसान	बिलासपुर	74.463	भाग
3.	192	पसान	बिलासपुर	191.014	भाग
4.	193	पसान	बिलासपुर	340.587	भाग
5.	194	पसान	बिलासपुर	428.876	संपूर्ण
6.	195	पसान	बिलासपुर	286.197	भाग
7.	198	पसान	बिलासपुर	196.194	भाग
8.	199	पसान	बिलासपुर	306.269	भाग
9.	200	पसान	बिलासपुर	354.430	संपूर्ण
10.	204	पसान	बिलासपुर	164.466	भाग
11.	205	पसान	बिलासपुर	371.020	भाग
योग :				2716.754 हेक्टेयर	(लगभग)

अनुसूची-आरी

राजस्व भूमि

क्र.सं.	ग्राम का नाम	पटवारी हल्का सं.	तहसील	जिला	क्षेत्र हैक्टर में	टिप्पणियाँ
1.	रानी-अटारी (असर्वेक्षित)	7	कटघोरा	बिलासपुर	45.973	संपूर्ण
2.	कन्डई	7	कटघोरा	बिलासपुर	76.405	संपूर्ण
3.	बीजडाण्ड (असर्वेक्षित)	7	कटघोरा	बिलासपुर	93.	संपूर्ण
4.	मुखनहरा	7	कटघोरा	बिलासपुर	38.203	भाग
5.	फुटीपखना (असर्वेक्षित)	7	कटघोरा	बिलासपुर	91.248	भाग
6.	तनेरा	7	कटघोरा	बिलासपुर	235.044	भाग
योग					580.164 हैक्टर (लगभग)	

कुल योग-2716.7545+80.164-3296.918 हैक्टर (लगभग)

या

8146.68 एकड़ (लगभग)

सीमा वर्णन :

क-ख-ग-घ रेखा वन कंपार्टमेंट सं. 192 में बिंदु 'क' से आरंभ होनी है और वन कंपार्टमेंट सं. 192, 190, 191, 195, 198, 199 में होकर जाती है, फिर ग्राम तनेरा में होकर जाती है और बिंदु "घ" पर मिलती है।

घ-ङ रेखा ग्राम तनेरा से होकर जाती है, फिर वन कंपार्टमेंट संख्यांक 205, 204 में होकर जाती है और बिंदु "ङ" पर मिलती है।

ङ-च-छ रेखा वन कंपार्टमेंट संख्यांक 204 में होकर जाती है, फिर ग्राम मुखनहरा से होकर जाती है और बिंदु "छ" पर ग्राम मुखनहरा तथा वन कंपार्टमेंट संख्यांक 200 की सम्मिलित सीमा पर मिलती है।

छ-ज-झ रेखा ग्राम मुखनहरा, फुटीपखना से होकर जाती है, फिर

ज-ट-ड वन कंपार्टमेंट संख्यांक 193, 192 से होकर जाती है और आरंभिक बिंदु 'क' पर मिलती है।

ड-क-

[सं. 43015/2/95-गल.एम.डब्ल्यू]

नरेन्द्र भगत, निदेशक,

New Delhi, the 10th March, 1995

S.O. 882.—Whereas it appears to the Central Government that coal is likely to be obtained from the lands mentioned in the Schedule hereto annexed;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development), Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal therein.

The plan bearing No. SECL/BSP/GM(PIG) Land/143 dated the 4th January, 1995, of the area covered by this notification can be inspected in the Office of the Collector, Bilaspur (Madhya Pradesh) or in the Office of the Coal Controller, 1 Council House Street, Calcutta-700001 or in the Office of the South Eastern Coalfields Limited (Revenue Section) Seepat Road, Bilaspur-491001 (Madhya Pradesh).

All persons interested in the land covered by this notification shall deliver all maps, charts and other documents referred to in sub-section (7) of section 13 of the said Act

to the Officer in Charge/Head of the Department (Revenue),
South Eastern Coalfields Limited, Seepat Road, Bilaspur-

498001 (Madhya Pradesh) within ninety days from the date
of publication of this notification in the Official Gazette

SCHEDULE
VIJAY BLOCK
SENDURGARH COALFIELD
DISTRICT-BILASPUR (MADHYA PRADESH)
CHIRIMIRI AREA

Plan No. SECL/BSP/GM(PLG)/Land/143

dated 4th January, 1995.

(showing land notified for prospecting).

FOREST LAND

Serial number	Forest Compartment number	Range	Division	Area in hectares	Remarks
1.	190	Pasan	Bilaspur	3.238	Part
2.	191	Pasan	Bilaspur	74.463	Part
3.	192	Pasan	Bilaspur	191.014	Part
4.	193	Pasan	Bilaspur	340.587	Part
5.	194	Pasan	Bilaspur	428.876	Full
6.	195	Pasan	Bilaspur	286.197	Part
7.	198	Pasan	Bilaspur	196.194	Part
8.	199	Pasan	Bilaspur	306.269	Part
9.	200	Pasan	Bilaspur	354.430	Full
10.	204	Pasan	Bilaspur	164.466	Part
11.	205	Pasan	Bilaspur	371.020	Part

Total: 2716.754 Hectares
(approximately)

SCHEDULE

REVENUE LAND

Serial No.	Name of Village	Patwari Halka number	Tahsil	District	Area in hectares	Remarks
1.	Rani Atari	7	Katghora	Bilaspur	45.973	Full
	Unsurveyed.					
2.	Kandai	7	Katghora	Bilaspur	76.405	Full
3.	Bijadand	7	Katghora	Bilaspur	93.241	Full
	Unsurveyed.					
4.	Sukhabahara	7	Katghora	Bilaspur	38.203	Part
5.	Putipakhana	7	Katghora	Bilaspur	91.298	Part
	(Unsurveyed.					
6.	Tanera	7	Katghora	Bilaspur	235.044	Part
Total					580.164 Hectares	(approximately)

Grand Total) = 2716.754 + 580.164 = 3296.918 Hectares (approximately)

or
8146.68 Acres (approximately)

Boundary description :

A-B-C-D Line starts from point 'A' in Forest Compartment number 192 and passes through Forest Compartment numbers 192, 190, 191, 195, 198, 199 then through village Tanera and meets at point 'D'

D-E Line passes through village Tanera, then through Forest Compartment numbers 205, 204 and meets at point 'E'.

E-F-G Line passes through Forest Compartment number 204, then through village Sukhabahara and

meets on the common boundaries of village Sukhabahara and Forest Compartment number 200 at point 'G'.

G-H-I-

J-K-L-

M-A

Line passes through villages Sukhabahara, Putipakhana, then through Forest Compartment numbers 193, 192 and meets at the starting point 'A'.

[No. 43015/2/95-LSW]

N. BHAGAT, Director

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग)

नई दिल्ली, 10 मार्च, 1995

का. घा. 883 यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में दहेज-गंधार से बढौदा तक पेट्रोकेमिकल्स उत्पाद के परिवहन के लिए पाइप लाइन इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी ज़मीनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध भूमि में अगित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोकेमिकल्स और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) को धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आणख एतद्वारा घोषित किया है।

बगलें कि उक्त भूमि में दितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आशेष सक्षम प्राधिकारी, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लि., इण्डियन म्यूनिपैलिटी, मयाजीगंज, बरोदा को 8 म अघिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आशेष करने वाला हर व्यक्ति निनिदिष्टता यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी मूखवर्दि व्यक्तिगत हो या किंगी बिधि व्यवसयी की मखन।

अनुसूची

पेट्रोकेमिकल्स के परिवहन के लिए पाइपलाइन दहेज-गंधार से बढौदा तक इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लि. बढौदा

राज्य : गुजरात जिला : बढौदा तालुका : पादरा

संख्या	सर्वेक्षण संख्या वार्ड संख्या	हेक्टर	क्षेत्रफल एकर	सेन्टीयर
1	2	3/1	3/2	3/3
पबलजारा	610	00	02	08
"	616	00	07	76
"	बोरसद-अणुसर रोड	00	08	00
"	617	00	01	30
"	601	00	00	36
"	600	00	05	20
"	599	00	09	30
"	596	00	23	32
"	598	00	00	08
"	597	00	06	10
"	595	00	00	45
"	काटे ट्रैक	00	02	90
"	542	00	17	80
"	543	00	03	80
"	545	00	18	31
"	546	00	01	42
"	549	00	09	70
"	547	00	14	40
"	548	00	16	30
"	काटे ट्रैक	00	01	90
"	469	00	04	40

1	2	3/1	3/2	3/3
पबलजारा-जारा	468	00	20	95
"	464	00	13	90
"	463	00	02	09
"	462	00	01	75
"	558	00	24	04
"	241	00	10	60
"	242	00	11	20
"	पबलजारा-हमासा	00	01	20
"	रोड			
"	236	00	13	70
"	235	00	10	15
"	नासा	00	02	95
"	79	00	18	00
"	87	00	00	76
"	81	00	04	60
"	82	00	04	90
"	83	00	04	60
"	84	00	02	50
"	85	00	00	70
"	80	00	12	05
"	काटे ट्रैक	00	02	00
"	93	00	14	27
"	ट्रेडिंग	00	03	00
"	94	00	07	85
"	96	00	26	00
"	97	00	10	20
"	98	00	07	85
"	104	00	06	89
"	99	00	06	99
"	103	00	06	12
"	122	00	18	50
"	123	00	19	20
"	काटे ट्रैक	00	05	04
"	125	00	03	74
"	124	00	12	60

[सं. 45011/1/94-मूएसपीसी]
धर्मपाल गोयल, अवर सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS
(Department of Chemicals and Petrochemicals)

New Delhi, the 10th March, 1995

S.O. 883.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum products from Dahej-Gandhar to Baroda, Via, GAIL Complex in Gujarat State pipeline should be laid by the Indian Petrochemicals Corporation Ltd.

And, whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent

Authority, Indian Petrochemicals Corporation Ltd., Gandhar Complex, 7th Floor, Hotel Surya Palace, Sayajigunj, Vadodara-5.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Petroleum pipeline from Dahej-Gandhar To Baroda
Indian Petrochemicals Corporation Ltd., Vadodara
State—Gujarat District—Baroda —Taluka— Padra

Village	Sr. No. Block No.	Area		
		Hac- tare	Are cent-	Cent-
1	2	3/1	3/2	3/3
Ekalbara	615	00	02	08
	616	00	07	76
Borsad-Jambusar Road		00	08	00
	617	00	01	80
	601	00	00	30
	600	00	05	20
	599	00	07	30
	576	00	23	32
	598	00	00	08
	597	00	06	10
	595	00	00	45
Cart Track		00	02	90
	542	00	17	80
	543	00	03	80
	545	00	16	31
	546	00	01	42
	549	00	09	70
	547	00	14	40
	548	00	16	30
Cart Track		00	01	20
	467	00	04	40
	468	00	20	95
	464	00	13	90
	463	00	02	09
	462	00	01	75
	558	00	24	04
	241	00	10	60
	242	00	11	20
Ekalbara-Dabhasa Road		00	04	20
	236	00	15	70
	235	00	10	15
	Nalla	00	02	95
	79	00	18	00
	87	00	00	76
	81	00	04	60
	82	00	04	90
	83	00	04	60
	84	00	02	50
	85	00	00	70
	80	00	12	05
Cart Track		00	02	00
	93	00	14	27
Drain		00	03	00
	94	00	07	85
	76	00	26	00
	97	00	10	20
	98	00	07	85

1	2	3/1	3/2	3/3
	104	00	06	89
	99	00	06	99
	103	00	06	12
	122	00	18	50
	123	00	19	20
Cart Track		00	05	03
	125	00	03	74
	124	00	12	60

[No. 45011/1/74-US (PC)]
D.P. GOEL, Under Secy.

नई दिल्ली, 10 मार्च, 1995

का.आ. सं. 884 यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में दहेज-संधार से बड़ोदा तक पेट्रोलियम उत्पाव के परिवहन के लिए पाइपलाइन इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः सब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) का धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

वर्तते कि उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आशेष भक्षम प्राधिकारी इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लि. होटल सूर्याक्षेप मयाजीगंज बड़ोदा को इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आशेष करने वाला हर व्यक्ति विनिश्चितता यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी मन्वाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवस्थाओं को मार्कन।

अनुसूची

पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन दहेज-संधार से बड़ोदा तक

इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लि. बड़ोदा

राज्य : गुजरात जिला - बड़ोदा भाग : का.आ. पाद-

गांव	संरक्षण संख्या खंड	क्षेत्रफल सेंटीमीटर	संख्या	हेक्टर
1	2	3/1	3/2	3/3
उमराया	376	00	19	75
	377/	00	03	15
	388	88	12	50
	389	00	12	95
	386	00	00	35
	398/अ	00	27	10
	155	00	26	90
	403	00	03	52
	430	00	01	30

SCHEDULE

1	2	3/1	3/2	3/3
उमराया	429	00	17	90
"	428/बी	00	12	60
"	427	00	05	51
"	426	00	01	95
"	डभासा-उमराया	00	02	00
"	इन्डियन पी एम रोड			
"	288	00	01	92
"	289	00	19	98
"	287	00	12	80
"	295	00	21	15
"	294	00	03	05
"	650	00	09	95
"	651	00	17	30
"	656	00	06	10
"	659/बी	00	05	50
"	659/ए	00	10	00
"	676	00	11	00
"	677/ए	00	04	60
"	कार्ट ट्रैक	00	01	35
"	760	00	03	04
"	758	00	09	50
"	757	00	09	20
"	756	00	04	40
"	755	00	04	80
"	709	00	15	65
"	710	00	10	60

[सं. 45011/1/94/यूपएस (पीसी)]
धर्मपाल गोयल, अवर सचिव

New Delhi, the 10th March, 1995

S.O. 884.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum products from DAHEJ-GANDHAR to BARODA, VIA GAIL COMPLEX in Gujarat State pipeline should be laid by the Indian Petrochemicals Corporation Ltd.

And, whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Indian Petrochemicals Corporation Ltd., Gandhar Complex, 7th Floor, Hotel Surya Palace, Sayajigunj, Vadodara-5.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

Petroleum pipeline from Dahej—Gandhar To Baroda
Indian Petrochemicals Corporation Ltd., Vadodara
State—Gujarat District—Baroda Taluka—Padra

Village	Sr. No. Block No.	Area		
		Hec-tare	Are	Cent-tare
1	2	3/1	3/2	3/3
Umaraya	376	00	19	75
	377/A	00	03	15
	388	00	12	50
	389	00	12	95
	386	00	00	35
	398/A	00	27	10
	155	00	26	90
	403	00	05	52
	430	00	01	30
	429	00	17	90
	428/B	00	12	60
	427	00	05	51
	426	00	01	95
	Dabhasa-Umaraya	00	02	00
	WBM Road			
	288	00	01	92
	289	00	19	98
	287	00	12	80
	295	00	21	15
	294	00	03	05
	650	00	09	95
	651	00	17	30
	656	00	06	10
	659/B	00	05	50
	659/A	00	10	00
	676	00	11	00
	677/A	00	04	60
	Cart Track	00	01	35
	760	00	03	04
	758	00	09	50
	757	00	09	20
	756	00	04	40
	755	00	04	80
	709	00	15	65
	710	00	10	60

[No. 45011/1/94-US (PC)]
D.P. GOEL, Under Secy.

नई दिल्ली, 10 मार्च, 1995

का.भा.सं. 885 यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में दहेज-गंधार से बड़ोदा तक पेट्रोलेियम उत्पाद के परिवहन के लिए पाएप लाइन इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतपाबद्ध भूखंडों में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलेियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

वशात् कि उपर्युक्त भूमि में हितवन्त कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सहित प्राधिकारी, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लि., होटल सूर्यापलस, सयाजीगंज, बड़ोदरा को इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिश्चितता यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

पेट्रोलेियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन वहेज-गंधार से बड़ोदरा तक
इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लि. बड़ोदरा

राज्य : गुजरात	जिला : बड़ोदरा	तालुका : पादरा
गांव	सर्वेक्षण संख्या खंड संख्या	हैक्टर क्षेत्रफल सेंटी एयर एयर
1	2	3/1 3/2 3/3
भुणा	380	00 15 50
"	381	00 11 95
"	402	00 25 70
"	430	00 31 90
"	कार्ट ट्रैक	00 01 80
"	446	00 15 95
"	439	00 26 95
"	444	00 03 60
"	442	00 03 00
"	441	00 12 65
"	440	00 11 55
"	507	00 07 35
"	508	00 11 70
"	512	00 10 60
"	520	00 19 90
"	518	00 12 40
"	531	00 01 05
"	533	00 00 84
"	532	00 14 56
"	534	00 00 14
"	539	00 03 36
"	540	00 06 85
"	544	00 07 05
"	543	00 02 55
"	नामा	00 00 80
"	568	00 24 50
"	570	00 07 00

New Delhi, the 10th March, 1995

S.O. 885.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum products from DAHEJ-GANDHAR to BARODA, VIA GAIL COMPLEX in Gujarat State pipeline should be laid by the Indian Petrochemicals Corporation Ltd.

And, whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Indian Petrochemicals Corporation Ltd., Gandhar Complex, 7th Floor, Hotel Surya Palace, Sayajigunj, Vadodara-5.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Petroleum pipeline from Dahej—Gandhar To Baroda
Indian Petrochemicals Corporation Ltd., Vadodara
State—Gujarat District—Baroda Taluka—Padra

Village	Sr. No. Block No.	Area
		Hec- tare Arc- cent- tare
1	2	3/1 3/2 3/3
Luna	380	00 15 50
	381	00 11 95
	402	00 25 70
	430	00 31 90
	Cart Track	00 01 80
	446	00 15 95
	439	00 26 95
	444	00 03 60
	442	00 03 00
	441	00 12 65
	440	00 11 55
	507	00 07 35
	508	00 11 70
	512	00 10 60
	520	00 19 90
	518	00 12 40
	531	00 01 05
	533	00 00 84
	532	00 14 56
	534	00 00 14
	539	00 03 36
	540	00 06 85
	544	00 07 05
	543	00 02 55
	Nalla	00 00 80
	568	00 24 50
	570	00 07 00

[सं. 45011/1/94-यूएस(पीसी)]

धर्मपाल गोयल, अवर सचिव

[No. 45011/1/94-US(PC)]

D.P. GOEL, Under Secy.

नई दिल्ली, 10 मार्च, 1995

का.आ. 886—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में दहेज-गंधार से बड़ोदा तक पेट्रोलेियम उत्पाद के परिवहन के लिए पाइपलाइन इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लि. द्वारा बिछाई जाना चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी साइटों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलेियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

बतर्क कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के सीधे पाइप लाइन बिछाने के लिए आशेष सक्षम प्राधिकारी, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लि., होटल स्युप्लियस, मयाजीगंज, बड़ोदा को इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आशेष करने वाला हर व्यक्ति विनिश्चितता यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

पेट्रोलेियम के परिवहन के निम्ने पाइपलाइन दहेज-गंधार से बड़ोदा तक इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लि. बड़ोदा

राज्य—गुजरात जिला—बड़ोदा तालुका—पादरा

गांव	सर्वेक्षण संख्या खंड संख्या	हेक्टर	अंशफल सेन्टीग्रेडर ग्रेडर	
1	2	3/1	3/2	3/3
जासपुर	कार्टे ट्रेक	00	02	10
"	669	00	01	20
"	664	00	39	35
"	659	00	19	75
"	660	00	03	37
"	654	00	06	90
"	643	00	00	12
"	655	00	11	60
"	644	00	22	22
"	645	00	10	60
"	646	00	12	00
"	631	00	20	60
"	633	00	00	40
"	635	00	21	00
"	630	00	24	20
"	621	00	11	80
"	623	00	21	30
"	610	00	07	00
"	611	00	15	24
"	612	00	01	60
"	614	00	11	30

1	2	3/1	3/2	3/3
जासपुर	613	00	18	35
"	602	00	11	00
"	601	00	20	80
"	597	00	21	30
"	584	00	13	75
"	585	00	07	95
"	जासपुर-पादरा	00	04	00
रोड				
"	554	00	45	00
"	540	00	12	62
"	553	00	02	58
"	545	00	35	00
"	कार्टे ट्रेक	00	02	00
"	504	00	09	60
"	523	00	00	14
"	505	00	10	56
"	506	00	14	30
"	507	00	14	90
"	518	00	17	30
"	517	00	15	10
"	जासपुर-नकईकुई	00	04	05
रोड				
"	212	00	05	55
"	213	00	04	30
"	214	00	11	40
"	215	00	18	20
"	216	00	11	40
"	217	00	13	45
"	कार्टे ट्रेक	00	01	25
"	296	00	24	50
"	कार्टे ट्रेक	00	01	25
"	268	00	00	95
"	270	00	09	30
"	271	00	11	90
"	272	00	04	40
"	273	00	19	25
"	274	00	04	45
"	275	00	10	05

[नं. 15011/1/94-यू.एस (पी.सी.)]

धर्मपाल गोयल, अव्वर सचिव

New Delhi, the 10th March, 1995

S.O. 886.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum products from DAHEJ-GANDHAR to BARODA, VIA GAIL COMPLEX in Gujarat State pipeline should be laid by the Indian Petrochemicals Corporation Ltd.

And, whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent

Authority, Indian Petrochemicals Corporation Ltd., Gandhar Complex, 7th Floor, Hotel Surya Palace, Sayajigunj, Vadodra-5.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Petroleum pipeline from Dahej—Gandhar To Baroda
Indian Petrochemicals Corporation Ltd., Vadodra
State—Gujarat District—Baroda Taluka—Padra

Village	Sr. No. Block No.	Area		
		Hec- tare	Are	Cent- tare
1	2	3/1	3/2	3/3
Jaspur	Cart Track	00	02	10
	669	00	01	20
	664	00	39	35
	659	00	19	75
	660	00	03	37
	654	00	06	90
	643	00	00	12
	655	00	11	60
	644	00	22	22
	645	00	10	60
	646	00	12	00
	634	00	20	60
	633	00	00	40
	635	00	21	00
	630	00	24	20
	621	00	11	80
	623	00	21	30
	610	00	07	00
	611	00	15	24
	612	00	01	60
	614	00	11	35
	618	00	18	35
	602	00	11	00
	601	00	20	80
	597	00	21	30
	584	00	13	75
	585	00	07	95
	Jaspur-Padra Road	00	04	00
	554	00	45	00
	540	00	12	62
	553	00	02	58
	545	00	35	00
	Cart Track	00	02	00
	504	00	09	60
	523	00	00	14
	505	00	10	56
	506	00	14	30
	507	00	14	90
	528	00	17	30
Jaspur	517	00	15	10
	Jaspur-Lakdikui Road	00	04	05
	212	00	05	55
	213	00	04	30
	214	00	11	40
	215	00	18	20
	216	00	11	40
	217	00	13	45
	Cart Track	00	01	25

1	2	3/1	3/2	3/3
	296	03	24	50
	Cart Track	03	01	25
	268	00	00	95
	270	00	09	30
	271	00	11	90
	272	00	04	40
	273	00	19	25
	274	03	04	45
	275	00	10	05

[No. 45011/1/94—US(PC)]

D.P. GOEL, Under Secy.

नई दिल्ली, 10 मार्च, 1995

का.प्र. 887 --यस केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में दहेज-गंधार में बड़ीदा तक पेट्रोलेियम उत्पाद के परिवहन के लिए पाइपलाइन इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी स्थितियों का निवारण के प्रयोजन के लिए एनएचआर अधिनियम में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलेियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम, 1962 (1962 का 50) का धारा 3 का उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना भार एनएचआर अधिनियम द्वारा किया है।

अतः कि उक्त भूमि में हित रखने वाले व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आश्रय सक्षम प्राधिकारी, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि., होटल सुपाईनेस, सयाजीगंज, बड़ोदरा को इस अधिनियम का सारोख के 21 बलों के अंतर्गत कर मकेगा।

और ऐसा आश्रय कराने वाला हर व्यक्ति विनिश्चितता यह भी करने का कि क्या वह चाहता है कि उसकी मृतवादी व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

पेट्रोलेियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन दहेज-गंधार में बड़ीदा तक इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि. बड़ोदरा

राज्य—गुजरात	जिला—बड़ोदरा	तालुका—बड़ोदरा
गांव	सर्वेक्षण संख्या खंड संख्या	क्षेत्रफल हेक्टर एकर सेन्टीएकर
1	2	3/1 3/2 3/3
अपाठ	286	00 19 00
"	287	00 08 60
"	288	00 00 02
"	285	00 00 38
"	290	00 13 40
"	291	00 09 10
"	292	00 20 35
"	कार्ड टुक	00 03 45
"	233/पी	00 00 30
"	कार्ड टुक	00 01 40

1	2	3/1	3/2	3/3
अपाद---(अ.री)	296	00	21	02
"	295	00	14	30
"	298/ए एण्ड बी	00	21	28
"	304	00	09	22
"	305	00	10	60
"	कार्ट ट्रैक	00	01	80
"	317	00	05	61
"	307/ए एण्ड बी	00	34	29
"	कार्ट ट्रैक	00	01	00
"	309	00	20	60
"	कार्ट ट्रैक	00	00	60
"	191	00	19	10
"	190	00	10	90
"	189	00	12	80
"	156	00	07	50
"	188	00	15	10
"	187	00	01	00
"	186	00	10	60
"	185	00	18	05
"	166	00	06	52
"	129	00	13	46
"	165	00	10	85
"	161	00	08	47
"	127	00	08	60
"	128	00	17	00
"	126	00	02	81
"	कार्ट ट्रैक	00	01	85
"	97	00	11	35
"	98	00	10	05
"	96	00	08	96
"	94	00	02	40
"	100	00	20	50
"	78	00	17	00
"	102	00	13	10
"	103	00	08	85
"	104/ए	00	15	15

[सं 45011/1/94-यू.एम.(पी.सी.)]

शर्मपाल गोयल, अवर सचिव

New Delhi, the 10th March, 1995

S.O. 887.--Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum products from DAHEJ-GANDHAR to BARODA, VIA GAIL COMPLEX in Gujarat State pipeline should be laid by the Indian Petrochemicals Corporation Ltd.

And, whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Indian Petrochemicals Corporation Ltd., Gandhar Complex, 7th Floor, Hotel Surya Palace, Sayajigunj, Vadodara-5.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Petroleum pipeline from Dahej—Gandhar To Baroda
Indian Petrochemicals Corporation Ltd, Vadodara
State—Gujarat District—Baroda Taluka—Baroda

Village	Sr. No.	Block No.	Area		
			Hac-	Are	Cent-
			ture	cent	are
1	2	3/1	3/2	3/3	
Ampad	285	00	19	00	
	287	00	08	60	
	288	00	00	02	
	285	00	00	38	
	290	00	13	40	
	291	00	09	10	
	292	00	20	35	
	Cart Track	00	03	45	
	293/P	00	00	30	
	Car. Track	00	01	40	
	296	00	21	02	
	295	00	14	30	
	298/A&B	00	21	28	
	304	00	09	22	
	305	00	10	60	
	Cart Track	00	01	80	
	317	00	05	61	
	307/A&B	00	34	29	
	Car. Track	00	01	00	
	309	00	20	60	
	Cart Track	00	00	60	
	191	00	19	10	
	190	00	10	90	
	189	00	12	80	
	156	00	07	50	
	188	00	15	10	
	187	00	01	00	
	186	00	10	60	
	185	00	18	05	
	166	00	06	52	
	129	00	13	46	
	165	00	10	85	
	161	00	08	47	
	127	00	08	60	
	128	00	17	00	
	126	00	02	81	
	Cart Track	00	01	85	
	97	00	11	35	
	98	00	10	05	
	96	00	08	96	
	94	00	02	40	
	100	00	20	50	
	78	00	17	00	
	102	00	13	10	
	103	00	08	85	
	104/A	00	15	15	

[No. 45011/1/94--US(PC)]

D.P. GOEL, Under Secy.

नई दिल्ली, 10 मार्च, 1995

का आ 886 ---यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में दहेज-संधा से बड़ीदा तक पेट्रोसियम उत्पाद के परिवहन के लिए, पाइपलाइन इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी माहनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाय अतिसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोसियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आग्रह एतद्वारा जोषित किया है।

बलपूर्वक कि उपर भूमि में हितवश कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सधम प्राधिकारी, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि, होटल सूर्यप्रीतम, सयाजीगंज, बड़ीदा को इस अतिमूर्खता की साख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति बिनिदिष्टता यह भी कथन करेगा कि यथा वह यह सातता है कि उसकी मूलवादी व्यक्तिगत हो या किसी बिधि व्यवसायी की बाकत।

अतिसूची

पेट्रोसियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन दहेज-संधार से बड़ीदा तक इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि, बड़ीदा

राज्य—गुजरात	जिला—बड़ीदा	भांका—बड़ीदा			
संख	संक्षेप संख्या खंड संख्या	हेक्टर	अक्षेपन सेन्टीग्रेडर एकर		
1	2	3/1	3/2	3/3	
जेरखी	537/14	00	03	38	
	537/13	00	16	71	
	537/9	00	15	90	
	537/5	00	18	20	
	537/1	00	11	00	
	कार्ट ट्रेक	00	01	40	
	549/2	00	18	80	
	549/1	00	07	80	
	553/8	00	08	00	
	551/7	00	24	40	
	भीमपुरा—बड़ीदा	00	01	80	
	रोड				
	563/3—ए	00	22	78	
	563/1	00	06	40	
	564	00	10	78	
	565/ए एण्ड बी	00	17	78	
	566	00	02	70	
	567	00	12	60	
	568	00	04	80	
	कार्ट ट्रेक	00	01	20	
	506/ए	00	21	10	
	505/1	00	15	80	
	493	00	15	80	

1	2	3/1	3/2	3/3	
जेरखी—जानी	494	2	00	20	60
	496/2		00	21	60
	497/4—ए एण्ड बी		00	04	80
	ईक्वएन्ट केनाल		00	04	00
	497/4—ए एण्ड बी		00	06	90
	497/3—ए एण्ड बी		00	11	80
	497/2—ए एण्ड बी		00	06	20
	497/1—ए		00	05	60
	500/3—ए एण्ड बी		00	11	60
	पोन्डी फार्म		00	06	20
	कार्ट ट्रेक		00	01	35
	368/3		00	08	50
	368/2		00	03	03
	368/1		00	11	00
	कार्ट ट्रेक		00	01	80
	331/2—ए		00	24	30
	336/2—ए एण्ड बी		00	13	00
	336/1—ए एण्ड बी		00	08	20
	338/2		00	18	00
	338/1		00	14	10
	कार्ट ट्रेक		00	01	40
	280/3		00	16	60
	281/1		00	20	00
	283		00	13	20
	कार्ट ट्रेक		00	01	80
	284/ए		00	21	20
	285/ए		00	20	00
	301		00	20	40
	300/1		00	01	80
	300/2		00	07	50
	कार्ट ट्रेक		00	00	90
	156/1		00	14	00
	157/1		00	13	80
	157/2—ए एण्ड बी		00	03	80
	कार्ट ट्रेक		00	02	00
	166/1—ए		00	01	70
	163/1—ए		00	11	90
	162/2—ए		00	18	80
	162/1		00	14	30
	161/2—ए		00	16	90
	कार्ट ट्रेक		00	01	00
	131		00	01	55
	130		00	15	30
	129/ए		00	10	55
	128		00	18	20
	126/ए एण्ड बी		00	14	00
	125/2—ए एण्ड बी		00	13	40
	124/2		00	08	70
	123/1—ए एण्ड बी		00	06	70
	कार्ट ट्रेक		00	01	80
	106/5		00	09	80
	106/6—बी		00	05	22
	106/3		00	14	58
	106/4—ए एण्ड बी		00	03	30

1	2	3/1	3/2	3/3
शेरखी	106/1-ए एण्ड बी	00	13	90
"	कार्ट ट्रैक	00	01	80

[सं. 45011/1/94-यू एस (पी सी)]

अर्जुन गोयल, अवर सचिव

New Delhi, the 10th March, 1995

S.O. 888.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum products from DAHEJ-GANDHAR to BARODA, VIA GAIL COMPLEX in Gujarat State pipeline should be laid by the Indian Petrochemicals Corporation Ltd.

And, whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Indian Petrochemicals Corporation Ltd., Gandhar Complex, 7th Floor, Hotel Surya Palace, Sayajigunj, Vadodara-5.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Petroleum pipeline from Dahej—Gandhar To Baroda
Indian Petrochemicals Corporation Ltd., Vadodara
State—Gujarat District—Baroda Taluka—Baroda

Village	Sr. No. Block No.	Area		
		Hec- tare	Ac- re	Cent- tare
1	2	3/1	3/2	3/3
Serkhji	537/14	00	03	38
	537/13	00	16	71
	537/9	00	15	90
	537/5	00	18	20
	537/1	00	11	00
	Cart Track	00	01	40
	549/2	00	18	80
	549/1	00	07	80
	553/8	00	08	00
	551/A	00	24	40
	Bhimpura-Baroda	00	01	80
	Road			
	563/3-A	00	22	78
	563/1	00	06	40
	564	00	10	78
	565/A&B	00	17	78
	566	00	02	70
	567	00	12	60
	568	00	04	80
	Cart Track	00	01	20
	506/A	00	24	10
	505/1	00	15	80
	493	00	15	80

1	2	3/1	3/2	3/3
Serkhji	494/2	00	20	00
	496/2	00	21	60
	497/5-A&B	00	04	80
	Eff-Channee	00	04	00
	497/4-A&B	00	06	90
	497/3-A&B	00	11	80
	497/2-A&B	00	05	20
	497/1-A	00	05	60
	500/3-A&B	00	14	60
	Poultry Farm	00	06	20
	Cart Track	00	01	35
	368/3	00	06	50
	368/2	00	03	03
	368/4	00	11	00
	Cart Track	00	01	80
	331/2-A	00	24	30
	336/2-A&B	00	13	00
	336/1A & B	00	08	20
	338/2	00	18	00
	338/1	00	14	10
	Cart Track	00	01	40
	281/3	00	16	60
	280/1	00	20	00
	183	00	13	20
	Cart Track	00	01	80
	284/A	00	21	20
	285/A	00	20	00
	301	00	20	40
	330/1	00	01	80
	300/2	00	07	50
	Cart Track	00	00	90
	156/1	00	14	00
	157/1	00	13	80
	157/2-A&B	00	03	80
	Cart Track	00	02	00
	166/1-A	00	01	70
	163/1-A	00	11	90
	162/2-A	00	18	80
	162/1	00	14	30
	161/2-A	00	16	90
	Cart Track	00	01	00
	131	00	01	55
	130	00	15	30
	129/A	00	10	55
	128	00	18	20
	126/A&B	00	14	00
	125/2-A&B	00	13	40
	124/2	00	08	70
	123/1-A&B	00	06	70
	Cart Track	00	01	80
	106/5	00	09	80
	106/6-B	00	05	22
	106/3	00	14	58
	106/4-A&B	00	03	30
	106/1-A&B	00	13	90
	Cart Track	00	01	80

[No-45011/1/94-IS(PC)]
D.P. GOEL, Under Secy.

नई दिल्ली, 10 मार्च, 1995

का.प्र. 889.—यह: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में बहेज—गंधार सड़क तहसील तक पेट्रो

नियम उत्पाद के परिवहन के लिए पाइपलाइन इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदपारब्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलेियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि., होटल सूर्यपैलेस, सयाजीगंज, बड़ौदा को इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिश्चितता यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

पेट्रोलेियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन दहेज-गंधार से बड़ौदा तक इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि., बड़ौदा

राज्य - गुजरात	जिला - भरुच	तालुका - बागरा			
गांव	सर्वेक्षण संख्या	हेक्टेयर	अक्षर	सेन्टीयर	
खंड संख्या					
1	2	3/1	3/2	3/3	
पादरिया	162/बी	00	10	40	
	161/ए	00	27	80	
	160	00	09	50	
	159/बी	00	07	40	
	नाला	00	03	00	
	180	00	05	20	
	179	00	12	90	
	177	00	24	80	
	कार्ट ट्रैक	00	00	80	
	170/बी	00	14	20	
	168	00	33	65	
	170/ए	00	04	55	
	13	00	20	40	
	15	00	52	20	
	अणिसादरा इन्ड्यू	00	04	80	
	बी एम रोड				

[सं. 45011/1/94-यूपम (पीसी)]

धर्मपाल गोयल, अवर सचिव

New Delhi, the 10th March, 1995

S.O. 889.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum products from DAHEJ-GANDHAR to BARODA VIA GAIL COMPLEX in Gujarat State pipeline should be laid by the Indian Petrochemicals Corporation Ltd.

And, whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Indian Petrochemicals Corporation Ltd., Gandhar Complex, 7th Floor, Hotel Surya Palace, Sayajiguni, Vadodara-5

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner

SCHEDULE

Petroleum pipeline from Dahai-Gandhar To Baroda
Indian Petrochemical Corporation Ltd., Vadodara

Village	Sr. No	Block No.	Area			
			Hac-	Are	Centi-	
			tare		tiare	
1	2	3/1	3/2	3/3		
Padriya	162/B	00	10	40		
	161/A	00	27	80		
	160	00	09	50		
	159/B	00	07	40		
	Nalla	00	03	00		
	180	00	05	20		
	179	00	12	90		
	177	00	24	80		
	Cart Track	00	00	80		
	170/B	00	14	20		
	168	00	33	65		
	170/A	00	04	55		
	13	00	20	40		
	15	00	52	20		
	WBM Road to Janiyadra	00	04	80		

[No. 45011/1/94-US(PC)]

D.P. GOEL, Under Secy.

नई दिल्ली, 10 मार्च, 1995

कां.आ. 890 यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक-हित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में दहेज - गंधार से बड़ौदा तक पेट्रोलेियम उत्पाद के परिवहन के लिए पाइपलाइन इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदपारब्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलेियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि., होटल सूर्यपैलेस, सयाजीगंज, बड़ौदा को इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टता: यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी मृतवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन वहेज-गंधार से बड़ौदा तक इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लि., बड़ौदा

राज्य - गुजरात जिला - भाखुच तालुका - वागरा

गांव	सर्वेक्षण संख्या खंड संख्या	हेक्टर एवं अंशफल	सेन्टीयर एकर	सेन्टीयर
1	2	3/1	3/2	3/3
पणियादरा	178/पी	00	07	04
	178/पी	00	09	00
	178/पी	00	07	60
	178/पी	00	03	80
	178/पी	00	15	32
	175	00	10	30
	179	00	20	80
	182	00	31	30
	174	00	04	55
	198	00	20	80
	200	00	10	30
मालोदरा-डब्ल्यू		00	04	40
बोगस रोड				
	199	00	11	40
	205	00	11	00
	206	00	07	20
	207	00	14	00
	208	00	08	00
	209	00	19	60
	239	00	03	74
	238	00	15	52
कार्ट ट्रैक		00	05	60
	258	10	22	50
	274	0	10	50
	259	00	01	98
	273	00	13	80
	290	00	31	15
	272/ए	00	13	80
	271	00	02	16
	270	00	01	54
	269	00	01	58
	268	00	00	60
नरणाजी रोड		00	05	00
	347	00	06	60
	346	00	06	25
	345	00	05	40
	350	00	11	50
	355	00	17	10
	356	00	22	85
	358	00	01	43
	357	00	01	92
	363	00	01	65
	364	00	10	70

1	2	3/1	3/2	3/3
	362	00	00	45
	366	00	17	60
	368	00	12	80
	369	00	08	30
	372/ए	00	18	52
	371	00	01	08
	373	00	20	00
	378	00	11	10
	379	00	02	46
	381	00	21	72
	380	00	01	65
	383	00	11	90
	384	00	00	38
	385	00	16	70
	388	00	00	30
	387	00	12	10

[सं. 45011/1/94-मूल (पॉमो)]

प्रधान मंत्री, नया दिल्ली

New Delhi, the 10th March, 1995

S.O. 890.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum products from DAHEJ-GANDHAR to BARODA, VIA GAIL COMPLEX in Gujarat State pipeline should be laid by the Indian Petrochemicals Corporation Ltd.

And, whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition, of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Indian Petrochemicals Corporation Ltd., Gandhar Complex, 7th Floor, Hotel Surya Palace, Sayajigunj, Vadodara-5.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Petroleum pipeline from Dahej—Gandhar To Baroda
Indian Petrochemicals Corporation Ltd., Vadodara
State—Gujarat District—Bahruch Taluka—Vagra

Village	Sr. No. Block No.	Area			
		Hac- tiare	Are	Centi- tiare	
1	2	3/1	3/2	3/3	
Paniyadara	178/P	00	07	04	
	178/P	00	09	00	
	178/P	00	07	60	
	178/P	00	03	80	
	178/P	00	15	32	
	175	00	10	30	
	177	00	20	80	
	182	00	31	30	

1	2	3/1	3/2	3/3
Paniyadara—(Contd)	174	00	04	55
	178	00	20	80
	200	00	10	30
	WBM Road to Goladara	00	04	40
	199	00	11	40
	205	00	11	00
	206	00	07	20
	207	00	14	00
	208	00	08	00
	209	00	19	60
	239	00	03	74
	238	00	15	52
	Cart Track	00	05	60
	258	00	22	50
	274	00	10	50
	259	00	01	98
	273	00	13	80
	290	00	31	15
	272/A	00	13	80
	271	00	02	16
	270	00	01	54
	269	00	01	58
	268	00	00	60
	Road to Narvani	00	05	00
	347	00	06	60
	346	00	06	25
	345	00	05	40
	350	00	11	50
	355	00	17	10
	356	00	22	65
	358	00	01	43
	357	00	01	9
	363	00	01	65
	364	00	10	70
	362	00	00	
	366	00	17	60
	368	00	12	80
	367	00	08	30
	372/A	00	18	52
	371	00	01	08
	373	00	20	00
	378	00	11	10
	379	00	02	46
	381	00	21	72
	380	00	01	65
	383	00	11	70
	384	00	00	38
	385	00	16	90
	388	00	00	30
	387	00	12	10

[No. 45011/1/94-US (PC)]

D.P. GOEL, Under Secy

नई दिल्ली, 10 मार्च, 1995

का. प्रा. 891—यस: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक-हित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में बहेज - गंधार से बड़ोदा तक पेट्रोलियम उत्पाद के परिवहन के लिए पाइपलाइन इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और इस तरह होता है कि ऐसी साधनों को क्लियर के प्रयोजन के लिए एतदुपाय अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना प्राथम्य एतद्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लि., होटल सुसंप्रैमिस, सवाजीगंज, बड़ोदा को इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिश्चितता यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची]

पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन बहेज - गंधार से बड़ोदा तक इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लि. बड़ोदा

राज्य - गुजरात जिला - भरुच तालुका - ग्रामोद

गांव	सबभण संख्या खंड संख्या	हेक्टर	श्रेष्ठफल एकर	सेन्टीयर
1	2	3/1	3/2	3/3
रोडा - टंकारिया	928	00	05	70
	927	00	10	11
	एलपीजी रिकवरी	00	04	30
	प्लान्ट - सीपीएफ			
	लाईन			
	922	00	18	40
	909	00	08	70
	908	00	06	00
	904	00	22	48
	911	00	92	45
	913	00	28	40
	ग्रास पैच	00	04	70
	876	00	31	70
	885	00	09	25
	जीएनएफसी में	00	04	00
	सीपीएफ लाईन			
	878	00	07	70
	877	00	07	70
	879	00	08	38
	झनोर पानी	00	07	25
	पुखड़ा लाईन &			
	880	00	25	80
	881	00	10	70
	867	00	09	40
	862/ए एंड बी	00	43	00
	866	00	08	70
	865	00	24	00
	गंधार - ग्रामोद	00	08	00
	रोड			
	ताला	00	04	10
	799	00	23	20
	802	00	09	35
	798	00	08	65

1	2	3/1	3/2	3/3
रोसा - टंकारिया	803	00	04	10
	804	00	17	68
	805	00	22	00
नाला	00	04	00	
	766	00	11	30
	765	00	14	50
	768	00	29	10
	769	00	14	50
	768	00	29	10
	769	00	12	10
	770	00	24	30
	771	00	07	10
	772	00	10	80
	746	00	10	30
	744	00	19	00
नाला	00	40	30	
	583	00	19	00
	584	00	21	00
	585	00	17	10
	705	00	21	00
	704	00	17	00
कार्ट ट्रैक	00	09	00	
	703	00	12	25
	626	00	22	30
	627	00	43	10
	628	00	32	00
	629	00	20	30
	631	00	19	70
	632	00	04	08
	633	00	14	42
	657	00	29	00

[सं. 45011/1/94-यूएम (पीसी)]

धर्मपाल गोयल, अवर सचिव

New Delhi, the 10th March, 1995

S.O. 891.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum products from DAHEJ-GANDHAR to BARODA, VIA GAIL COMPLEX in Gujarat State pipeline should be laid by the Indian Petrochemicals Corporation Ltd.

And, whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Indian Petrochemicals Corporation Ltd., Gandhar Complex, 7th Floor, Hotel Surya Palace, Sayajigunj, Vadodara-5.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE				
Petroleum pipeline from Dahej—Gandhar To Baroda				
Indian Petrochemicals Corporation Ltd., Vadodara				
State—Gujarat	District—Bharuch	Taluka—Amod		
Village	Sr. No. Block No	Area		
		Hac-	Arc	Cent-
1	2	tare	centare	3/3
Roza-Tankaria	928	00	05	70
	927	00	10	11
	LPG Recovery Plant to CPF Line	00	04	30
	922	00	18	40
	909	00	08	70
	908	00	06	00
	904	00	22	48
	911	00	02	45
	913	00	28	40
	Grass Patch	00	04	70
	876	00	31	70
	885	00	09	25
	GNFC To CPF Line	00	04	00
	878	00	07	70
	877	00	07	70
	879	00	08	38
	Zanor Water Supply Line	00	07	25
	880	00	25	80
	881	00	10	70
	867	00	09	40
	862/A&B	00	43	00
	866	00	08	70
	865	00	24	00
	Gandhar-Amod Road	00	08	00
	Nalla	00	04	10
	799	00	23	20
	802	00	09	35
	798	00	08	65
	803	00	04	10
	804	00	17	68
	805	00	22	00
	Nalla	00	04	00
	766	00	11	30
	765	00	14	50
	768	00	29	10
	769	00	12	10
	770	00	24	30
	771	00	07	10
	772	00	10	80
	746	00	10	30
	744	00	19	00
	Nalla	00	40	30
	583	00	19	00
	584	00	21	00
	585	00	17	10
	705	00	21	00
	704	00	17	00
	Cart Track	00	09	00
	703	00	12	25
	626	00	22	30

1	2	3/1	3/2	3/3
Roz-Tankaria—concd.	627	00	43	10
	628	00	32	00
	629	00	20	30
	631	00	19	70
	632	00	04	08
	633	00	14	42
	657	00	29	00

[No. 45011/1/94-US (PC)]

D.P. GOEL, Under Secy

नई दिल्ली, 10 मार्च, 1995

का. प्रा. 892.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक-हित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में दहेज-मश्वर से बड़ोदा तक पेट्रोलियम उत्पाद के परिवहन के लिए पाइपलाइन इंडियन पेट्रोकैमिकल्स कारपोरेशन लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए ;

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों की बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाय अन्तर्गामी में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ;

अतः प्रा. पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है ;

वर्तते कि उक्त भूमि में हितवाले कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आशेष सक्षम प्राधिकारी, इंडियन पेट्रोकैमिकल्स कारपोरेशन लि., होटल सूर्यपिनेम, मयाजीगज, बड़ोदरा को इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आशेष करने वाला हर व्यक्ति विनिश्चितता यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन दहेज-मश्वर से बड़ोदा तक इंडियन पेट्रोकैमिकल्स कारपोरेशन लि., बड़ोदा

राज्य - गुजरात जिला - अरूच तालुका - बागरा

गांव	सर्वेक्षण संख्या	ट्रैक्टर	क्षेत्रफल	मेट्रो/एअर
	खंड संख्या		एअर	
1	2	3/1	3/2	3/3
दहेज	1380	00	07	20
	1370	00	12	10
	1369	00	45	55
	1368	00	20	95
	1372	00	10	90
	1374	00	16	10
	1363	00	15	90
	1362/बी	00	44	30
	नाला - कम-	00	06	90
	कार्ट - ट्रेक			

1	2	3/1	3/2	3/3
दहेज-जारी	1196	00	19	90
	1197	00	39	25
	1191	00	01	35
	1190	00	13	50
	1189	00	08	10
	1188	00	05	86
	1187	00	00	29
नाला		00	07	25
1204/ए		00	35	80
1205		00	03	90
1213		00	20	90
1207		00	07	35
1211		00	13	15
1208		00	19	45
1084		00	16	95
1083		00	20	65
1087		00	07	05
1088		00	20	10
1089		00	20	20
1076		00	33	60
1077		00	33	97
1075		00	01	68
1073		00	12	80
1071		00	15	70
1032		00	31	55
1034		00	05	30
1035		00	35	80
1036		00	04	05
1037		00	08	05
1031		00	34	95
1000		00	16	90
999		00	18	85
998		00	07	65
997		00	40	90
934		99	17	60
933		99	25	87
932		99	12	35
929		01	80	95
930		00	20	60
685/बी		00	19	60
684		00	21	20
686		00	05	80
रोड		00	06	00
672		00	12	20
673/ए		00	15	50
655/बी		00	08	66
660		00	00	75
659/बी		00	29	91
658/बी		00	11	50
नाला		00	03	80
645/बी		00	07	90
646/बी		00	07	40
650/बी		00	19	80

1	2	3/1	3/2	3/3
दाहेज-गंधार	619	00	15	30
	651	00	06	58
काटे ट्रेक		00	06	10
256		00	03	95
255/ए		00	09	25
254/बी		00	20	63
257		00	01	69
253		00	15	83
259/बी		00	13	98
260		00	01	10
263/बी		00	18	95
265/बी		00	19	60
वीएसीएस		00	14	85
काटे ट्रेक				
234/ए		00	09	25
225/बी		00	25	60
230		00	07	85
226/बी		00	31	60
204		00	00	60
207		00	12	33
205		00	00	50
206		00	06	35
202/ए		00	42	40
199		00	20	60
197		00	03	80
196		00	07	70
दाहेज	195	00	12	90
	194/बी	00	25	80
	193	00	11	40

[सं 45011/1/94 - यम (पीसी)]

धर्मपाल गोयल, अवर सचिव

New Delhi, the 10th March, 1995

S.O. 892.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum products from Dahej-Gandhar to Baroda, Via Gail Complex in Gujarat State pipeline should be laid by the Indian Petroleum Corporation Ltd;

And, whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Indian Petrochemicals Corporation Ltd., Gandhar Complex, 7th Floor, Hotel Surva Palace, Sayajigunj, Vadodara-5.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Petroleum pipeline from Dahej- Gandhar to Baroda
Indian Petrochemicals Corporation Ltd., Vadodara

State - Gujarat District - Bharuch Taluka - Vagra

Village	Sr. No, Block No.	Area		
		Hac- tare	Are	Cent- tare
1	2	3/1	3/2	3/3
Dahej	1380	00	07	20
	1370	00	12	10
	1369	00	45	55
	1368	00	20	95
	1372	00	10	90
	1374	00	16	10
	1363	00	15	90
	1362/P	00	44	30
	Nalla-cum-Cart Track	00	06	90
	1196	00	19	90
	1197	00	39	25
	1191	00	01	35
	1190	00	13	50
	1189	00	08	10
	1188	00	05	86
	1187	00	00	29
	Nalla	00	07	25
	1204/A	00	35	80
	1205	00	03	90
	1213	00	20	90
	1207	00	07	35
	1211	00	13	15
	1208	00	19	45
	1084	00	16	95
	1083	00	20	65
	1087	00	05	05
	1088	00	20	10
	1089	00	20	20
	1076	00	33	60
	1077	00	33	97
	1075	00	01	68
	1073	00	12	80
	1071	00	15	70
	1032	00	31	55
	1034	00	05	30
	1035	00	35	80
	1036	00	04	05
	1037	00	08	05
	1031	00	34	95
	1000	00	16	90
	999	00	18	85
	998	00	07	65
	997	00	40	90
	934	00	17	60
	933	00	25	87
	932	00	12	35
	929	00	81	95
	930	00	20	60
	685/B	00	19	60
	684	00	21	20
	686	00	05	80
Road		00	06	00

1	2	3/1	3/2	3/3
Dahej—Concl d.	672	00	12	20
	673/A	00	15	50
	655/B	00	08	66
	660	00	00	75
	659/B	00	29	94
	658/B	00	11	50
	Nalla	00	03	80
	645/B	00	07	90
	646/B	00	07	40
	650/B	00	19	80
	649	00	15	30
	651	00	06	58
	Cart Track	00	06	10
	256	00	03	95
	255/A	00	09	25
	254/B	00	20	63
	257	00	01	69
	253	00	15	83
	258/B	00	13	98
	260	00	01	10
	263/B	00	18	75
	265/B	00	19	60
	Cart Track To	00	14	85
	GACL			
	234/A	00	09	25
	225/B	00	25	60
	230	00	07	85
	226/B	00	31	60
	204	00	00	60
	207	00	12	33
	205	00	00	50
	206	00	06	35
	202/A	00	42	40
	199	00	20	60
	197	00	03	80
	196	00	07	70
	195	00	12	90
	194/B	00	25	80
	193	00	11	40

[No. 45011/1/94-US (PC)]

D.P. GOEL, Under Secy

नई दिल्ली, 10 मार्च, 1995

का. मा. 893.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक-हित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में बड़ेज-गंधार से बड़ीदा तक पेट्रोलियम उत्पाद के परिवहन के लिए पाइपलाइन इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाय अतिसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना प्राणय एतद्वारा घोषित किया है।

बनाने कि उक्त भूमि में किसबंद कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लि., होटल सूर्या पैलेस, मयाजीगंज, बड़ीदा को इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिबिधता यह भी कथन करेगा कि क्या यह चाहता है कि उसकी व्यक्तिगत सुनवाई हो या किसी विशिष्ट व्यवसायी को मार्केट।

अनुसूची

पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन बड़ेज-गंधार से बड़ीदा तक इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लि., बड़ीदा

राज्य - गुजरात जिला - अमच तालुका - वागरा

पथ	सर्वेक्षण संख्या खंड संख्या	हेक्टर	क्षेत्रफल सेन्टीएअर एअर	
1	2	3/1	3/2	3/3
बांधवेस	1205	00	21	15
	1203	00	01	40
	1204	00	34	25
	1207	00	04	55
	1208	00	10	78
	1209	00	78	96
	1210	00	06	46
	1103	00	31	51
	नाला	00	09	30
	1106	00	05	69
	1107	00	05	50
	1108	00	06	58
	1101	00	06	30
	1109	00	00	95
	1100	00	17	41
	1076	00	06	32
	1077	00	41	13
	1079	00	50	60
	बदलपुरा रोड	00	04	00
	1268	00	72	25
	1266	00	19	91
	1264	00	07	29
	1262	00	22	05
	1263	00	28	00
	ग्राम पेज	00	04	70
	164	00	12	40
	166	00	08	80
	167	00	17	40
	168	00	02	18
	170	00	46	82
	169	00	23	20
	199	00	04	80
	200	00	17	40
	201	00	14	02
	205	00	11	40
	208	00	33	40
	228	00	31	67
	229	00	03	08
	228/ए.एंड.बी	00	16	85
	रवाडी	00	11	60

[सं. 45011/1/94 - एस (पीसी)]

धर्मपाल गोयल, अधीक्षक सचिव

New Delhi, the 10th March, 1995

S.O. 893.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum products from DAHEJ-GANDHAR to BARODA, VIA GAIL COMPLEX in Gujarat State pipeline should be laid by the Indian Petrochemicals Corporation Ltd.

And, whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Indian Petrochemicals Corporation Ltd., Gandhar Complex, 7th Floor, Hotel Surya Palace, Sayajiguni, Vadodara-5.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Petroleum pipeline from Dahej—Gandhar To Baroda
Indian Petrochemicals Corporation Ltd., Vadodara
State—Gujarat District—Bharuch Taluka—Vagra

Village	Sr. No. Block No.	Area		
		Hac-tare	Are	Cent-tare
1	2	3/1	3/2	3/3
Chanchwel W	1205	00	21	15
	1203	00	01	40
	1204	00	34	25
	1207	00	04	55
	1208	00	10	78
	1209	00	78	96
	1210	00	06	46
	1103	00	31	51
	Nalla	00	09	30
	1106	00	05	69
	1107	00	05	50
	1108	00	06	58
	1101	00	06	30
	1109	00	00	95
	1100	00	17	41
	1076	00	06	32
	1077	00	41	13
Chanchwel	1979	00	50	60
	Reat to Badal-pura	00	04	00
	1268	00	72	25
	1266	00	19	91
	1264	00	07	29
	1262	00	22	05
	1263	00	28	00
	Grass Patch	00	04	70
	164	00	12	40
	166	00	08	80
	167	00	17	40
	168	00	02	18
	170	00	46	82
	169	00	23	20
	199	00	04	80
	200	00	17	40

1	2	3/1	3/2	3/3
	201	00	14	02
	205	00	11	40
	208	00	33	40
	228	00	31	67
	229	00	03	08
	226/A&B	00	16	85
	Khadi	00	11	60

[No. 45011/1/94-U/S (PC)]

D.P. GOEL, Under Secy.

नई दिल्ली, 10 मार्च, 1995

का. आ. 894 यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक-हित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में दहेज-गंधार से बड़ोदा तक पेट्रोलियम उत्पाद के परिवहन के लिए पाइपलाइन इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

यतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

बशर्त कि उक्त भूमि में हितवन् कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन-बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लि., होटल सूर्यापैलेस, सयाजीगुंज, बड़ोदा को इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिश्चितता यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन दहेज-गंधार से बड़ोदा तक इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लि. बड़ोदा

गांव संक्षेप संख्या हेक्टर क्षेत्रफल अन्दीपर
खंड संख्या एअर

1	2	3/1	3/2	3/3
पालडी	38	00	21	41
	39	00	16	52
	40	00	03	68
	36	00	00	48
	41	00	22	52
	42	00	04	80
	35	00	05	60
	34	00	04	60
	33	00	09	60
	15	00	04	20
	पालडी गैर	00	04	00
	431	00	09	60
	432	00	25	40
	433/ए	00	26	60

1	2	3/1	3/2	3/3
पालडी	कार्ट ट्रैक	00	04	00
	389	00	24	20
	390	00	16	00
	387	00	26	60
	386	00	04	20
पालडी - कार्ट ट्रैक		00	02	00
	175	00	21	30
	174	00	17	40
	177	00	34	59
	178	00	04	41
	179	00	15	80
	215	00	19	80
	214	00	04	32
	208	00	07	20
	213	00	22	00
जीएनसीवाय		00	04	00
इन्डियन पीट्रोम रोड				
	224	00	20	60
	225	00	14	80
	226	50	11	80
	227	00	12	40
	228	00	12	80
	252	00	25	40
	245	00	40	00
	244	00	34	35
पालडी				
	243	00	19	60
	258	00	16	40

[सं. 45011/1/94 - एस (पीसी)]

धर्मपाल गोक्न, सचिव

New Delhi, the 10th March, 1995

S.O. 894.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum products from DAHEJ-GANDHAR to BARODA, VIA GAIL COMPLEX in Gujarat State pipeline should be laid by the Indian Petrochemicals Corporation Ltd.

And, whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Indian Petrochemicals Corporation Ltd., Gandhar Complex, 7th Floor, Hotel Surya Palace, Sayajigunj, Vadodara-5.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Petroleum pipeline from Dahej—Gandhar To Baroda
Indian Petrochemicals Corporation Ltd., Vadodara
State—Gujarat District—Bharuch Taluka—Vagra

Village	Sr. No. Block No.	Area		
		Hac-	Are	Cen-
		tare	tare	tare
1	2	3/1	3/2	3/3
Paldi	38	00	21	44
	39	00	16	52
	40	00	03	68
	36	00	00	48
	41	00	22	52
	42	00	04	80
	35	00	05	60
	34	00	04	60
	33	00	09	60
	15	00	04	20
	Roat to Paldi	07	04	00
	431	00	09	60
	432	00	25	40
	433/A	00	26	60
	Cart Track	00	04	00
Paldi	389	00	24	20
	390	00	16	00
	387	00	26	60
	386	00	04	20
	Cart Track to Paldi	00	02	00
	175	00	21	30
	174	00	17	40
	177	00	34	59
	178	00	04	41
	179	00	15	80
	215	00	19	80
	214	00	04	32
	208	00	07	20
	213	00	22	00
	WBM Road to GNGY	00	04	00
Paldi	224	00	20	60
	225	00	14	80
	226	00	11	80
	227	00	12	40
	228	00	12	80
	252	00	25	40
	245	00	40	00
	244	00	34	35
Paldi	243	00	19	60
	258	00	16	40

[No. 45011/1/94-U/S (PC)]

D.P. GOEL, Under Secy;

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1995

क्र०आ० 895.—यतः चेम्बूर पातालगंगा पाइपलाइन लिमिटेड ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 की धारा 6(1) के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित गांवों में नेफ्था पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग का अधिकार अर्जित किया है और उक्त अधिनियम की धारा 7(1) के खण्ड 1 में यथा संदर्भित पाइपलाइन बिछाने का कार्य 31 मार्च, 1992 तक पूरा कर लिया है,

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) नियम, 1963 के नियम 4(1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी इसके द्वारा उपरलिखित तारीख को अनुसूची में यथा उल्लिखित गांवों में पाइपलाइन बिछाने के कार्य की परिसमाप्ति की तारीख के रूप में अधिमूचित करता है, यथा :

अनुसूची

राज्य : महाराष्ट्र

क्रम संख्या	गांव का नाम	तालुक	जिला	कार्य परिसमाप्ति की तारीख
1.	अनिक	कुर्ला	बम्बई उपनगरीय जिला	31-03-92

[फाइल संख्या आर-31015/6/91-ओ०आर०-II]

के०सी० कटोच, अवसर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 24th March, 1995

S.O. 895.—Whereas the Chembur Patalganga Pipelines Limited has acquired the right of user under Section 6(1) of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 for laying the Naphtha Pipelines in the villages mentioned in the schedule given below and

has completed on the 31st March, 1992 the laying of pipelines as referred to in clause 1 of Section 7(1) of the said Act;

Now, therefore, in pursuance of rule 4(1) of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies that the above mentioned date as the date of termination of operation of laying the pipeline in the villages mentioned in the schedule as follows, namely :—

SCHEDULE

State Maharashtra

Sr. No.	Name of the Village	Taluka	District	Date of Termination of Operation
1	2	3	4	5
1.	Anik	Kurla	Bombay Suburban District	31-03-1992

[File No. R.—31015/6/91-OR-II]

K.C. KATOCH, Under Secy.

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1995

क्र०आ० 896.—यतः चेम्बूर पातालगंगा पाइपलाइन लिमिटेड ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 की धारा 6(1) के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित गांवों में नेफ्था पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग का अधिकार अर्जित किया है और उक्त अधिनियम की धारा 7(1) के खण्ड 1 में यथा संदर्भित पाइपलाइन बिछाने का कार्य 31 मार्च, 1992 तक पूरा कर लिया है,

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) नियम 1963 के नियम 4(1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी इसके द्वारा उपरलिखित तारीख को अनुसूची में यथा उल्लिखित गांवों में पाइपलाइन बिछाने के कार्य की परिसमाप्ति की तारीख के रूप में अधिमूचित करता है, यथा :

अनुसूची

जिला : महाराष्ट्र

क्रम संख्या	गांव का नाम	तालुक	जिला	कार्य परिसमाप्ति की तारीख
1	2	3	4	5
1.	आंबीवली	खालापूर	रायगढ़	31-03-92
2.	वासाम्बे (मोहपाडा)	"	"	31-03-92
3.	पनशील	"	"	31-03-92
4.	तालेगांव	"	"	31-03-92
5.	खानावली	पनशील	"	31-03-92
6.	मोहपे	"	"	31-03-92
7.	भिंगरवाडी	"	"	31-03-92
8.	भिंगर	"	"	31-03-92
9.	शेंदुग	"	"	31-03-92
10.	अजीवली	"	"	31-03-92
11.	मांगाडे	"	"	31-03-92
12.	सिखाले	"	"	31-03-92
13.	शिवकर	"	"	31-03-92
14.	विचुंबे	"	"	31-03-92
15.	देवाड	"	"	31-03-92
16.	पालीदेवाड	"	"	31-03-92
17.	शिलोट्टार रायचूर	"	"	31-03-92
18.	आदाई	"	"	31-03-92
19.	मानडाले	कुर्ली	बम्बई	31-03-92

[फाइल संख्या—आर-31015/6/91-ओ०आर०ii]

के०सी० कटोच, अवर सचिव

New Delhi, the 24th March, 1995

S.O. 896.—Whereas the Chembur Patalganga Pipelines Limited has acquired the right of user under Section 6(1) of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 for laying the Naphtha Pipeline in the villages mentioned in the schedule given below and has completed on the 31st March, 1992 the laying of pipelines as referred to in clause 1 of Section 7(1) of the said Act;

Now, therefore, in pursuance of rule 4(1) of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies that the above mentioned date as the date of termination of operation of laying the pipeline in the villages mentioned in the schedule as follows, namely :—

SCHEDULE

State—Maharashtra

Sr. No.	Name of the Village	Taluka	District	Date of Termination of Operation
1	2	3	4	5
1.	Ambivali	Khalapur	Raigad	31-03-1992
2.	Wasambe (Mohapada)	"	"	31-03-1992
3.	Panshil	"	"	31-03-1992
4.	Talegaon	"	"	31-03-1992

1	2	3	4	5
5.	Khanawale	Panvel	"	31-03-1992
6.	Mohope	"	"	31-03-1992
7.	Bhingarwadi	"	"	31-03-1992
8.	Bhingar	"	"	31-03-1992
9.	Shedung	"	"	31-03-1992
10.	Ajiwali	"	"	31-03-1992
11.	Sangade	"	"	31-03-1992
12.	Chikhale	"	"	31-03-1992
13.	Shivahar	"	"	31-03-1992
14.	Vichumbe	"	"	31-03-1992
15.	Devad	"	"	31-03-1992
16.	Palidevad	"	"	31-03-1992
17.	Shillottar Raichur	"	"	31-03-1992
18.	Adai	"	"	31-03-1992
19.	Mandale	Kurla	Bombay	31-03-1992

[File No. R.—31015/6/91-OR. II]
K.C. KATOCH, Under Secy.

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1995

का आ 897 .—केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 2346 दिनांक 06-11-93 द्वारा पेट्रोलियम परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकारों के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 06-11-93 को उपलब्ध करा दी गई थी,

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसर्गण में सक्षम अधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है।

आर केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए,

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करने की घोषणा करती है,

और केन्द्रीय सरकार उक्त धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाए सभी विल्लंगों से मुक्त चेम्बुर पातालगंगा पाइपलाइन लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

तहसील : पानवेल		जिला : रायगढ़		राज्य : महाराष्ट्र	
गांव का नाम	क्र सं /वर्ग सं	हिस्सा सं	क्षेत्रफल	सेंटेयर	
			हेक्टेयर	आरे	
1	2	3	4	5	6
गांव : अजीवाली	62	1 हिस्सा	00	02	50

[फाइल संख्या आर 31015/6/93-ओ आर -II]
के. सी. कटोच, अवर सचिव

New Delhi, the 24th March, 1995

S.O. 897.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, No. 2346 dated 6-11-1993 issued under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transport of petroleum products;

And, whereas, the copies of the said Gazette Notification were made available to the public on the 6-11-1993;

And, whereas, the Competent Authority in pursuance of sub-section (1) of Section 6 of the said Act has made his report to the Central Government;

And, whereas, the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification are hereby acquired;

And, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6, the Central Government hereby directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government, vest in the Chembur Patalganga Pipelines Limited free from all encumbrances.

SCHEDULE

Tehsil : Panvel		District : Raigad		State : Maharashtra	
Name of Village	Survey No./ GAT No.	Hissa No.	Area		
			Hectare	Acre	Centiare
1	2	3	4	5	6
Village—Ajiwali	62	1 Part	00	02	50

[F. No. R-31015/6/93-OR. II]

K.C. KATOCH, Under Secy.

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1995

का.आ. 898.—केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 2345 दिनांक 06-11-93 द्वारा पेट्रोलियम परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकारों के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 06-11-93 को उपलब्ध करा दी गई थी,

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम अधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है।

और केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए,

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करने की घोषणा करती है,

और केन्द्रीय सरकार उक्त धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाए मधी विल्वंगमों से मुक्त चेम्बुर पातालगंगा पाइपलाइन लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

तहसील : खालापूर		जिला : रायगढ़		राज्य : महाराष्ट्र	
गांव का नाम	क्र. सं. / वग सं.	हिस्सा संख्या	क्षेत्रफल		सेंटेयर
			हेक्टेयर	आरे	
तेले गांव	8	6 हिस्सा	00	03	25
	8	2 हिस्सा	00	03	00
	8	1 हिस्सा	00	02	90
	7	6 हिस्सा	00	01	35

[फाइल संख्या आर-31015/9/91-ओ आर -II]

के.सी. कटोच, अधीक्षक सचिव

New Delhi, the 24th March, 1995

S.O. 898.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, No. 2345 dated the 6-11-1993 issued under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transport of petroleum products;

And, whereas, the copies of the said Gazette Notification were made available to the public on the 6-11-1993;

And, whereas, the Competent Authority in pursuance of sub-section (1) of Section 6 of the said Act has made his report to the Central Government;

And, whereas, the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification are hereby acquired;

And, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6, the Central Government hereby directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government, vest in the Chembur Patalganga Pipelines Limited free from all encumbrances.

SCHEDULE

Tehsil : Khalapur		District : Raigad		State : Maharashtra	
Name of Village	Survey No./ GAT No.	Hissa No.	Area		
			Hectare	Acre	Centiare
1	2	3	4	5	6
Village—Talegaon	8	6 part	00	02	25
	8	2 part	00	03	00
	8	1 part	00	02	90
	7	6 part	00	01	35

[F. No. R.-31015/9-91-OR.II]
K.C. KATOCH, Under Secy.

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1995

का. आ. 899.—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई और भारत के राजपत्र, भाग - II, खंड 3, उपखंड (ii) के पृष्ठ 1802 से 1801 पर प्रकाशित भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 1321 तारीख 11 जून, 1994 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दी की ;

और केन्द्रीय सरकार की जानकारी में यह लाया गया है कि राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन में सूत्रण प्रकृति की कमिषन त्रुटियां हो गई हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची का निम्नलिखित रूप में संशोधन करती है :—

पृष्ठ 1803—“गांव का नाम” शीर्षक से संबंधित स्तम्भ 1 के नीचे सबसे पहले प्रकाशित “विमापुर (2)” के स्थान पर “विमापुर (1)” पढ़ें।

पृष्ठ 1803— स्तम्भ 1 के नीचे गांव का नाम “कटारणी” के स्थान पर “कातरणी” पढ़ें।

पृष्ठ 1803—स्तम्भ 1 के नीचे गांव का नाम “अदगांव रेपाल (1)” के स्थान पर “अदगांव रेपाल (1)” पढ़ें तथा पृ. 1803 और 1804 पर स्तम्भ 1 के नीचे गांव का नाम “अदगांव रेपाल” जहाँ-जहाँ भी वह आता है, “अदगांव रेपाल” पढ़ें।

पृष्ठ 1803—“अदगांव रेपाल (1)” गांव से संबंधित सर्वे नं. 488 के सामने स्तम्भ 4 के नीचे “80” के स्थान पर “30” पढ़ें।

पृष्ठ 1804—“अदगांव रेपाल (4)” गांव से संबंधित सर्वे नं. 160 के सामने स्तम्भ 5 के नीचे “05” के स्थान पर “50” पढ़ें तथा सर्वे नं. 175 के सामने स्तम्भ 4 के नीचे “04” के स्थान पर “05” पढ़ें।

पृष्ठ 1804—“अदगांव रेपाल (5)” गांव से संबंधित सर्वे नं. “58” और स्तम्भ 3 से स्तम्भ 5 में क्रमशः “0” “44” और “40” का लोप किया जाता है।

पृष्ठ 1804—“नीलखेड़ा” गांव से संबंधित सर्वे नं. 176/ए के सामने स्तम्भ 4 में “10” के स्थान पर “19” पढ़ें।

पृष्ठ 1804—“लोकी - शिरत (2)” गांव से संबंधित प्रविष्टि के स्तम्भ (2) में सर्वे नं. “100/3” के स्थान पर “103/3” पढ़ें।

पृष्ठ 1804—स्तम्भ 1 के नीचे गांव का नाम “लोकी - शिरत” के स्थान पर “लोकी - शिरत (3)” पढ़ें तथा जहाँ-जहाँ “लोकी शिरत” आता है वहाँ “लोकी शिरत” पढ़ें।

पृष्ठ 1804—स्तम्भ 1 के नीचे गांव का नाम “वलदगांव” के स्थान पर “वलदगांव (1)” पढ़ें तथा “वलदगांव” गांव से संबंधित प्रविष्टि के स्तम्भ 2 के नीचे सर्वे नं. “194/3/ए/1” के स्थान पर “194/3/ए पढ़ें।

पृष्ठ 1804—“वलदगांव (2)” गांव से संबंधित सर्वे नं. 239 के सामने स्तम्भ 5 के नीचे “10” के स्थान पर “18” पढ़ें।

ऐसी किसी भूमि में, जिसकी बाबत उपरोक्त संशोधन जारी किया गया है, हितवद्ध कोई व्यक्ति उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, दसकोस दिन के भीतर उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अनुसार उक्त संपूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में या उस पर किसी अधिकार के अर्जन के संबंध में आक्षेप श्री ए. एन. देशपाण्डे सक्षम प्राधिकारी, मुम्बई-मनमाड पाइपलाइन परियोजना, 9-13, त्रितीय तल, बसन्त मार्केट कनाड कॉर्नर नामिक - 422002 को कर सकेगा।

स्पष्टीकरण: केवल इस अधिसूचना के माध्यम से संशोधित भूमि, जसरा संख्यांक और क्षेत्र की बाबत, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अनुसार दसकोस दिन की उक्त अवधि उस तारीख से आरंभ होती है जिसको यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन के पश्चात् जनता को उपलब्ध करा दी जाती है।

[फाइल सं. आर-31015/3/93-ओ. आर-II]

के. सी. कटोच, अवर सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 24th March, 1995

S.O. 899.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas No. S.O. 1321 dated 11th June, 1994 published at pages 1804 to 1806 dated 11th June, 1994 of the Gazette of India Part II, Section 3, Sub-section (ii), issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of Users in Land) Act, 1962, (50 of 1962), the Central Government gave notice of its intention to acquire the lands specified in the schedule appended to that notification;

And whereas, it has been brought to the notice of the Central Government that certain errors of printing nature have occurred in the publication of the said notification in the Gazette;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby amends the schedule appended to the said notification as follows:

at page 1805, in village Adgaon Repal (I), between Survey No. “469/3” and “479/2” in column 2 “479/1”, in column 3 “0”, in column 4 “17” and in column 5 “50” shall be added.

at page 1805, in village Adgaon Repal (V), “58” in column 2, “0” in column 3, “44” in column 4 and “40” in column 5 shall be omitted,

at page 1806, in village Valadgaon (I), for Survey No. “233/1” read “223/1”.

Any person interested in any land in respect of which the above amendment has been issued, may within twenty one days from the date on which the copies of this notification are made available to the general public, object to the acquisition of the whole or any part of the said land or any right in or over such land in terms of sub-section (i) of section 5 of the said Act to Shri A. N. Deshpande, Competent Authority, Bombay Manmad Pipeline Project, 9-13, 2nd Floor, Vasant Market, Canada Corner, Nasik-422002.

Explanation.—In respect of the lands, Khasra Nos. and area amended through this notification only, the said period of twenty one days in terms of sub-section (1) of Section 5 of the said Act starts running from the date notification is made available to the public after its publication in Official Gazette.

[File No. R-31015/3/93-OR. II]

K. C. KATOCH, Under Secy.

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 29 मार्च, 1995

का. आ. 900.—केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकांश का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत के राजपत्र, भाग - 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) पृष्ठ 66 पर प्रकाशित भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संवाहक की अधिसूचना सं. का. आ. 69 तारीख 14 जनवरी, 1995 द्वारा इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दी थी,

और केन्द्रीय सरकार की जानकारी में यह लाया गया है कि राजपत्र के प्रकाशन में भ्रम संबंधी कुछ गलतियां हो गई हैं।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में निम्नलिखित रूप में संशोधन करती है:—

पृष्ठ सं. 66 गुजरा गांव में, स्तम्भ 3 के नीचे किला नं. “51” के स्थान पर “5/1” पढ़ें।

सम्बुके गांव में, स्तम्भ 3 के नीचे किला नं. “32” के स्थान पर “3/2” पढ़ें।

ऐसी भूमि में, जिसकी बाबत उपरोक्त संशोधन जारी किया गया है, हितवद्ध कोई व्यक्ति इस अधिसूचना के जारी किए जाने के दसकोस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के विवेचना के अनुसार उक्त संपूर्ण भूमि या उसके किसी भाग के या ऐसी भूमि में या उस पर के किसी अधिकार के अर्जन के संबंध में आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, डिप्टी आयल कारपोरेशन लिमिटेड, कोर्टा नं. 1010, सेक्टर 42-बी, खण्डीगढ़ को कर सकेगा।

स्पष्टीकरण:— इस अधिसूचना द्वारा संशोधित भूमियों, किला नं. और क्षेत्र क्रम को आवत की उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के निबंधनों के अनुसार इकतीस दिन की उक्त अवधि उस तारीख से प्रारम्भ होती है जिसकी यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन के पश्चात् जनता को उपलब्ध करा दी जाती है।

[नं. प्रार-31015/4/94-ओ. प्रार-I]

के. सी. कटोच, प्रवर सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 29th March, 1995

S.O. 900.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas No. S.O. 69, dated 14th January, 1995, published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), at pages 66 to 67 issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government gave notice of its intention to acquire the land specified in the Schedule appended to the notification;

And whereas, it has been brought to the notice of the Central Government that certain errors of printing nature have occurred in the publication of the said notification in the Gazette;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby amends the Schedule appended to the said notification as follows:

at page 67, in village Gobindpur Nagri, against killa No. 9, in column 6, for '53' read '63';
in village Jhanduke, in column 3, for killa No. '312' read '3/2'.

Any person interested in any land in respect of which the above amendment has been issued, may within twenty one days of the issue of this notification, object to the acquisition of the whole or any part of the said land or any right in or over such land in terms of sub-section (1) of section 5 of the said Act to the Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Kothi No. 1010, Sector 42-B, Chandigarh.

Explanation.—In respect of the lands, killa Nos. and areas amended through this notification only, the said period of twenty one days in terms of sub-section (1) of section 5 of the said Act starts running from the date the notification is made available to the public after publication in the Gazette.

[No. R-31015/4/94-OR, 1]

K. C. KATOCH, Under Secy.

कृषि मंत्रालय

(कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, 10 मार्च, 1995

का.प्र. 901.—केन्द्रीय सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में एतद्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निम्नलिखित संस्थानों जिनके 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को अधिसूचित करती है।

1. केन्द्रीय समुद्री वास्तुशिल्पी अनुसंधान संस्थान का वैरावल अनुसंधान केन्द्र (गुजरात)

2. राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल (हरियाणा)

[संख्या 13-5/95-हिन्दी]

प्रार. पो. सरोज, प्रवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agricultural Research and Education)

New Delhi, the 10th March, 1995

S.O. 901.—In pursuance of Sub-Rule 4 of Rule 10 of the Official Language (use of Official purpose of the Union) Rules, 1976, the Central Government, Ministry of Agriculture, Department of Agricultural Research and Education hereby notifies the following Institutes of ICAR, where more than 80 per cent of Staff have acquired the working knowledge of Hindi:

1. Veraval Research Centre of Central Marine Fisheries Institute (Gujarat).

2. National Dairy Research Institute, Karnal, (Haryana).

[No. 13-5/95-Hindi]

R. P. SAROJ, Under Secy.

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय

(नागर विमानन विभाग)

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 1995

का.प्र. 902.—राष्ट्रपति, एयर वाइस मार्शल (सेवानिवृत्त) एच.एम. शाहुल, सलाहकार (प्रचालन) राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को 24-2-95 में और अगला आदेश जारी होने तक रु. 9000-10000/- के अनुसूचित "क" ग्रेड में राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष और भारत अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करते हैं।

[एफ. संख्या ए.वी.-11015/4/93-एन.ए.ए. (बी.सी.)]

वी. के. साधु, उप-सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND TOURISM

(Department of Civil Aviation)

New Delhi, the 24th February, 1995

S.O. 902.—The President is pleased to appoint Air Vice-Marshal (Retd.) H.M. Shahul, Adviser (Operations), National Airports Authority as Chairman, National Airports Authority and Chairman, International Airports Authority of India in the Schedule "A" grade of Rs. 9000-10,000/- with effect from 24-2-1995 and until further orders.

[F. No. AV. 11015/4/93-NAA (VB)]

V. K. SADHU, Dy. Secy.

(पर्यटन विभाग)

(होटल एवं रेस्तरां प्रभाग)

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1995

विषय: किसी भी साइज के महलों/दुर्गों/किलों/ड्वेलियों/आवासों को हेरिटेज होटलों में परिवर्तित करने के लिए पूंजीगत इमदाद स्कीम

का.प्र. 903.—भारत के राष्ट्रपति ने किसी भी साइज के महलों/दुर्गों/किलों/ड्वेलियों/आवासों को हेरिटेज होटलों में परिवर्तित करने के लिए पूंजीगत इमदाद स्कीम के प्रचलन को 30-6-95 तक बढ़ा दिया है।

पूंजीगत इमदाद स्कीम के लिए शर्तें दिनांक 12-5-1993 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित शर्तों के अनुसार ही बनी रहेंगी।

ये आदेश एकीकृत वित्त की सहमति से उनके दिनांक 12-2-1995 के ओ.टि. 345/एफ-11/95 के तहत जारी किए जाते हैं।

[सं. 3-टीएच-II(6)/92-खण्ड]

ए. के. सूद, अवर सचिव

(Department of Tourism)

(H AND R DIVISION)

New Delhi, the 28th February, 1995

Subject : CAPITAL SUBSIDY SCHEME for converting palaces/castles/forts/havelies/residences of any size into Heritage Hotels.

S.O. 903.—The President of India is pleased to extend the operation of the capital subsidy scheme for converting palaces/castles/forts/havelies/residences of any size into Heritage Hotels upto 30-6-1995.

The terms and conditions for capital subsidy scheme will remain the same as notified vide Notification dated 12-5-93.

These orders are issued with the concurrence of Integrated Finance vide their U.O. No. 346/F. 55/95, dated 12-2-95.

[No. 3-TH-II (6)/92-Pt.]

A. K. SOOD, Under Secy.

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

नई दिल्ली, 21 मार्च, 1995

कां.प्रा० 904.—अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 की संख्या 52) (इसे आगे कथित अधिनियम संदर्भित किया गया है) की धारा 14 की उपधारा (1) के अनुसरण में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् एतद्वारा निम्नलिखित अध्ययन मंडल स्थापित करती है, अर्थात् :—

- (i) कानपुर स्थित उत्तरी क्षेत्रीय समिति कार्यालय;
- (ii) मद्रास स्थित दक्षिणी क्षेत्रीय समिति कार्यालय;
- (iii) बम्बई स्थित पश्चिमी क्षेत्रीय समिति कार्यालय;
- (iv) कलकत्ता स्थित पूर्वी क्षेत्रीय समिति कार्यालय।

2. कथित अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में परिषद् एतद्वारा निम्नलिखित अध्ययन मंडल स्थापित करती है, अर्थात् :—

- (i) भोपाल स्थित केन्द्रीय क्षेत्रीय समिति कार्यालय;
- (ii) चंडीगढ़ स्थित उत्तर पश्चिमी क्षेत्रीय समिति कार्यालय;
- (iii) बंगलौर स्थित दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रीय समिति कार्यालय।

[फा० 4-5/सीसीएफ/आरईजीयू/आरसीएस/94(14)]

जे०पी० गुप्ता, सदस्य सचिव

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION

New Delhi, the 21st March, 1995

S.O. 904.—The following regional Committees are hereby established by the All India Council for Technical Education, in pursuance of sub-section (1) of section 14 of the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987) (hereinafter referred to as the said Act), namely :—

- (i) the Northern Regional Committee with its office at Kanpur;
- (ii) the Southern Regional Committee with its office at Madras;
- (iii) the Western Regional Committee with its office at Bombay; and
- (iv) the Eastern Regional Committee with its office at Calcutta.

2. In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the said Act, the Council hereby establishes the following Regional Committees, namely :—

- (i) the Central Regional Committee with its office at Bhopal;
- (ii) the North Western Regional Committee with its office at Chandigarh; and
- (iii) the South Western Regional Committee with its office at Bangalore.

[F. No. 4-5/CCF/REGU/RCS/94 (14)]

J. P. GUPTA, Member Secy.

नई दिल्ली, 21 मार्च, 1995

कां.प्रा० 905.—अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 की संख्या 52) (इसे आगे कथित अधिनियम संदर्भित किया गया है) की धारा 13 की उपधारा (1) के अनुसरण में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् एतद्वारा निम्नलिखित अध्ययन मंडल स्थापित करती है, अर्थात् :—

- (i) अखिल भारतीय व्यावसायिक शिक्षा मंडल;
- (ii) अखिल भारतीय तकनीशियन शिक्षा मंडल;
- (iii) अखिल भारतीय स्नातकपूर्व इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी अध्ययन मंडल;
- (iv) अखिल भारतीय स्नातकोत्तर इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी शिक्षा और अनुसंधान मंडल; और
- (v) अखिल भारतीय प्रबंध विज्ञान अध्ययन मंडल।

2. कथित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में परिषद् एतद्वारा निम्नलिखित अध्ययन मंडल स्थापित करती है, अर्थात् :—

- (i) अखिल भारतीय वास्तुकला शिक्षा मंडल;
- (ii) अखिल भारतीय नगर और ग्राम योजना शिक्षा मंडल;
- (iii) अखिल भारतीय होटल प्रबंध और खान-पान प्रौद्योगिकी मंडल;
- (iv) अखिल भारतीय भेषजीय शिक्षा मंडल; और

(v) अखिल भारतीय कंप्यूटर विज्ञान/इंजीनियरी व प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग मंडल।

[फा० 4-5/सीसीएफ/आरईजीयू/आरसीएस/94(13)]

जे०पी० गुप्ता, सदस्य-सचिव

New Delhi, the 21st March, 1995

S.O. 905.—The following Boards of Studies are hereby established by the All India Council for Technical Education, in pursuance of sub-section (1) of section 13 of the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987) (hereinafter referred to as the said Act), namely :—

- (i) All India Board of Vocational Education ;
- (ii) All India Board of Technician Education ;
- (iii) All India Board of Under-graduate Studies in Engineering and Technology ;
- (iv) All India Board of Post-graduate Education and Research in Engineering and Technology ; and
- (v) All India Board of Management Studies.

2. In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 13 of the said Act, the Council hereby establishes the following Boards of Studies, namely :—

- (i) All India Board of Architectural Education ;
- (ii) All India Board of Town and Country Planning Education ;
- (iii) All India Board of Hotel Management and Catering Technology ;
- (iv) All India Board of Pharmaceutical Education ; and
- (v) All India Board of Computer Sciences/Engineering and Technology and Applications.

[F. 4-5/CCF/RUGU/RCS/94 (13)]

J. P. GUPTA, Member Secy.

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 मार्च, 1995

का.आ. 906.—केन्द्रीय सरकार, भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 की धारा 36 की उपधारा 1 के अनुसरण में राजपत्र अधिसूचना संख्या 25/1/90-डी (एस ई बी) (एस.ओ. संख्या 3106), दिनांक 15-4-1994 में अधिसूचित केन्द्रीय सरकार और संघ राज्य क्षेत्र में संबंधित अथवा नियन्त्रणाधीन अधिष्ठापना के बोरे में श्री के.एन.सिन्हा के स्थान पर श्री बी.एम.रेड्डी, माय इंजीनियर (इन्स्पेक्टर-रेंट), केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षक के रूप में नामित करती है।

[स. 25/1/90-डी (एस ई बी)]

बी.के. शर्मा, उप सचिव

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 7th March, 1995

S.O. 906.—In pursuance of Sub-section 1 of Section 36 of the Indian Electricity Act, 1910, the Central Government hereby nominates Shri B. M. Reddy, Chief Engineer (Inspectorate), Central Electricity Authority as Electrical Inspector in respect of installations belonging to or under the control

of the Central Government and Union Territory as notified in the Gazette Notification No. 25/1/90-D(SEB) (SO No. 3106) dated 15-4-1994, vice Shri K. N. Sinha.

[No. 25/1/90-D(SEB)]

V. K. SHARMA, Dy. Secy.

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1995

का.आ. 907.—दिल्ली विकास (मु. योजना तथा क्षेत्रीय योजना) नियम, 1959 के नियम 5 के साथ गठित दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 10 (1) के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की क्षेत्रीय विकास योजना के प्रारूप को तैयार करने तथा उसके प्रकाशन के लिए सूचना।

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि :—

क. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के जोन "ए" (चार दीवारी शहर के अतिरिक्त) के लिए एक क्षेत्रीय विकास योजना प्रारूप तैयार कर लिया गया है।

ख. उसकी एक प्रति निरीक्षण के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यालय, भूतल, विकास मीनार में आगे पैरा 3 में उल्लिखित तारीख तक सभी कार्य दिवसों के दौरान प्रातः 11.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक उपलब्ध होगी।

2. इस प्रारूप योजना के सम्बन्ध में एतद्द्वारा आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं।

3. आपत्ति एवं सुझाव लिखित रूप में दायुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास भवन, नई दिल्ली-23, को सन् 1995 के जून महीने की 30 तारीख से पहले भेजे।

आपत्ति/सुझाव भेजने वाले व्यक्ति को अपना नाम एवं पता भी अवश्य देना चाहिए।

[फाइल नं. एफ. 1(8)/93-अईपी]

विश्व मोहन वसल, दायुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 24th March, 1995

S.O. 907.—Notice under section 10(1) of the Delhi Development Act, 1957 (No. 61 of 1957) read with rule 5 of the Delhi Development (Master Plan and Zonal Development Plan) Rules, 1959 of the preparation and publication of the draft of the Zonal Development Plan for the National Capital Territory of Delhi.

Notice is hereby given that :

- (a) A draft of a Zonal Development Plan for Zone 'A' (Other than walled city) in the National Capital Territory of Delhi has been prepared.

(b) A copy thereof will be available for inspection of the office of the Delhi Development Authority, on Ground Floor, Vikas Minar, I. P. Estate, New Delhi, between hours of 11 A.M. to 5 P.M. on all working days till the date mentioned in para '3' hereinafter.

2. Objections and suggestions are hereby invited with respect to this draft plan.

3. The Objection or suggestion may be sent in writing to the Commissioner-cum-Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, 'B' Block, I.N.A., New Delhi-23, before the 30th day of June, 1995.

Any person making the objection or suggestion should also give his name and address.

[No. F. 1(8)/93-ZP]

V. M. BANSAL, Commissioner-cum-Secy.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 मार्च, 1995

का.प्र. 908.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, मै. भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का महुदा क्षेत्र के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, (सं. 1) धनबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 1-3-95 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-20012/232/93-आई आर (कोल-1)]

ब्रज मोहन, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 1st March, 1995

S.O. 908.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, (No. 1), Dhanbad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Mohuda Area of M/s. BCCL and their workmen, which was received by the Central Government on the 1-3-95.

[No. L-20012/232/93-IR(Coal-I)]

BRAJ MOHAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. I, DHANBAD

In the matter of a reference under section 10(1)(d)(2-A) of the Industrial Disputes Act, 1947.

Reference No. 184 of 1994

Parties :

Employers in relation to the management of Mohuda Area of M/s. B.C.C. Ltd.

AND

Their Workmen

Present :

Shri P. K. Sinha, Presiding Officer.

Appearances :

For the Employers : Shri B. Joshi, Advocate.

For the Workmen : None.

STATE : Bihar

INDUSTRY : Coal

Dated the 20th February, 1995

AWARD

By Order No. L-20012/232/93-I.R. (Coal-I) dated 25/27-7-1994, the Central Government in the Ministry of Labour has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2-A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

"Whether the action of the General Manager, Mohuda Area of BCCL in denying to allow Sh. Rameshwar Dusadh, U/G Loader to join his duties is justified? If not, to what relief is the concerned workman entitled?"

2. The order of the reference was received in this Tribunal on 5-8-1994. Thereafter notice was issued to the sponsoring Union to file written statement. Though the notice was received, no written statement was filed on behalf of the sponsoring Union. Even on 6-2-1995 neither the concerned workmen nor any representative of the sponsoring Union was present.

3. It, therefore, appears that the sponsoring Union is not interested in pursuing the present dispute nor it has now any dispute with the management.

4. Therefore I render a 'no dispute' award in the present industrial dispute.

P. K. SINHA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 6 मार्च, 1995

का.प्र. 909.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 37 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार कन्टोनमेंट बोर्ड के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 1-3-95 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-13011/4/93-आई आर (डी यू)]

के वी वी उन्नी, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 6th March, 1995

S.O. 909.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Cantonment Board and their workmen, which was received by the Central Government on the 1-3-95.

[No. L-13011/4/93-IR(DU)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (MP)
CASE REF. NO. CGIT/LC(R)(199)/1994

BETWEEN

Shri Ramesh Kumar Patel represented through Shri Vishnu Kant Thakur, President, Cantonment Board Karamchhari, Sangh, C-48, Vijaynagar Extension Colony, Ranjhi, Jabalpur (MP).

AND

The Executive Managing Officer, Cantonment Board, Jabalpur (MP).

Presided in : By Shri Arvind Kumar Awasthy.

Appearances :

For Workman : Shri Vishnu Kant Thakur.

For Management : Mohd. Anward.

INDUSTRY : Cantonment Board DISTRICT : Jabalpur (MP)

AWARD

February 21, 1995

This is a reference made by the Central Government, Ministry of Labour, vide its Notification No. L-13011/4/93-IR(DU) Dated 4-11-1994, for adjudication of the following industrial dispute :—

“क्या प्रबन्धक एक्जीक्यूटिव आफिसर, कैंटोनमेंट बोर्ड जबलपुर (म.प्र.) के प्रबन्धकों द्वारा अपने कार्यालय आदेश सं. 135 दिनांक 21-1-93 द्वारा श्री रमेश कुमार पटेल, कम्पाउण्डर स्व. कुमारी उमा अवस्थी सहायक शिक्षक के घेतन से कटौती किये जाने कार्यवाही न्यायोचित है यदि नहीं, तो सम्बन्धित कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है।”

SCHEDULE

2. The statement of claim was filed by the Union and Shri Vishnu Kant Thakur, President of the Union has prayed therein that after reference was made by the Government the Officer of the Cantonment Board considered the case of the workman and the management has regularised the deduction of one day wages by sanctioning the leave to Shri R. K. Patel vide order No. 105 dated 6-12-1994. Therefore no dispute exists between the workman and the management. Consequently, no dispute award is passed. No order as to costs.

ARVIND KUMAR AWASTHY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 7 मार्च, 1995

का.आ. 910.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 6-3-95 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/121/91-आई आर बी-II]

बी.के.शर्मा, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 7th March, 1995

S.O. 910.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Central Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on 6-3-95.

[No. L-12012/121/91-IR(B-II)]

V. K. SHARMA, Desk Officer

ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (MP)
CASE REF. NO. CGIT/LC(R)(142)/1991

BETWEEN

Shri Ravikapoor Singh Thakur, represented through the Regional Secretary, Central Bank Employees Union C/o The Central Bank of India, Budhwari, Chhindwara (MP).

AND

The Regional Manager, Central Bank of India, Chhindwara (MP).

Presided in : By Shri Arvind Kumar Awasthy.

Appearances :

For Workman : None.

For Management : Shri N. K. Patel, Advocate.

INDUSTRY : Banking DISTRICT : Chhindwara (MP)

AWARD

February 17, 1995

This is a reference made by the Central Government, Ministry of Labour, vide its Notification No. L-12012/121/91-IR-B-2 dated 1st August, 1991, for adjudication of the following industrial dispute :—

SCHEDULE

“Whether the action of the management of Central Bank of India in terminating the services of Shri Ravikapoor Singh Thakur is justified? If not, to what relief is the workman entitled?”

2. This reference was made for adjudication of the industrial dispute in the year 1991. Since then as many as 10 dates were fixed for filing of statement of claim by the workman, but neither he appeared nor filed statement of claim. Therefore it appears that the workman is not interested in pursuing his case and this Court has no option but to close case and pass a no dispute award. No dispute award is passed. No order as to costs.

ARVIND KUMAR AWASTHY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 7 मार्च, 1995

का.आ. 911.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 6-3-95 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/168/86-डी II-ए आई आर बी-II]

बी.के.शर्मा, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 7th March, 1995

S.O. 911.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Central Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on 6-3-95.

[No. L-12012/168/86-D.IIA/IR(B-II)]

V. K. SHARMA, Desk Officer

ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (MP)
CASE REF. NO. CGIT/LC(R)(34)/1987
BETWEEN

Shri Mohd. Jalil, Sub-staff S/o Lal Mohd. (Nagar Nigam Wale), Nazirabad, Satna (MP).

AND

The Regional Manager, Central Bank of India, Regional Office, 601 Napier Town, Jabalpur (MP)-482 001.

Presided in : By Shri Arvind Kumar Awasthy.

Appearances :

For Workman : None.

For Management : Shri Patel, Advocate.

INDUSTRY : Banking DISTRICT : Jabalpur (MP)

AWARD

Dated : February 13, 1995

This is a reference made by the Central Government, Ministry of Labour, vide its Notification No. L-12012/168/86-D.II(A) dated 16th April, 1987, for adjudication of the following industrial dispute :—

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Central Bank of India in relation to their Satna Branch (MP) in terminating the services of Shri Mohd. Jalil, Sub-staff w.e.f. 27-12-84 is justified? If not, to what relief the workman concerned is entitled?"

2. My learned predecessor on 27-2-1991 passed the no dispute award and it is observed therein that both the parties failed to appear on 20-7-90, 31-10-90 and 27-2-91, it was further observed that the parties have no interest in prosecuting the case and the Court has no option, but to pass a no dispute award. However, after passing the no dispute award on 27-2-91 my learned predecessor restored the case and the award passed on 27-2-91 was set aside and the case was again posted for evidence of the parties. However, on 18-10-94 the workman did not turn up. Consequently, it is clear that the workman is not interested in pursuing the issue. As such no dispute award is hereby passed. Parties to bear their own costs.

ARVIND KUMAR AWASTHY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 7 मार्च, 1995

का.आ. 912.—श्रीमोक्षिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार विजया बैंक के प्रबंधन के संबंध नियोजकों और उनके कमकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट श्रीमोक्षिक विवाद में श्रीमोक्षिक अधिकरण, मद्रास के पंचसट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 6-3-95 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/33/86-डी. IV. ए/आई आर(वी-2)]
बी के शर्मा, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 7th March, 1995

S.O. 912.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Madras as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of

Vijaya Bank and their workmen, which was received by the Central Government on 6-3-95.

[No. L-12012/33/86-D.IV.A/IR(B-II)]
V. K. SHARMA, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL, TAMIL NADU.
MADRAS

Friday, the 28th October, 1995

Present :

Thiru K. Ponnusamy, M.A.B.L., Industrial Tribunal.
INDUSTRIAL DISPUTE NO. 37 OF 1987

(In the matter of the dispute for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the Workman and the Management of Vijaya Bank, Bangalore).

BETWEEN

The Workman represented by :
The Regional President,
Vijaya Bank Workers Organisation,
283, Pycrofts Road, Triplicane,
Madras-600 005.

AND

The Jt. General Manager,
Vijaya Bank, Personnel Department (IRS),
14, Trinity Circle, M. G. Road,
Bangalore-560 001.

Reference :

Order No. L-12012/33/86-D.IV(A), dated 6-4-1987,
Ministry of Labour, Govt. of India, New Delhi).

This dispute coming on for final hearing on Tuesday, the 18th day of October, 1994, upon perusing the reference, claim and counter statements and all other material papers on record and upon hearing the arguments of Tvl. Row and Reddy, and S. Vaidyanathan, Advocates appearing for the Workman and of Thiru S. Jayaraman, Advocate appearing for the Management and this dispute having stood over till this day for consideration, this Tribunal made the following :

AWARD

This reference has been made for adjudication of the following issue :

"Whether the action of the Management of Vijaya Bank in dismissing from service Sri V. Manikumar, Sub-Staff in the Tuticorin branch, of the Bank with effect from 27-7-1984 is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled?"

2. The claim of the petitioner briefly stated is as follows: V. Manikumar, the dismissed Sub-Staff is a member of the petitioner Union. A substantial section of the employees of the respondent bank are members of the Petitioner Union. He joined the respondent bank as a sub-staff on 17-2-1975. He had unblemished record of service till the issue of Charge sheet which led to his dismissal. He was issued a charge sheet dated 4-1-1983 for.

(i) delayed remittance of certain amounts to the Electricity Board towards payment of Electricity charges; and

(ii) for having collected Rs. 400/- on 1-9-82 from A. N. Solvaraj for opening 4 R.D. Accounts and having opened only one account for Rs. 100/-.

He gave a cheque Rs. 300 on 13-10-1982 with which three R. D. accounts were opened on 15-10-1982. He was charge sheeted for gross misconduct under Clause 19.5(f) of Chapter 19 of Bi-partite Settlement dated 19-10-1966 for "doing any act prejudicial to the interest of the bank or

gross negligence or negligence involving or likely to involve the Bank in serious loss". Even before he could offer his explanation, the Management had in their charge sheet pre-judged the matter that there was a *prima facie* ground for believing that he was guilty of gross misconduct. He gave an explanation dated 18-3-1983 denying the charges. The order of suspension dated 24-12-1982 was itself illegal because it was issued contrary to 19.2(a) and (b) of the Bi-partite Settlement according to which an employee can be placed under suspension only when the charge sheet has been issued. Charge sheet came to be issued only on 4/8-1-83, whereas he was placed under suspension on 24-12-1982. Suspension without issue of charge sheet is contrary to para 52.10(a) and (b) of the Sastry Award the terms of which are similar to the Bi-partite Settlement. Under paragraph 19(2)(b) of the Bi-partite Settlement, an employee can be placed under suspension pending such enquiry whereas the suspension order issued to him refers to pending disciplinary action. The question of action would come only, if he is found guilty at the domestic enquiry. If he had been suspended not pending enquiry but pending disciplinary action, this means the employer had already decided the issue. Even before the enquiry commenced, the Management had pre-judged the issue. The suspension is contrary to Clause 19(2)(b) of the Bi-partite Settlement. Even before the enquiry into the charge sheet could be over, the Management stopped his promotion to the clerical cadre during the year 1983. He was not given two annual increments that were due to him in February 1983 and 1984. It shows that the Management had already decided to punish him and in fact punished him. Regarding the filed charge namely, the delayed remittance of the amount given for the payment of Electricity Bill, the Disciplinary Authority unfortunately found the employee guilty in respect of all the four amounts. Regarding the sum of Rs. 173.07 it was drawn and paid by the employee towards electricity charges for the month of May and June 1980 and this has been affirmed by the Branch Manager. From Ex. M-6, it is seen that the same amount was drawn and given to the employee on 8-5-1981, for the payment of electricity charges and this amount was paid on the same day. Therefore, the amount was wrongly paid as representing electricity charges for May and June 1980, first on 22-8-1980 and second time on 8-5-81. This was later adjusted by the Electricity Department in the receipt dated 24-8-1981 for Rs. 209.70 (Ex. M-12) while paying the Electricity Bill for February and March 1981 (Ex. M-10) by actually paying only Rs. 36.33. Without realising this, the Disciplinary Authority had made it appear that the amount received on 22-8-1980 was remitted only on 24-8-1981. As regards item nos. 2 and 4 namely Rs. 96.00 and Rs. 415.96 the receipt from the Electricity Department, Ex. M-7 though dated Rs. 5.81, does not show that these amounts were remitted only on those days. If there was delayed remittance, the Electricity Board would have disconnected the power supply in the mean time which was not the case here. The Bill itself shows that if the amount is not paid within one week, the electricity will be cut off, in accordance with Section 24 of the Indian Electricity Act, 1910. Even assuming at the worst there was a slight delay in the remittance of the Electricity Bill amount, it does not automatically lead to the conclusion that the employee had temporarily misappropriated the amount. The Disciplinary Authority failed to see that the remittance of Electricity Bills was not a part of his normal duties. Due to pressure of work he could not go there in time. He was the only peon available in that Branch. There was no rule to the effect that if the amount was not remitted to the Electricity Board, it should be remitted back to the Bank. The charge sheet also did not state that the employee was asked to remit back the amount and draw it again for remittance without appreciating these facts, the Authority found the employee guilty of misappropriation on the sole ground of delayed payment, before issuing the charge sheet, they had issued a Memo Ex. M-19 on 1-4-1982. He is forced to give an explanation. On the lines suggested by the Branch Manager assuring him that no action will be taken and the matter will be closed. Actually for seven long months, no charge sheet was issued, which only confirm the case of employee, that the matter had been treated and closed. But strangely, on 24-12-1982, he was suspended. The delayed remittance of Electricity Bill amounts was also added as a charge alongwith the alleged incident dated 1-9-1982. Regarding the second charge of not opening the R. D. Account in time, if the complaint was true and had been made on 22-9-1982 itself, the Branch

Manager would have issued a Memo a/cast by Post to the employees' residential address then and there. If the complaint was true, the Branch Manager would have further withheld the identification letter to be given to the workman to sit for the examination. The Complaint is in English. On 13-10-82, the Cheques were forcibly got from the employee. On 15-10-82, three R.D. Accounts were opened if the customer wanted to genuinely open the R.D. Account he would have remitted further amount. No further amount was remitted. After the R.D. accounts were opened on 15-10-1982 which only proves that the cheques were got out of force, some papers were burnt, in the presence of the employee and the Branch Manager. This only confirms the case of the employee that the cheques were got under the pretext that the report would be destroyed and nothing would happen to him. Therefore, the findings on the charge are not justified. The Management taking advantage of the helpless nature of Peon, got a statement and dismissed him from service. Even in the matter of punishment, there has been discrimination. It is not as if employees who have been found guilty of misappropriation have been instantaneously dismissed. For example, Kumaresan, a Clerk working in the Head Office was charged and found guilty of misappropriation of some amount, in the despatch section during 1982, but he was only warned. U. Abdul Salam a Peon working in the Quilon branch in Kerala who was suspended on the charge sheet for misappropriating Rs. 1600 from customer's account in April, 1984 was later reinstated in June 85, after imposing a punishment of stoppage of two increments. But unfortunately, the Bank has dealt with the employee severely when he was really not guilty. His unblemished record of service was not really taken into account. The action of the Management was therefore not bona fide. The Disciplinary Authority while issuing Second Show Cause notice dated 26-3-1984 has stated that there are no extenuating circumstances which implies that there was something against the employee in his past record of service. The Disciplinary Authority did not choose to give those particulars in which case the employee would have suitably answered. Hence the dismissal based on such a Second Show Cause notice is bad. The Appellate Authority in his orders dated 14-11-1984 states that there are several complaints against the employee without choosing to disclose the same. Hence the appeal of the employee was dismissed on undisclosed materials. He was only a Peon. His past 7 years of undismissed record of services was not taken into account. The punishment is really harsh. He has got a widowed mother and sisters to support. He is the only bread winner of the family. The order of suspension and dismissal are contrary to the Bipartite Settlement. Others have been dealt with differently. In any event, this Hon'ble Tribunal may be pleased to interfere under Section 11-A as the punishment is highly excessive. The employee has a good past record and comes from a very poor family.

3. The defence of the respondent briefly stated is as follows :

Petitioner was working as a Peon in the Tuticorin branch of the bank. During his tenure of his service as peon, he has misappropriated amounts of cash handed over to him for the purpose of paying electricity bills for consumption of electricity on several occasions. On 4 occasions he did not pay the amount to the Tamil Nadu Electricity Department on the date when the amounts were handed over to him. However, the amounts so handed over were paid to the Electricity Board after the lapse of several months. He was charge sheeted for the above misconduct and he was called to submit his explanation. On 24-5-82, the workman submitted his explanation wherein he did not specifically deny the charges. The Management however with a view to give him an opportunity and also to comply with the principles of natural justice, order an enquiry into those charges. On 1-9-82 petitioner visited the business premises of one A. N. Selvaraj firm and requested whom to open account with the branch of the bank during the Saving and Service months. Mr. Selvaraj had given him cash of Rs. 400 four opening for recurring deposit accounts with monthly instalment of Rs. 100 in the following names. Alongwith the initial deposit of

Rs. 400 the depositor had also handed over the recurring deposit opening forms to Manikumar. Instead of opening four recurring deposit accounts of Rs. 100 each, as per the instructions of the customer, he opened only one account in the name of A. K. Salvaring on 1-9-82 and remitted only a sum of Rs. 100 to the credit of the said Recurring deposit account and misappropriated the balance of Rs. 300. He did not open the other three R.D. Accounts though the money and the application forms were handed over to him by the customer. When the customer demanded the other three pass books, while handing over the one which was opened on 1-9-82, petitioner had informed the customer that the bank staff are very busy and therefore the other books were not written. The customer gave a complaint to the Manager on 29-9-82. Petitioner was on leave for the period from 22-9-82 to 12-10-82. On 2-10-82 he visited the Branch Manager's quarters to obtain identification letter for attending an interview for promotion. The Branch Manager at that time enquired will regard to the non-opening of the recurring deposit accounts of Selvaraj. The workman relied stating that he did not receive the R.D. Account opening form. He returned to work after the expiry of leave on 13-10-82. On that day the Branch Manager asked him about the non-opening of the R.D. Accounts. Only after making such enquiry, the petitioner opened the accounts at 3.00 p.m. in the names viz., 1. S. Muthukamal, 2. S. Vimala, 3. Nirmala, by giving 3 cheques in favour of the bank drawn by him. Thus it will be clear from the act of the employee that he had misappropriated the amounts paid by the customer for the opening of the R.D. Accounts. The employee was issued charge memo and he was called upon to submit his explanation. It is needless to state that in the charge sheet, the entire details of the misconduct committed by him was set out and he was charged under the relevant provisions of the rules applicable to the bank employees belonging to his category, the rule being the awards and bipartite settlement, entered into between the bank and the workmen. The petitioner was issued an order of suspension on 21-12-1982. The charge sheet was issued on 8-1-83. He submitted his statement of defence on 18-3-83 wherein he denied the charges levelled against him. Therefore the Management ordered an enquiry into those charges. The enquiry was conducted at the Tuticorin branch during the period 21-9-83 to 27-9-83. The petitioner participated in the enquiry and he was afforded all the opportunities. The enquiry was conducted strictly in accordance with the principles of natural justice. If however, this Tribunal comes to the conclusion that the enquiry is not fair and proper, the respondent herein prays that this Tribunal may be pleased to permit the respondent to lead evidence before this Tribunal and prove the charges. The enquiry officer found the charges proved and found the petitioner guilty of all the charges. The Disciplinary Authority communicated to the petitioner the proposed punishment by letter dated 26-3-84 and also directed him to show cause as to why he should not be dismissed from service for the proved misconduct which has been proved in a properly conducted domestic enquiry. The petitioner submitted his reply to the notice on 30-4-84 which is more or less reiteration of his statement of defence and also an attack on the conduct and propriety of the enquiry. The Management also afforded another opportunity to the petitioner to make oral representation. On 19-6-84 the petitioner took part in that enquiry and made oral representations. The Disciplinary authority by order dated 27-7-84 imposed punishment of dismissal of the workman. The petitioner also filed an appeal against the final order of the disciplinary authority on 11-9-84. The petitioner in his written appeal submitted to the Appellate Authority made a request for oral hearing alongwith his defence representative. He was permitted to have the defence representative in the

oral hearing of the Appeal therefore the Appellate Authority viz., the Chairman Managing Director. The Appellate Authority after considering his appeal and oral representation passed a detailed order enumerating the reasons as to how he is unable to interfere with the punishment of dismissal on 14-11-84. A mere perusal of the order passed by the Appellate Authority would clearly reveal the entire facts and also justified the Management's action in having dismissed the employee from service. The petitioner was employee of a Bank and the Management of the bank is answerable to its customers. The petitioner who has received money from the customer with a view to open R.D. account having not done so, cannot be retained in the bank's service. If he is allowed to be retained it will completely spoil the image of the bank in the minds of the customers. The bank is fully justified in having dismissed the petitioner from service. The petitioner was dismissed for a proved misconduct which was proved in a properly conducted enquiry in accordance with principles of natural justice wherein the workman fully participated. The petitioner's contention that his suspension pending enquiry is contrary to Section 19.12 (a) and (b) is not correct. It is too well settled that it is open to the employer to keep an employee under suspension pending enquiry. Even assuming that there are no powers to suspend an employee before issuance of charge sheet, the only requirement is that the employee may have to be paid full wages for the 10 days during which period he has been kept under suspension even before issuance of charge sheet. The Management has got power to suspend an employee even before issuance of charge sheet, as per the Bipartite Settlement. The reference to the judgement of the Allahabad High Court would have no relevance since the facts in those are such that the Management did not have any specific powers to suspend pending enquiry, before issuance of charge sheet and they did not also pay full wages. At any rate this question will have only academic view since the larger issue with regard to the dismissal of the employee has been referred to before this Tribunal. The contention of the petitioner that his suspension pending enquiry the employer has already decided and prejudged the issue is absolutely devoid of any substance. On the other hand the relevant documents viz., proceedings and findings and other documents would clearly reveal that the charges have been proved and he has been dismissed for a proved misconduct. His further contention that the Management has issued the order of Suspension contrary to Cl. 9(2) (b) of the Bipartite Settlement will again fail for the reasons stated above. His contention that the Management has stopped his promotion in the clerical cadre during the year 1983 and that they have not given two annual increments for the year 1983-84 and that the above act of the Management clearly shows that they have prejudged the issue and determined to punish him is without any substance for the simple reason that he has been dismissed for a proved misconduct. The petitioner's attempt to substantiate that the findings of the Enquiry Officer are not based on any evidence and that he has been wrongly found guilty is futile. The petitioner received the amounts and failed to remit the same in time. The fact that the Electricity department has not chosen to disconnect the supply would not necessarily lend support to the petitioner to show that he has not committed misconduct. The petitioner has more or less admitted the delay in remittance of the electricity charges. The petitioner's reason for justifying the delay in any event is not sustainable. The disciplinary authority has properly found the employee guilty of the misappropriation. The allegation that the Management forced the petitioner to give an explanation on the line suggested by the Branch Manager is also false. The petitioner admitted the misconduct in M-20. It is not open to him now to turn round and contend that the explanation was extracted from him. His further contention that the Management

in their charge sheet issued after 7 months which was issued for an incident that took place on 1-9-82 and included an earlier misconduct committed by him with a view to punish him is not correct. The Management has issued the charge sheet for the misconduct and the same has been proved in a properly held enquiry. There is no element of any malafides or victimisation which has been pleaded or proved before the Enquiry Officer. On other hand the misconduct has been proved. The contention of the petitioner that the Management not having issued memo by post to the employee then and there i.e. immediately after the complaint made on 22-9-82 would only show that the complaint with regard to the opening of the R.D. Account itself is without substance and the further contention that the Management having withheld the identification letter would establish that the complains are not true is without substance. There is no necessity for a customer to come forward with a complaint with a view to dismiss an employee of the bank. The customer has handed over Rs. 400 during the Savings and Service month to the petitioner with a view to open R.D. Account in 4 different names. The petitioner on the other hand did not open the account nor had he returned the money. Having realised the guilt he himself issued cheques drawn on the bank and the balance 3 R.D. Accounts were opened. The contention that the cheques were forcibly extracted from him is baseless. If the petitioner is allowed to be retained in employment it will create a very bad impression in the minds of the Customers of the Bank. The Bank itself cannot survive without the customers involvement. The Management is fully justified in dismissing the employee from service. The allegation that his unblemished past record has not been taken into account is devoid of any merits. It is not as if past record is without blemish. The relevant factors have been taken into account before imposing the punishment of dismissal. The allegation that the disciplinary authority did not give particulars with regard to the past record and other extenuating circumstances and therefore the petitioner was handicapped in giving his reply is not correct. The 2nd show cause notice has narrated all the details and all the factors have been taken into account, which is clear from a more reading of the 2nd show cause notice. The allegation that the Appellate Authority has not chosen to disclose the complaint levelled against the workman and therefore the order dismissing the appeal is void is without any merits. On the other hand the order of the Appellate Authority has considered point by point which was mentioned in the appeal and ultimately thought it fit to confirm the order of dismissal. The allegation that the punishment is harsh and disproportionate is without substance. Having regard to the fact that he is employed in a bank where customers come and have transactions and having regard to the fact that the misconduct committed by the workman will considerably tarnish the image of the bank, it is not possible to retain this kind of employees in banks, which survive only because of the customers' patronage. Therefore, there is no merit to interfere with the punishment under 11-A of the I. D. Act. This is a proper and fit case where this Tribunal should exercise the discretion to confirm the punishment of dismissal than to interfere with the same. The charges have been proved beyond doubt and only for the proved charges the petitioner has been dismissed.

4. The issue for determination is :

"Whether the action of the Management of Vijaya Bank in dismissing from service Sri V. Manikumar, Sub-Staff in the Tuticorin branch of the bank, w.e.f. 27-7-84 is justified ? If not, to what relief is the workman concerned entitled ?"

5. The issue.—Admittedly the claimant/petitioner worked as a Sub-Staff in the respondent-bank till his dismissal from service on 27-7-84. The respondent furnished the list of witnesses to be examined by the Enquiry Officer on the prosecution side, is borne out by Ex. M-1. The petitioner was charge sheeted is made out by Ex. M-2. The petitioner was required to submit his explanation within 7 days from the date of receipt of the charge sheet, is evidenced by Ex. M-2. The petitioner submitted his explanation pleading innocence, is substantiated by Ex. M-3. The respondent gave Rs. 173.07 to the petitioner on 22-8-80 to remit the same towards the electricity charges, is disclosed by Ex. M-4. The said amount was remitted by petitioner on 24-8-81 after a delay of nearly about 11 months and 22 days. A sum of Rs. 296.72 was debited in the respondent's account on 8-5-81 is revealed by Ex. M-5. A sum of Rs. 533.23 was remitted towards Electricity charges bill for the month of May, June and September, 1980, is revealed by Ex. M-6. A sum of Rs. 96 was debited in the account of the respondent for the Electricity charges on 10-2-81, is substantiated by Ex. M-7. A sum of Rs. 140.50 was debited in the account of the respondent, for the electricity charges on 14-3-81 is established by Ex. M-8. Electricity charges of Rs. 209.70 was remitted on 25-6-81, is evidenced by Ex. M-9. Rs. 36.63 was debited to the account of the respondent towards electricity charges is made out by Ex. M-10. Rs. 209.70 was remitted towards electricity charges on 24-8-81 is borne out by Ex. M-11. Rs. 271.52 was remitted by the respondent towards the electricity charges is borne out by Ex. M-12. The respondent remitted Rs. 415.96 towards the electricity charges on 19-10-81 is evidenced by Ex. M-13. Rs. 414.44 was remitted by the respondent towards electricity charges on 4-4-82 is borne out by Ex. M-14. The respondent-bank remitted Rs. 271.52 towards electricity charges on 4-1-82, is made out by Ex. M-15. The petitioner received Rs. 173.07 from the respondent on 22-8-80 to remit the same towards the electricity charges due from the respondent and he remitted the same on 24-8-81. The petitioner received Rs. 96 on 11-2-81 from the respondent, to remit the same towards electricity charges and he remitted the same on 8-5-81. The petitioner received Rs. 140.50 on 14-3-81 from the Respondent to remit the same on 8-5-81. The petitioner received Rs. 415.56 on 19-10-81 from the respondent to remit towards electricity charges and he remitted the same on 4-1-82. The petitioner has admitted the receipt of the aforesaid amount from the respondent to remit the same towards electricity charges due from the respondent, that he failed to remit the amounts properly. There is a long delay on the part of the petitioner in remitting the electricity charges. The explanation of the petitioner that late remittances of electricity charges is due to family difficulties and mental agony is not legally sustainable. The petitioner has not given the details of his alleged mental agony and family difficulties for later remittances of electricity charges.

6. The petitioner was on leave for a short period and the long delay of remittance of the money towards electric charges is not properly explained by the petitioner. The petitioner pleaded for the condonation of the late remittances of electricity charges due from the respondent to the Tamil Nadu Electricity Board. The Regional Office wrote the letter to the Personnel Manager, Personnel Department, that the petitioner received a cash of Rs. 300 from the party and he remitted the same after a long delay of more than 5 months, that in the formal enquiry conducted by the Branch Manager in the presence of Clerk, Deivanayagam, the petitioner admitted his guilt, that the petitioner has not produced credit advices for Rs. 300 and he has admitted in writing the delayed remittances of the electricity charges that he has subsequently paid electricity charges, and his action is highly irregular, that he is a potential danger to the Vijaya Bank, Tuticorin Branch and suitable action must be taken against him immediately. is evidenced by Ex. M-16. The Branch Manager of the Vijaya Bank, Tuticorin Branch sent a letter to the Regional Manager, Madras that typographical errors crept in the complaint against the petitioner regarding the name of the party namely Ms. Radha and the date of incident is 22-8-81, is evidenced by Ex. M-16.

7. The Electricity Board official came to the respondent-bank premises to disconnect the electricity connection. The respondent requested the electricity department official to wait for some time, and not to disconnect the electricity connection, that Branch Manager came to know that the petitioner misappropriated the money given to him for remittance towards electricity charges, that the petitioner produced a single receipt for Rs. 533.23 and petitioner falsely threw the became on the Tamil Nadu Electricity Board, that the concerned clerk refused to issue duplicate receipt for the previous payments, and the petitioner failed to produce receipt for Rs. 415.96 plus electricity bills for April, May and June 1981 inspite of repeated reminders and the Branch Manager sent the Accountant Padmanabhan Naik to Electricity Office on 30-12-81 and thereafter the Branch Manager came to know the irregularities committed by the petitioner, by not remitting the electricity charges, is borne out by Ex. M-17. The petitioner paid back Rs. 300 to Radha from her he received a cash of Rs. 300 is evidenced by Ex. M-17. That amount was given by Radha to the petitioner towards the jewel loan obtained by her from the respondent-bank. The Regional Office sent a letter to the Branch Manager, Tuticorin, to furnish the details with regard to the irregularities committed by the petitioner, is made out by Ex. M. 18. The petitioner did not remit Rs. 300 received from Radha, towards her jewel loan account. The petitioner was directed to submit his explanation, is borne out by Ex. M. 19. The petitioner submitted his explanation, is made out by Ex. M. 20. In his explanation he has denied the receipt of Rs. 300 from Radha. In Ex. M. 20, he submitted the delayed remittance of electricity charges and the belated remittance of electricity charges is not only wrong but also serious, and is due to his mental agony and family difficulties. He sought the pardon of the respondent, for the lapse and negligence on his part. He purchased a moped by applying a loan from the respondent-bank branch of Tuticorin, that he sent the certificate of registration to Regional Transport Authority for payment of the Tax and he would produce certificate of registration and Moped to the branch at a later point of time. His explanation for the delayed remittance of Electricity charges does not stand for a moment's scrutiny. The petitioner has not promptly remitted the electricity charges and subsequently remitted the same is evidenced from Ex. M. 21. The petitioner received Rs. 300 from Radha and he failed to remit the same to the bank and misappropriated the same, is proved by Ex. M. 22. The petitioner received Rs. 100 from the Account holder Selvaraj to open Recurring deposit account. His contention that he gave 3 applications to Selvaraj to get the signature of three customers and he could not open recurring deposit account for three customers on account of his work load, forgetfulness and Selvaraj has not sent the recurring deposit account forms cannot be countenanced. He issued a self cheque for Rs. 300 to the Branch Manager, Tuticorin and he pleaded for pardon, is evidenced by Ex. M. 22, established that he received Rs. 300 from Radha and failed to remit the same towards her jewel loan account.

8. The petitioner received Rs. 100 to open a recurring deposit account in the name of Ruth Kamalam and he failed to do so. He issued a self cheque for Rs. 100 each on 30-10-1982. The respondent bank branch at Tuticorin is made out by Ex. M. 23. to M. 24. Vimala Mariaselvi requested the Branch Manager Tuticorin to open recurring deposit in her name, is evidenced by Ex. M. 26. Similarly Ruth Kamalam requested the Branch Manager Tuticorin, to open a recurring deposit account in her name, for remittance at the rate of Rs. 100 p.m. for one year, is evidenced by Ex. M. 27. S. N. Nirmala Guanaselvi requested the Branch Manager to open a recurring deposit account, to remit Rs. 100 p.m. for one year is borne out by Ex. M. 28. Selvaraj requested the Branch Manager to open recurring deposit account remittance at the rate of Rs. 100 p.m. for one year is made out by Ex. M. 29 Vimala Mariaselvi remitted Rs. 100 towards her recurring deposit account, is made out by Ex. M. 30. Ruth Kamalam remitted Rs. 100 in the respondent's bank branch at Tuticorin is proved by Ex. M. 31. Nirmala Gananaselvi remitted Rs. 100 in the branch bank is established by Ex. M. 32. Selvaraj remitted Rs. 100 in the Branch Bank is substantiated by Ex. M.33.

9. The explanation of the petitioner was unsatisfactory. Domestic enquiry was ordered and conducted, is proved by Ex. M-34. The petitioner was suspended pending domestic enquiry, is borne out by Ex. W-1. He misappropriated the money given to him for payment of the electricity charges, is established by Ex. W-2. He misappropriated the sum of Rs. 300 from Radha, is proved by Ex. W-4, and thereby committed grave misconduct is made out by Ex. W-2. He was charge sheeted is evidenced by Ex. M-4. His counsel submitted his written statement argument is borne out by Ex. M-5, mainly attacking the domestic enquiry. The Enquiry Officer conducted the domestic enquiry, following the procedure prescribed by law and the provisions of the Act. The principles of natural justice, equity and good conscience, are complied with in the domestic enquiry. The petitioner has been given opportunity to defend charges levelled against him and to cross-examine the witnesses on the side of the Management and adduce evidence on his side. The Enquiry Officer has no bias against the petitioner. The Enquiry Officer after weighing the evidence and considering the documents, came to the conclusion that the charges levelled against the petitioner are proved by the legal evidence. Prime facie case has been made out against the petitioner. The domestic enquiry does not suffer from any infirmity. The enquiry is not vitiated by any defects or mistake. The findings of the domestic enquiry Office are not perverse and as such this Tribunal cannot disregard the findings of the Enquiry Officer. The jurisdiction of this Tribunal is restricted. This Tribunal has no jurisdiction to re-appreciate the evidence. This Tribunal is not an Appellate Authority sitting over the findings of the Enquiry Officer. The domestic enquiry conducted by the Enquiry Officer is fair and proper. The Disciplinary Authority concurred with the findings of the Enquiry Officer. The Disciplinary Authority sent the second show cause notice to the petitioner as to why the proposed punishment should not be imposed against him, is borne out by Ex. W-7. The petitioner submitted his explanation to the second show cause notice, is borne out by Ex. W-8.

10. The Disciplinary Authority gave personal hearing to the petitioner. The disciplinary authority after considering all the aspects dismissed the petitioner from service with immediate effect, is borne out by Ex. W-9. The petitioner preferred an appeal to the Chairman/Managing Director. The appellate Authority after giving personal hearing to the petitioner, dismissed the appeal confirming the order of dismissal passed by the disciplinary authority, is made out by Ex. W-10 and the order of dismissal is proper, is made out by Ex. W-11. The Regional President of the Union sent a petition to the Regional Labour Commissioner (Central), Madras requesting to reinstate the petitioner to service, is established by Ex. W-12. The petitioner's request for conciliation proceedings was rejected by the Regional Labour Commissioner, Madras since it is not a fit case for conciliation proceedings, is borne out by Ex. W-13. The Regional President, of the Union sent a letter to Asst. Labour Commissioner (Central) is evidenced by Ex. W-14. The Conciliation failed is proved by Ex. W-15. The Tribunal can interfere by invoking the power under Section 11-A only when it is desirable or necessary and not always, is held in 1988 II LLJ P. 263 CHRISTIAN MEDICAL COLLEGE EMPLOYEES' UNION Vs. CMC and 1991 II LLJ page 372 BIRENDRA Vs. STATE OF WEST BENGAL AND OTHERS. There is no reason warranting interference by this Tribunal by invoking the power under Section 11-A. Consideration of past records of service is an unilateral obligation is held in 1984 II LLJ P. 105 ACC Ltd., Vs. SRIVATSHVA. Misappropriation of Canteen tickets worth about Rs. 25 by the employee was dismissed, and the Court should not interfere with the punishment for the misconduct is held in 1986 II LLJ P. 85 SEERLAN Vs. MAKHANIL DEY Vs. UNION OF INDIA. There should not be any discrimination is held in 1967 II LLJ P. 782. In the present case, there is no discrimination. The past records of service of the petitioner were considered by the disciplinary authority. The action of the petitioner is a grave misconduct. His action tarnished the image of the respondent, he public will loose confidence in the respondent on account of the misconduct on the part of the petitioner. The continuation of the petitioner in service, is highly prejudicial to the interest of the respondent. It is not desirable to allow the petitioner to continue in service. There is no justifiable

ground to reinstate the petitioner in service. The punishment imposed on the petitioner is in proportion to the crime.

11. By taking the aforesaid aspects into consideration, this Tribunal comes to the irrefutable conclusion that the action of the Management of Vijaya Bank in dismissing from service Shri V. Manikumar Sub-staff in the Tuticorin branch of the bank w.e.f. 27-7-84 is justified. The first part of the issue is found against the petitioner. The second part of the issue does not arise for consideration.

In the result, an award is passed rejecting the claims of the petitioner. No costs.

Dated, this the 28th day of October, 1994.

THIRUK PONNUSAMY, Industrial Tribunal

WITNESSES EXAMINED

For both sides : None.

DOCUMENTS MARKED

- Ex. W-1/13-12-82—Order of suspension issued to Thiru V. Manikumar (copy).
- Ex. W-2/4-1-83—Charge sheet issued to Thiru V. Manikumar (copy).
- Ex. W-3/18-3-83—Explanation by Thiru V. Manikumar (copy) to Ex. W-2.
- Ex. W-4/29-10-83—Written arguments of the Presenting Officer in support of charges framed against Thiru V. Manikumar in the domestic enquiry (copy).
- Ex. W-5/30-11-83—Defence Counsel's written arguments in the enquiry proceedings (copy).
- Ex. W-6/24-2-84—Findings of the Enquiry Officer (copy).
- Ex. W-7/17-3-84—Second Show Cause Notice issued to Thiru V. Manikumar (copy).
- Ex. W-8/30-4-84—Explanation by Thiru V. Manikumar to Ex. W-7 (copy).
- Ex. W-9/27-7-84—Dismissal order issued to Thiru V. Manikumar (copy).
- Ex. W-10/11-9-84—Appeal preferred by Thiru V. Manikumar to the Appellate Authority against his dismissal order (copy).
- Ex. W-11/14-11-84—Order of Appellate Authority (xerox copy).
- Ex. W-12/20-5-85—Dispute raised by Thiru V. Manikumar before the Regional Labour Commissioner (Central), Madras (copy).
- Ex. W-13/30-8-85—Reply filed before the Regional Labour Commissioner (Central), Madras to Ex. W-12 (copy).
- Ex. W-14/27-1-86—Reply by Thiru V. Manikumar to Ex. W-13 (copy).
- Ex. W-15/12-3-86—Conciliation Failure Report (copy).

For Management :

- Ex. M-1—List of witnesses on behalf of Management (Xerox copy).
- Ex. M-2/4/8-1-83—Charge sheet issued to Thiru V. Manikumar (Xerox copy).

Ex. M-3/18-3-93—Reply by Thiru V. Manikumar to Ex. M-2 (Xerox copy).

Ex. M-4/22-8-80—Debit slip for Rs. 173.07 regarding amount paid to Thiru V. Manikumar for payment of lighting charges (Xerox copy).

Ex. M-5/8-5-81—Debit slip for Rs. 296.72 regarding amount paid to Thiru V. Manikkumar for payment of lighting charges (Xerox copy).

Ex. M-6/8-5-81—Receipt for payment of electricity charges of Rs. 533.23 (Xerox copy).

Ex. M-7/10-2-81—Debit slip for Rs. 96 regarding amount paid to Thiru V. Manikumar for payment of lighting charges for the month of September, 1980 (Xerox copy).

Ex. M-8/14-3-81—Debit slip for Rs. 140.50 regarding amount paid to Thiru V. Manikumar for payment of lighting charges for the month of October, 1980 (Xerox copy).

Ex. M-9/25-6-81—Receipt for payment of electricity charges of Rs. 209.70 (Xerox copy).

Ex. M-10/10-7-81—Debit slip for Rs. 36.63 being the lighting charges for the month of February, March (Xerox copy).

Ex. M-11/24-8-81—Receipt for payment of electricity charges of Rs. 209.70 (Xerox copy).

Ex. M-12—Receipt for payment of electricity charges of Rs. 144.44 and Rs. 271.82 (2 Nos) (Xerox copy).

Ex. M-13/19-10-81—Debit slip for Rs. 415.96 being the lighting charges for the month of April, May and June, 1981 (Xerox copy).

Ex. M-14/4-1-82—Tamil Nadu Electricity Board's receipt for payment of Rs 144.44 being the electricity charges (Xerox copy).

Ex. M-15/4-1-82—Tamil Nadu Electricity Board's receipt for payment of Rs. 271.52 being the electricity charges (Xerox copy).

Ex. M-16/24-2-82—Letter from the Regional Manager to the Personnel Manager, Personnel Department of the Management Bank enclosing complaint against Thiru V. Manikumar (Xerox copy).

Ex. M-17/17-4-82—Letter from Tuticorin branch of the Management-Bank to the Management-Bank regarding irregularities committed by Thiru V. Manikumar with enclosure (Xerox copy).

Ex. M-18/4-2-82—Letter from Regional Office of the Management-Bank to the Branch Manager, Tuticorin regarding complaint against Thiru V. Manikumar (Xerox copy).

Ex. M-19/1-4-82—Charge memo from Tuticorin branch of the Management-Bank issued to Thiru V. Manikumar (Xerox copy).

Ex. M-20/24-5-82—Reply by Thiru V. Manikumar to Ex. M-19 (Xerox copy).

Ex. M-21/20-3-82—Letter from Thiru V. Manikumar admitting that his conduct committed by him (Xerox copy).

Ex. M-22/21-10-82—Letter from Head Office of the Management-Bank to the Joint General Manager, Advances C&D Zones, H.O. Bangalore enclosing complaint against Thiru V. Manikumar (Xerox copy).

Ex. M-23/13-10-82—Xerox copy of cheque for Rs. 100 given by Thiru V. Manikumar in favour of Vijaya Bank on the account of Ruth Kamalim.

- Ex. M-24/13-10-82—Xerox copy of cheque for Rs. 1 given by Thiru V. Manikumar in favour of Vijaya Bank on the account of Nirmala Gnanaselvi (Xerox copy).
- Ex. M-25/13-10-82—Xerox copy of cheque for Rs. 100 given by Thiru V. Manikumar in favour of Vijaya Bank on account of Vimala Maria selvi (Xerox copy).
- Ex. M-26/15-10-82—Application for opening of Recurring Deposit Account in Vijaya Bank by S. Vimala Mariaselvi (Xerox copy).
- Ex. M-27/15-10-82—Application for opening of Recurring Deposit Account in Vijaya Bank by S. Ruth Kamalam (Xerox copy).
- Ex. M-28/15-10-82—Application for opening of Recurring Deposit Account in Vijaya Bank by S. Nirmala Ganaselvi (Xerox copy).
- Ex. M-29/1-9-82—Application for opening of Recurring Deposit Account in Vijaya Bank by A. N. Selvaraj (Xerox copy).
- Ex. M-30—Ledger extract of R.D. A/c No. 122/82 in the name of S. Vimala Mariaselvi (Xerox copy).
- Ex. M-31—Ledger extract of R.D. A/c No. 123/82 in the name of S. Ruth Kamalam (Xerox copy).
- Ex. M-32—Ledger extract of R.D. A/c. No. 124/82 in the name of S. Nirmala Gnanaselvi (Xerox copy).
- Ex. M-33—Ledger extract of R.D. A/c. 77/82 in the name of A. N. Selvaraj (Xerox copy).
- Ex. M-34—Proceedings of the Enquiry Officer (copy).

नई दिल्ली, 7 मार्च, 1995

का.आ. 913.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार रिजर्व बैंक आफ इंडिया, कानपुर के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 6-3-95 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12011/21/86-डी II-ए]

पी.जे. माईकल, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 7th March, 1995

S.O. 913.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Reserve Bank of India, Kanpur and their workmen, which was received by the Central Government on the 6-3-1995.

[No. L-12011/21/86-D II-A]
P. J. MICHAEL, Desk Officer

ANNEXURE

Before Sri B K Srivastava Presiding Officer Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court Pandu Nagar Deoki Palace Road Kanpur Industrial Dispute No. 142 of 1986
In the matter of dispute between :
The Chief Secretary

R.B.I. 'D' Class Union,
C/o Reserve Bank of India
Mall Road Kanpur

AND

The Manager

Reserve Bank of India
Mall Road Kanpur

AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour, New Delhi, vide its notification no. L-12011/21/86-D.II(A) dated 10-12-86 has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :—

Whether the action of the management of Reserve Bank of India, Kanpur in not regularising 42 Tikka Mazdoor man who have completed more than 240 days of actual work as mentioned in the annexure is justified? If not, to what relief the workman concerned are entitled?

2. In the instant case the Employer vide its application dt. 21-2-95 requestd that since the matter in controversy has been resolved between the Employer and the Union raising dispute and have filed a settlement arrived at between the Employer and the All India Reserve Bank Workers Federation including Class IV Employees Federation to which the present Union is affiliated and the reference be decided accordingly in the light of the settlement.

3. The Union raising the present dispute was called upon to submit on this point on 28-2-95. On 28-2-95, when the case was taken up none appeared for the Union present in the case. Thus it appears that the Union is not interested in prosecuting its case.

4. Therefore, in view of the above facts and circumstances, the reference is answered in the light of the settlement 23-7-93.

5. Reference is answered accordingly.

Dt. 28-3-95.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer.

नई दिल्ली, 7 मार्च, 1995

का.आ. 914.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार नार्दन रेलवे, लखनऊ के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 6-3-95 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-41012/95/92-आईआर(डी यू)]

पी.जे. माईकल, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 7th March, 1995

S.O. 914.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Northern Rly., Lucknow and their workmen, which was received by the Central Government on the 6-3-95.

[No. L-41012/95-92-IR(DV)]

P. J. MICHAEL, Desk Officer

ANNEXURE

Before Sri B K Srivastava Presiding Officer Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court Pandu Nagar Deoki Palace Road Kanpur Industrial Dispute No. 85 of 1993

The Working President

U.R.K.U. 96/196 Roshan Bajaj Lane

Ganesh Ganj Lucknow.

And

The Dy. C.M.E. C & W Shops

Alambagh Lucknow.

AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour, vide its notification no. L-41012/95/92-IR. (DU) dated 30-9-93, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :—

Whether the action of the management of Dy. C.M.E.(W) Carriage and Wagen Shops Alambagh Northern Rly. Lucknow, in awarding the punishment of a reduction of rank Cobbler to the post of Khalasi Helper to Sri Surendra Kumar T. No. 215F is justified? If not, what relief the concerned workman is entitled?

2. In the present case, the Union without filing its statement of claim moved application dt. 5-2-94 with the prayer that the Union has no objection if the case is closed as the workman is not interested in prosecuting the case any more. The Union has also filed an application signed by the workman concerned to this effect.

3. In view of the facts and circumstances stated hereinabove the reference has become redundant and a no claim award is given in the case. Consequently the workman is entitled to no relief.

4. Reference is answered accordingly.

Dt. 28-2-95.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer.

नई दिल्ली, 8 मार्च, 1995

का.आ. 915.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सी पी डब्ल्यू डी के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नई दिल्ली के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 8-3-95 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-42012/22/91 आई आर (डी यू)]

के. बी. बी. उन्नी, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 8th March, 1995

S.O. 915.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby published the award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of C.P.W.D. and their workmen, which was received by the Central Government on 8-3-1995.

[No. L-42012/22/91-IR(DU)]

K.V.B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI GANPATI SHARMA : PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL : NEW DELHI

I.D. No. 118/91

In the matter of dispute between :

Shri H. S. Vats, President,

C.P.W.D. Mazdoor Union, E-26 (Old Quarter), Raja Bazar, Baba Khark Singh Marg, New Delhi.

Versus

The Director, General of Works.
C.P.W.D., Nirman Bhawan.
New Delhi.

विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नई दिल्ली के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 8-3-95 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/20/90-आई आर बी-2]

बी.के. शर्मा, डेस्क अधिकारी

APPEARANCES :

New Delhi, the 8th March, 1995

Shri Nand Lal for the workman.
Shri Pyare Lal Ex. Engineer for the Management.

AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour vide its Order No. L-42012/22/91-IR(DU) dated 24/26-9-1991 has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication:

“Whether the action of the management of CPWD, Nirman Bhawan, New Delhi in not granting the permanent status and not paying the regular scale of sweepers to Smt. Gudo though working since 1980 was justified? If not, to what relief the workman is entitled to?”.

2. The workman did not appear and his representative made statement that no dispute award in this case may be given as the workman wanted to withdraw this dispute. In view of this situation it appears that no dispute exists between the parties to be adjudicated by this Tribunal. I, therefore, pass a No Dispute award in this case leaving the parties to bear their own costs.

February 20, 1995.

GANPATI SHARMA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 8 मार्च, 1995

का.आ. 916.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बैंक आफ इंडिया के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निम्नलिखित औद्योगिक

S.O. 916.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on 8-3-1995.

[No. L-12012/20/90-IR(B-II)]

V. K. SHARMA, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI GANPATI SHARMA : PRESIDING
OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL : NEW DELHI
I.D. No. 69/90

In the matter of dispute between :
Maha Sachiv,
Bank of India Staff Union (Delhi),
through Bank of India,
12-B, Connaught Place,
New Delhi-110001.

Versus

Zonal Manager,
Bank of India,
Jiwan Bharti Building,
124, Connaught Place,
New Delhi-110001.

APPEARANCES :

None for the workman.

Shri Rajiv Singh for the management.

AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour vide its Order No. L-12012/20/90-I.R.-(B-2) dated Nil has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication :—

“Whether the action of the management of Bank of India, New Delhi not assigning the duty of ALPM/AEPM Operator duty to senior most clerk Shri Ved Prakash in Karol Bagh Branch and

assigning to a Junior on 20-1-1987 was justified? If not, to what relief the workman is entitled to?".

2. The case was fixed for evidence of the workman but the workman did not appear inspite of many opportunities having been given to him. Even the representative did not come inspite of an undertaking given by Mr. H. M. Ahuja who appeared as proxy for representative for the workman on the previous date. In view of this situation it appears that the workman is not interested in pursuing this matter and no dispute award is given in this case leaving the parties to bear their own costs.

GANPATI SHARMA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 8 मार्च, 1995

का.आ. 917.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार नादर रेलवे, नई दिल्ली के प्रबंधन के संबंध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 7-3-95 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या-एल 41012/58/90/आईआर(ड्यु)]

पी.जे. माईकल, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 8th March, 1995

S.O. 917.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Northern Railway and their workmen, which was received by the Central Government on the 7-3-1995.

[No. L-41012/58/90/IR(DU)]
P. J. MICHAEL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI B. K. SRIVASTAVA PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT PANDU NAGAR DEOKI

PLACE ROAD, KANPUR.

Industrial Disputes No. 38 of 1991

In the matter of dispute between :

The Divisional Secretary,
Uttar Rly. Karamchari Union,
T-40/K Haidar Canal Colony,
Charbagh Lucknow.

AND

General Manager,
Northern Railway,
Baroda House,
New Delhi.

AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour, New Delhi, vide its notification No. L-41012/58/90.I.R. DU dated 2-4-1991, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal:—

Whether the General Manager, Northern Rly. New Delhi, is justified in promoting Shri Shyam Lal and superceding Sri A. P. Dikshit in the grade of Rs. 700-900 w.e.f. 1-1-1984? If not what relief the workman concerned entitled to?

2. Now it is not necessary to give details of the case, as the workman Sri A. P. Dikshit has moved an application in this case paper no 29 on 21st November, 1994 informing that he now does not press his claim.

3. In view of above application the reference is answered against the workman. Consequently he is not entitled for any relief.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 8 मार्च, 1995

का.आ. 918.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मिलिटरी फार्म डिपो के प्रबंधन के संबंध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक

विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नई दिल्ली के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 8-3-95 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-14012/4/91-आईआर (डीयू)]

के. वी. बी. उन्नी, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 8th March, 1995

S.O. 918.—In pursuance of the Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby published the award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Military Farm Depot Roorki and their workmen, which was received by the Central Government on 8-3-1995.

[No. L-14012/4/91-IR(DU)]

K.V.B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI GANPATI SHARMA : PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL : NEW DELHI
I.D. No. 119/91

In the matter of dispute between :
Shri Desh Raj S/o Shri Bharat Ram,
Village Mohanpura, P.O. Dandhera Phatak,
Roorki Distt. Haridwar, Uttar Pradesh.
Versus

The management of Military Farm Depot.,
Roorkee, Distt. Haridwar, U. P.

APPEARANCES :

Shri R. B. Pathak for the workman.

Shri O. P. Yadav with Sh. Ravi Kumar
Jhams for the management.

AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour vide its Order No. L-14012/4/91-IRDU dated 27-9-1991 has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication :—

“Whether the action of Military Farm Depot, Rurkee in terminating the service of Shri Deshraj, s/o Shri Bhartoo Ram w.e.f. 13-2-90 is justified? If not to what relief is the workman entitled?”

2. The case was fixed for management evidence when the parties arrived at settlement and made a joint statement stating therein that the workman has received letter No. E-50/RKE/PC dated 13-12-1994 sent by Lt. Col. J. S. Kadyan, Officer Incharge, Military Farm Meerut Cantt. The terms and conditions laid down in the said letter were acceptable to the workman and he would report duty within 10 days. In view of this statement no dispute award may be given in this case.

3. In view of the statement made by both the representative for the parties the matter stands settled and no dispute award is given in this case leaving the parties to bear their own costs.

February 6, 1995.

GANPATI SHARMA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 8 मार्च, 1995

का.आ. 919—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एस डी ओ (टेलीग्राफ) के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निश्चित औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, उड़ीसा (भुवनेश्वर) के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 8-3-95 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-40012/77/91-आई आर (डीयू)]
के. वी. बी. उन्नी, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 8th March, 1995

S.O. 919.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby published the award of the Industrial Tribunal, Orissa Bhubaneswar as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of S.D.O. (Telegraphs) and their workmen, which was received by the Central Government on 8-3-95.

[No. L-40012/77/91-IR-(DV)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

INDUSTRIAL TRIBUNAL : ORISSA : BHUBANESWAR
PRESENT :

Sri P. K. Tripathy, M.A. LL.B.,
Presiding Officer. Industrial Tribunal.

Orissa, Bhubaneswar.

Industrial Dispute case No. 36 of 1991 (Central)

Dated, Bhubaneswar, the 20th February, 1995.

BETWEEN :

The management of S.D.O. (Telegraphs), Berhampur,
Dist Ganjam-760004 . . . First party-management

AND

Their workman Sri Panchanan Patra, C/o. Sri B. P.
Mohanty, Advocate, P.O. Sakhigopal, Dist :
Puri-7520014, Second party-workman

APPEARANCES :

Sri A. B. Mishra & Sri Patnaik, Advocates,—For the
first party-management.

Sri S. B. Dash & Sri R. N. Acharya, Advocates.—For
the second party-workman.

AWARD

As per Order No. L-40012/77/91-IR(DU) dt. 19-11-91, the Government of India in the Ministry of Labour, in exercise of powers conferred upon them by clause (d) of sub-section (i) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) (for short 'the Act') have forwarded the following schedule of reference for adjudication. For the sake of convenience, the above described first party and the second party are hereinafter referred to as the management and the workman respectively

SCHEDULE

"Whether the action of the management of S.D.O., Telegraphs, Berhampur in terminating the services of Shri Panchanan Patra, Ex-Casual Mazdoor w.e.f. 3-7-87 is justified? If not, to what relief the workman concerned is entitled to?"

2 In the above context, the case of the workman is that with effect from 19-6-85 he alongwith 12 other persons were engaged as casual labourers continuously till 3rd July, 1987 on the basis of payment of wage @ Rs. 7.25 paise per day upto March, 1986, @ Rs. 8.25 paise till March '87 and then @Rs. 9.25 paise per day till July '87. At the time of receiving payment he was signing on the muster roll. During the period of engagement he worked with efficiency and to the best satisfaction of his employer. In their letter No. IPM/1986/87/129 dated 3-6-87 the management served a notice to terminate his service w.e.f. 3-7-87 without assigning any reason for such action and thereafter retrenched him w.e.f. 3-7-87. Though alongwith him 12 other workmen were retrenched yet later on many of them were again provided with employment by the management. The workman has contended that the retrenchment is illegal and ill-motived. He has thus, prayed for reinstatement with full back wages and for regularisation of his service.

In his additional claim statement the workman has further contended that at the time of his retrenchment many juniors were retained in service and apart from that new hands have been taken to manage the work. He has further contended that there is sufficient work load with the management justifying his employment.

3. In his written statement the first party has advanced the case that the second party-workman was engaged as a daily rated casual worker in August '85 though the said engagement was made in contravention of the ban order dated 30-3-85 and the instruction of the department of Telecom communicated in their letter No. 270/6/84-STN dated 30-3-85 and letter No. 269/130/78-STN dated 1-10-84. The workman alongwith 12 other casual labourers were thus retrenched with effect from 3-7-87 as per the instruction of the department and with a view to implement the decision of the Apex Court reported in A.I.R. 1992 S.C. Page-130. The workman was engaged intermittently and not continuously and he did not work for 240 days in any of the years during 1985, 1986 and 1987. The workman worked for 144 days during August to December '85, for 204 days in 1986 and for 107 days from January to May '87. The first party has further denied to the allegation of 644 GI/95—14,

engaging any of the retrenched workers or employing any new hands. Thus, on facts the contentions of the workman in the claim statement have been disputed. Besides that, the first party has challenged the maintainability of the proceeding on the ground that the Telegraph Department (i.e., the S.D.O., Telegraphs, Berhampur) is not an 'industry'. the claim of the workman is barred by Limitation and under such circumstance, the reference is not maintainable.

4. Keeping in view the aforesaid pleadings, issues have been framed as hereunder :—

Issues

- (1) Whether the reference is barred by Limitation ?
- (2) Whether the second party is a 'workman' and whether the case is maintainable ?
- (3) Whether the action of the management of S.D.O., Telegraphs, Berhampur in terminating the services of Shri Panchanan Patra, Ex-casual Mazdoor w.e.f. 3-7-87 is justified ?
- (4) To what relief, if any, the concerned workman is entitled to ?

5. So far as this reference is concerned, on 4-2-93 an ex parte award was passed and thereafter the petition of the management to set aside the ex parte award was rejected vide order dated 13-12-93 in Restoration Misc. case No. 15/93. The management challenged that order in O.J.C. No. 2510/94. Hon'ble Court allowed the writ application of the management and the operative portion of the order of the Hon'ble Court reads as hereunder :—

"xx xx xx In the aforesaid premises, we quash the impugned award passed by the tribunal subject to the condition that the Union of India shall pay a cost of Rs 1000 to Mr. Mohanty appearing for the employee within four weeks from today. If the cost as directed is paid then the tribunal is further directed to dispose of the proceeding by giving opportunity both to the employee and to the employer, within two months thereafter. Both the writ applications are disposed of with the aforesaid directions."

After receipt of a copy of the order, since the parties did not appear voluntarily, notice in registered post was issued to them and thereafter on 12-1-95 the management appeared and filed a memo stating that the cost as ordered by the Hon'ble Court was paid to the workman on 1-11-94. On 16-1-95 the workman appeared and admitted to have received the cost in time. Hearing of the case had not commenced till then though the targetted period expired on 3-1-95. Hence, vide letter No. 226 dated 16-1-95 the Tribunal prayed to the Hon'ble Court for extension of time till end of March, 1995 relating to disposal of the reference. However, all possible expeditious steps were taken and hearing of argument was closed on 9-2-95 and that follows with this Award.

6. Issues Nos 1 and 2 relate to the maintainability of the proceeding. So far as it relates to the question of limitation, the management has not pressed that point, in as much as, no evidence or law has been brought into record in support of the contention that the proceeding is barred by any provisions in the Limitation Act. On the other hand, it is the well known fact available from the Statute that the provisions in the Limitation Act prescribing the period of limitation for institution of case are not applicable to industrial dispute cases. Hence, issue No. 1 is answered in negative.

7. While challenging the maintainability of the proceeding, the main thrust of argument of the management is that office of the S.D.O. (Telegraphs) is not an 'industry' and therefore, the proceeding under the Act is not maintain-

able. Disputing the aforesaid contention of the management, it is argued by the workman that on facts and evidence it is proved that the first party management is an 'industry'. Both the parties have relied upon certain citations on this score. Before dealing with the aforesaid citations, the facts and evidence may be briefly stated.

In their respective pleadings, both the parties have asserted on their respective contentions. The workman has asserted that the management is an 'industry' and the latter has asserted that it is not an 'industry'. At the time of trial, the management examined M.W. No. 3 Sri Bir Sadhana Pal, S.D.O. (Telegraphs), Berhampur. In his examination-in-chief he stated that the management is a Central Government Department and it is functioning for the purpose to provide telephone lines to the consumers and to maintain the same and the department does not do any business being a purely Government office. In the cross-examination, he has stated the Telegraph office dealing with technical staff does not run during the normal office hours of 10 A.M. to 5 P.M. but at different hours, telephone exchanges are being operated by machines and technical staffs are being engaged to operate the same and such offices run round the clock and the employees are engaged shiftwise. He has further stated that machines are being operated with the help of power i.e., electricity and battery and in that connection, the management purchases electricity from the State Electricity Board which realises the tariff treating the management as a commercial establishment. He has also admitted that the management realises subscription and periodical rent of the telephone instruments and the telephone connection given to the subscribers and the salary and wages are being paid from that amount and the surplus is being deposited in the State exchequer. He has candidly admitted that the management is a commercial establishment. After the aforesaid evidence being in record perhaps it does not lie in the mouth of the management to further canvas its point that the management is not an 'industry' or 'industrial establishment'. Nonetheless, the management has canvassed and pursued that point. The following discussions of the citations from both the sides would indicate that the stand of the management is not sustainable.

The management has relied upon the decision reported in A.I.R. 1978 S.C. Page-548 (Bangalore Water Supply & Sewerage Board, Appellant V. A. Rajappa & others Respondents). It may be noted here that when the matter came-up before the Hon'ble Supreme Court to propound as to what 'industry' means as per the definition in Section 2(i) of the Act, at that time the definition of the term 'industry' was different than at present. In as much as, as per the Amendment of the year 1982, the definition of the term 'Industry' has gone a revolutionary change perhaps keeping in view the remarks of the Hon'ble Supreme Court in the above noted decision. Therefore, the interpretation of the term 'industry' on the basis of the old definition is of little assistance to the management. Be that as it may, in the above decision of the Hon'ble Supreme Court even keeping in view the then existing ambiguous definition, their Lordships have been pleased to pronounce that what is meant by the term 'industry' and how it should be construed. In that connection, two relevant paragraphs i.e., paragraphs-126 and 161 of the said judgment are quoted below :

"126. The first is one where the enterprise, like any other, yields profits but they are siphoned off for altruistic objects. The second is one where the institution makes no profit but hires the services of employees as in other like business but the goods and services which are the output are made available, at low or no cost, to the indigent needy who are priced out of the market. The third is where the establishment is oriented on a humane mission fulfilled by men who work, not because they are paid wages, but because they share the passion for the cause and derive job satisfaction from their contribution. The first two are industries, they third not. What is the test of identity whereby these institutions with eleemosynary inspiration fall or do not fall under the definition of industry?"

"161. 'Industry' as defined in S. 2(i) and explained in Banerji (AIR 1953 SC-58) has a wide import.

(a) Where (i) systematic activity, (ii) organised by co-operation between employer and employee (the direct and substantial element is chimerical) (iii) for the production and/or distribution of goods and services calculated to satisfy human wants and wishes (not spiritual or religious but inclusive of material things or services geared to celestial bliss i.e. making, on a large scale prasad or food) prima facie, there is an industry in that enterprise.

(b) Absence of profit motive or gainful objective is irrelevant, be the venture in the public, joint, private or other sector.

(c) The true focus is functional and the decisive test is the nature of the activity with special emphasis on the employer-employee relations.

(d) If the organisation is a trade or business it does not cease to be one because of philanthropy animating the undertaking.

II. Although Section 2(i) uses words of the widest amplitude in its two limbs, their meaning cannot be magnified to overreach itself.

(a) 'Undertaking' must suffer a contextual and associational shrinkage as explained in Banerji and in this judgment so also, service, calling and the like. This yields the inference that all organized activity possessing the triple elements in I (supra) although not trade or business, may still be 'industry' provided the nature of the activity viz. the employer-employee basis, bears resemblance to what we find in trade or business. This takes into the fold 'industry' undertakings, callings and services, adventures 'analogous to the carrying on of trade or business.' All features, other than the methodology of carrying on the activity viz. in organizing the co-operation between employer and employee, may be dissimilar. It does not matter, if on the employment terms there is analogy.

III. Application of these guidelines should not stop short of their logical reach by invocation of creeds, cults or inner sense of incongruity or outer sense of motivation for or resultant of the economic operations. The ideology of the Act being industrial peace, regulation and resolution of industrial disputes between employer and workmen, the range of this statutory ideology must inform the reach of the statutory definition. Nothing less, nothing more.

(a) The consequences are (i) professions, (ii) Clubs (iii) educational institutions, (iv) co-operatives, (v) research institutes, (vi) Charitable projects and (vii) other kindred adventures, if they fulfil the triple tests listed in I (supra), cannot be exempted from the scope of Section 2(j).

(b) a restricted category of professions, clubs, co-operatives and even gurukulas and little research labs, may qualify for exemption if, in simple ventures, substantially and going by the dominant nature criterion, substantively, no employees are entertained but in minimal matters, marginal employees are hired without destroying the non-employee character of the unit.

(c) If in a pious or altruistic mission many employ themselves, free or for small honoraria or like return, mainly drawn by sharing in the purpose or cause such as lawyers volunteering to run a free legal services, clinic or doctors serving in their spare hours in a free medical centre or ashramites working at the bidding of the holiness, divinity or like central personality, and the services are supplied free or at nominal cost and those who serve are not engaged for remuneration or on the basis of master and servant relationship, then, the institution is not an industry even if stray servants, manual or technical, are hired. Such eleemosynary or like undertakings alone are exempt—not other generosity, compassion, developmental passion or project.

IV. The dominant nature test;

- (a) Where a complex of activities, some of which qualify for exemption, others not, involves employees on the total undertaking, some of whom are not 'workmen' as in the University of Delhi case (AIR 1963 SC 1873) or some departments are not productive of goods and services if isolated even then, the pre-dominant nature of the services and the integrated nature of the departments as explained in the Corporation of Nagpur (AIR 1960 SC 675) will be the true test. The whole undertaking will be 'industry' although those who are not 'workmen' by definition may not benefit by the status.
- (b) Notwithstanding the previous clauses, sovereign functions, strictly understood, (alone) qualify for exemption, not the welfare activities or economic adventures undertaken by government or statutory bodies.
- (c) Even in departments discharging sovereign functions, if there are units which are industries and they are substantially severable, then they can be considered to come within S. 2(j).
- (d) Constitutional and competently enacted legislative provisions may well remove from the scope of the Act categories which otherwise may be covered thereby.

(V) xx xx xx xx xx xx."

Applying the aforesaid test and keeping in view the above noted evidence of M.W.No. 3 it leaves no room for doubt that the management is an 'industry', in as much as, there existed relationship of employer and employee between the first party and the second party and the first party-managemnt systematically carries on commercial activities of supplying telephone lines and realising rent for the same and to maintain the department from out of such income and in depositing the profit with the Government exchequer. In this connection, the other decisions cited by the management is found distinguishable. It may be noted that in 1983 Lab. I.C. Page-83 (State of Punjab V. Sh. Kuldip Singh), the point for consideration was whether the construction and maintenance of National and State highways by the State comes within the ambit of 'industry'. In the said case, the Hon'ble Punjab & Haryana High Court did not find existence of any of the ingredients as propounded in the Bangalore Water Supply case (supra) and accordingly propounded that such department of the State is not an 'industry'. The aforesaid ratio is distinguishable because in that case the concept of business or commercial activities was totally absent with that department whereas in the present case the commercial activities have been admitted by M.W. No. 3. In O.I.C. No. 686 of 1994 (alongwith O.I. Cs. 2748, 2758 to 2760 of 1984 and 3049 of 1986) while considering the matter relating to applicability of the provisions of E.S.I. Scheme under the Act, 1952, the Hon'ble Orissa High Court propounded that the Works Department of the Government of Orissa in carrying out the construction and maintenance of roads and buildings is not an 'industry' as per the aforesaid decision of the Bangalore Water Supply. That decision of the Hon'ble Court is also distinguishable on facts and circumstances as stated above.

8. On the other hand, in the decision reported in 1985 Lab. I.C. page-1770 (Rabindra Kumar Prusty V. Govt. of Orissa), the Hon'ble Orissa High Court have been pleased to propound that the Irrigation Division of the State Govt. is an 'industry', in as much as, its aim and objectives are for distribution of water for the purpose of irrigation to satisfy human needs and though it was a benevolent act of the State Government with absence of profit motive, yet income could be derived from pisciculture and collection of water rent. Their Lordships have also followed the principles in Bangalore Water Supply case (supra) and decided the case accordingly. In 1983 Lab. I.C. 1884 (Bijoy Kumar Bharti and others Vs. State of Bihar & others), the Hon'ble Patna High Court in a full bench decision have also been pleased to propound that the employees of the Command Area Development Agency and Bihar Hill Area Lift Irriga-

tion Corporation is an 'industry'. In 1987 Lab. I.C. page-89 (The P.W.D. Employees Union & others V. State of Gujarat & others), the Hon'ble Gujarat High Court have been pleased to propound that the workmen i.e., the M.M. Rs. of P.W.D. (Irrigation) Department engaged for the purpose of construction and maintenance of medium size irrigation dam are workmen and the said department is an 'industry'.

The aforesaid ratios have got applicability to the facts and circumstances which are identical in the present case.

9. As per the aforesaid discussions of the facts and evidence and the ratios, it is held that the management is an 'industry'. Since the second party-workman worked as a casual mazdoor under it, therefore, he is a 'work man' within the meaning of Section 2(s) of the Act and since the matter relates to his retrenchment/termination of job, therefore, the reference is maintainable. The issue No. 2 is answered accordingly.

10. Before going to consider the next issue, it is just and proper to dispose of another contention raised by the management regarding the jurisdiction of this Tribunal to adjudicate the reference. According to the management, the Telegraph Department is governed by the provisions in the Indian Telegraphs Act and relating to service matters, the Central Administrative Tribunal is competent to decide the matter, hence this Tribunal has no jurisdiction to decide the matter relating to service conditions of employees like the workman. In support of that contention, the management has relied upon the decision reported in AIR 1993 S.C. Page-382 (Union of India Vs. Deep Chnad Pandey). The workman has repelled the aforesaid argument and contended that this Tribunal has the jurisdiction. The ratio cited by the management is not applicable and distinguishable, inasmuch as, in the cited case the Hon'ble Supreme Court have been pleased to propound that according to the provisions in Section 14 of the Administrative Tribunal Act, 1985, the jurisdiction of the Courts have been excluded relating to the service matter of the employees of the Central Government (Union of India) hence, the Hon'ble Madhya Pradesh High Court had no jurisdiction to exercise the writ jurisdiction to entertain the claim of the employee, whereas in the case at hand it does not relate to an employee governed by the provisions in the Statute of the Indian Telegraphs Act or the service conditions prescribed their service rules. Apart from that, Industrial Disputes Act is a special Statute prescribing a forum to the aggrieved workmen to ventilate their grievance through proper channel relating to the breach in the service conditions or the contract, if any, made by the employer. Under such circumstance, this Tribunal has jurisdiction to deal with the case.

11. Coming to the factual aspect of the case relating to refusal of employment with effect from 3-7-87, it is found from the pleadings of the parties that the workman describes the same as an act of retrenchment in violation of the provision in Section 25-F of the Act whereas the management asserts that refusal of employment was under compelling circumstance and the same was implemented legally and correctly. Various contentions have been made on this aspect and they are to be dealt with one after the other, as hereinafter.

12. The workman has stated in the claim petition as well as in his evidence that he was engaged with effect from 19-6-85. In that connection, he has proved Ext. 2, an extract from the muster roll showing the period of engagement. It appears from Ext. 2 that he had been engaged from August, 1985. W.W. No. 2 Satyavadi Behera, who is a Line Inspector, has stated in his evidence that the workman worked as a Mazdoor from 1985 to 1987. He has not stated as to from which month of 1985 the workman was employed. W.W. No. 3 has made a bald assertion that the workman was engaged since June 1985. The case of the management is that the workman was engaged from August '85. The conflicting evidence adduced by the workman goes to show that he was not engaged since June '85. In that connection, though he has prayed Ext. 2 which substantiated the case of the management but thereafter the workman has not tendered any other documentary evidence to prove that he had been engaged from June '85. Hence, the case of the workman that he had been engaged from June '85 is not acceptable. The workman relying

on a decision reported in 1993 (II) O.L.R. page-141 (Sri Himanshu Sekhar Sharma V. Presiding Officer, Labour Court & others), contended that the management should have produced the relevant records and registers to disprove the contention of the workman regarding his employment from June '85. Keeping in view the distinguishable facts and circumstances of the present case, it is found that the cited ratio is not applicable. In that connection, it may be noted that the management granted the certificate Ext. 2 and the workman relied upon the same and exhibited as evidence from his side. Apart from that, there was no statement from the side of the workman stating that in June or July '85 he had signed in the muster roll and had received the payment. He did not take any step even to request the Tribunal to call for those muster rolls. Under such circumstance, after sleeping over the matter till the date of hearing of argument, the workman cannot get rid of the lacuna by contending that the material should have been collected by the Court for proper adjudication of the matter. In that context, it may further be noted that when parties are adducing evidence and does not seek assistance of the Tribunal in any manner, as an impartial umpire the Tribunal should not show interestedness towards the case of either of the party. If the parties fail to produce documents for proper adjudication of the matter, in that case of course the Tribunal may call for the relevant documents. But when the parties have adduced evidence, both oral and documentary and have not sought for the assistance of the Court to call for any record or register, in such a case the Tribunal can not suo motu trade out the relevant documents and thereafter call for them from the custody of the management. Thus, in this case when the workman himself has adduced evidence which does not prove his stand but proves the case of the management regarding the initial date of management, at that stage the Tribunal could not have called for the documents, whose particulars were not known, with a view to support the contention of the workman. On an assessment of the above noted evidence in record, it is held that the workman was engaged with effect from August 1985 and not from 19-6-85.

13. Though it is the admitted case of the parties that as per the notice, Ext. 1, the workman was refused employment, yet at the stage of argument the workman has contended that he was not served with retrenchment notice and he was not paid the retrenchment compensation and therefore, the retrenchment is in violation of the provisions in Section 25-F of the Act. Since there existed the relationship of employer and employee between the management and the workman and the workman has been refused employment by way of termination of service with effect from 3-7-1987, therefore, as per the ratio reported in AIR 1976 SC page-1111 (State Bank of India V. Sundara Money), the termination of service of the workman is 'retrenchment'. Under such circumstance, it is to be found out whether the provisions in Section 25-F of the Act have been complied with. In that connection, the management has contended that though it has served the notice, Ext. 1 one month before the termination of service, yet the management was not bound to comply with the provisions of Section 25-F of the Act because of the fact that the workman had not continuously worked for a period of one year by the date of his retrenchment. Apart from that, since the management in implementing the direction of the Hon'ble Supreme Court in the case of Daily Rated Casual Labour employed under P & T Deptt. through Bharatiya Dak Tar Mazdoor Manch V. Union of India & others, (reported in A.I.R. 1987 S.C. Page-2342) had to regularise the services of certain casual employees employed prior to 1983, it became necessary to terminate the services of the casual workers engaged after 30-3-83 and in accordance with that the aforesaid order of termination was passed. The workman disputing the aforesaid contention argued that he has worked for 240 days preceeding the date of his retrenchment and therefore, as per the provisions in Section 25-B of the Act he has worked for a period of one year and was entitled to the retrenchment benefit.

14 From the pleadings and the evidence, it is the admitted position that the management did not pay retrenchment compensation to the workman. Though the workman in his evidence has given a conflicting version regarding the receipt of the notice, Ext. 1 (relating to termination of his service) but W.W. No. 2 has admitted that he served the notice of

termination on the workman. From such evidence though it is found that the notice of termination was served but it was not in accordance with the provisions in Section 25-F of the Act, in as much as, the notice of termination was issued on 3-6-87 intimating the workman to terminate his service with effect from 3-7-87. The evidence from the side of the management does not show the date of service of the notice and W.W. No. 2 has also not stated about the date on which he served the notice. When the workman, as W.W. No. 1, has disputed to have received the notice on 3-6-87, even if the notice was served on him between 3-6-87 and 3-7-87 then also it can be reasonably concluded that the notice was not served one month before the date of termination. Thus, the notice was not served in accordance with the provisions in Section 25-F of the Act, if at all the requirements of Section 25-F of the Act are to be complied with by the management.

15. As per the provisions in Section 25-F of the Act, a workman who has been in continuous service for at least a period of one year by the date of retrenchment, he is entitled to retrenchment benefits as provided in that section. Section 25-B of the period of one year includes the actual In sub-section (1) the period of one year includes the actual period of service and the uninterrupted period on account of sickness, authorised leave, accident or legitimate strike or lock-out or cessation of work due to no fault of the worker. If that type of continuous service for a year is not qualified, then sub-section (2) provides that if a worker has worked out for 240 days in a period of 12 calendar months preceeding the date with reference to which the calculation is to be made, then it will be deemed that he has worked for a period of one year. The same interpretation has been given to the term under consideration and principles have been propounded by the Hon'ble Courts in the authorities cited by the workman viz. 1980 Lab. I.C. Page-1292 (Surendra Kumar Verma V. Industrial Tribunal-cum-Labour Court, New Delhi), AIR 1981 SC page-1253 (Mohan Lal V. Management of M/s. Bharat Electronics Ltd.), 1986 Lab. I.C. Page-98 (Workmen of American Express International Banking Corporation, V. Management of American Express International Banking Corporation), AIR 1991 SC Page-1286 (Rabinarayan Mohapatra V. State of Orissa & others) and Vol. 72 (1991) C.L.T. page-404 (Chakradhar Tripathy V. State of Orissa & others).

16. Reverting to the facts in hand, it is found from Ext. 2 that during the first spell of employment between August 1985 to June 1986 i.e. during eleven months, according to the management, the workman had worked for 290 days. From July to October 1986 the workman did not work and thereafter from November 1986 till 3-7-1987 he worked for 196 days. The aforesaid calculation is on the basis of the facts mentioned in Ext. 2 and the pleadings in the written statement of the management. If the short break periods of a day or two in each month during the aforesaid period will be counted in favour of the workman (so as to include Sundays and holidays), then it comes to 315 days during the first spell and 214 days during the second spell. Because of the break of service for four months between July to October 1986 the workman did not work for a continuous period of 12 months preceeding the date of termination. On the other hand, he worked for about nine months between November 1986 to 3-7-1987 and the total days of work including Sundays if will be counted in favour of the workman, then it comes to 214 days. Hence, the workman has not worked for a period of 240 days during the period of 12 months preceeding the date of termination with reference to which the calculation is made. In that connection, it may be mentioned that the workman has not led any evidence to prove that during the aforesaid break period either he was sick and on leave or that due to non-availability of work he was not given employment or any such other ground to cover-up for ingredients of Section 25-B(1) of the Act. Under such circumstance, the provision in Section 25-F was not required to be complied with by the management for granting the retrenchment compensation, in as much as, the workman did not work for 240 days in the preceding 12 months from the date of retrenchment and even he did not work for a year as per Section 25-B(1) of the Act.

17. It appears from Ext. A to G besides the decision reported in AIR 1987 S.C. page-2342 (supra) that with a view to regularise the services of large number of casual workers employed through out the country by the management, termination of services of the casual workers was made who had been engaged after March, 1993.

18. Because of the aforesaid facts and circumstances, in a way the action of the management is justified. Persons like the workman were being engaged by responsible Officers working under the management and after providing employment for a year or two or more than that their services have been discontinued depriving them from a prospect of future employment any where else. A person like the workman when works in a department like the management, at that time he has a high hope of being regularised at a subsequent period, may be after a lapse of eight to ten years and with that hope only he works with low-wages in comparison to the regular workers of his category working in the same department. By this type of retrenchment, the worker is thrown in the open sea when he does not know how to swim and it renders him helpless to reach the shore of life regarding earning of his livelihood. Under such circumstance, the workman should not have been retrenched when he was not claiming for regularisation of his service and when according to the unchallenged evidence of W.W. Nos. 2 and 3 even now also contract labourers are engaged as and when necessary. The workman could have been utilised for such purpose. However, that was not done and since technically the termination is not illegal, a direction to that effect cannot be given. But while considering the matter as to what relief the workman is entitled to, keeping in view the aforesaid facts and circumstances, it is deemed just and proper and in the ends of natural justice that the workman should be compensated with a compensation of Rs. 5,000 (Rupees five thousand only) for the damage to his career which he has suffered for the irrational act of the management in providing him with employment from 1985 to 1987 i.e., during the ban period (according to the management) and thereafter refusing further employment as casual worker.

19. As per the aforesaid findings and discussions, it is held that under the facts and circumstances the termination of service of the workman is legally sustainable but under the further discussed fact he is found to be entitled to a compensatory compensation of Rs. 5,000 which should be paid to the workman within a period of two months from the date of publication of the Award.

The Award is passed accordingly.

Dictated & corrected by me.

P. K. TRIPATHY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 8 मार्च, 1995

का.आ. 920.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मिलिटरी फार्म डिपो के प्रबंधन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निविष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नई दिल्ली के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 8-3-95 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-14012/5/91-आई आर (डीयू.)]
के०वी०बी० उन्नी, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 8th March, 1995

S.O. 920.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi as shown in the Annexure

in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Military Farm Depot Roorkee and their workmen, which was received by the Central Government on 8-3-1995.

[No. L-14012/5/91-IR (DU)]
K. V. B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI GANPATI SHARMA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, NEW DELHI

I. D. No. 110/91

In the matter of dispute :

BETWEEN

Shri Shiv Kumar S/o Shri Teak Ram,
Village Panniyala,
P.O. Chandapur Panniyala,
Roorkee Distt. Haridwar, U.P.

Versus

The Management of Military
Farm Depot, Roorkee,
Distt. Haridwar, U.P.

APPEARANCES :

Shri R. C. Pathak with workman.

Shri O. P. Yadav with Shri Ravi Kumar Jhamb—for
the Management.

AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour vide its Order No. L-14012/5/91-IR (DU) dated 26-9-91 has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of Military Farm Depot Roorkee in terminating the services of Shri Shiv Kumar S/o Shri Tikka Ram w.e.f. 13-2-90 is justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

2. The case was fixed for management evidence when the parties arrived at settlement and made a joint statement stating therein that the workman has received letter No. E. 50/RKE/PC dated 13-12-94 sent by Lt. Col. J. S. Kadyan, Officer Incharge, Military Farm, Meerut Cantt. The terms and conditions laid down in the said letter were acceptable to the workman and he would report duty within 10 days. In view of this statement no dispute award may be given in this case.

3. In view of the statement made by both the representative for the parties the matter stands settled and no dispute award is given in this case leaving the parties to bear their own costs.

Dated : February 6, 1995.

GANPATI SHARMA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 9 मार्च, 1995

का.आ. 921.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक आफ इंडिया के प्रबंधन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निविष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नई दिल्ली के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 8-3-95 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/28/88-डी (IV) ए]
पी०जे० मार्शल डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 9th March, 1995

S.O. 921.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Export Import Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on 8-3-1995.

[No. L-12012/28/88-D.IV (A)]

P. J. MICHAEL, Desk Officer
ANNEXURE

BEFORE SHRI GANPATI SHARMA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, NEW DELHI

I. D. No. 84/88

In the matter of dispute :

BETWEEN

Shri More Singh through
The General Secretary,
All India Industrial and Commercial Workers
Union, 161-E, Kamla Nagar,
Delhi-110007.

Versus

The Deputy General Manager,
Export Import Bank of India,
Tower VIIIth Floor, Jeevan Bharti,
124, Connaught Circus,
New Delhi.

APPEARANCES :

Mr. B. M. Rao—for the workman.

Shri Pawan Kumar—for the Management.

AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour vide its Order No. L-12012/28/88-D.IV (A) dated 8-8-88 has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of Export Import Bank of India, New Delhi, in terminating the services of Shri More Singh, Car-Driver-cum-Messenger, w.e.f. 31-7-87 is justified ? If not, to what relief is the workman entitled ?"

2. On 11th April 1984, the workman was appointed by the Bank as a Driver-cum-Messenger on certain terms and conditions. He continued in the service of the Bank uninterruptedly and when a regular vacancy arose in the Bank, he was appointed against such a vacancy on 31-7-1985 as a Probationer. According to the Letter of Appointment dated 31-7-1985, the period of probation was one (1) year commencing from 1-8-1985. During the period of Probation, his services were spotless and unblemished and the Bank, on 24-3-1986, issued a letter to the workman stating that his annual increment will be postponed by 10 days. This letter about his annual increment was issued just prior to the completion of his probation. On completion of the said 1 year probation period i.e. on 1-8-1986, no action was taken by the Bank either to confirm the workman or to terminate him. In other words, the workman continued in service on successful completion of probation for 103 days. It was only then that the workman received a letter from the Bank on 11th November, 1986 to the effect that the probation was extended by 6 months with retrospective effect from 1st August, 1986. Again on 27th January, 1987 the workman's probation was extended for a second time, for another six (6) months w.e.f. 1-2-1987.

3. To his utter shock and surprise the workman on 31-7-1987, received a letter of termination from the Bank stating that the workman's services

"..... have not been found satisfactory to warrant your confirmation in the Bank's employment..... Accordingly, please note that your services in the Bank will stand terminated with effect from close of business hours on July 31, 1987."

This abrupt termination from the services of the Bank is being challenged by the workman as wrong, unlawful illegal and unjustified as the Bank gave the workman no warning, no charge sheet and no enquiry into his conduct or performance was conducted prior to termination. The workman has, therefore, prayed this Tribunal that the letter of termination be quashed and claimed reinstatement in the service of the Bank with continuity of services and full back wages.

4. The Management filed its Written Statement. Their plea is that, prior to 30 October, 1987, the Bank had only two vehicles in their Delhi Office and one vehicle was disposed of in October 1987 and the other vehicle was driven by the Officer himself (to whom the car allotted) leaving no car for the workman to drive. As such there was no vacancy in the Bank for a driver w.e.f. 1-11-1987. Further, the Bank has pleaded that, as the workman's work "was not found satisfactory", the probationary period was extended by the Bank's letter dated 11th November, 1986 and it was further extended for a 2nd time by the Bank's letter dated 27th January 1987. As the workman did not show any improvement, despite extensions of the probationary period, his services were terminated on the last day of the extended period of probation i.e. 31st July 1987. It is the case of the Bank that as the service of the workman was terminated during the period of probation, the question of issuing any charge sheet does not arise. So, the Bank has denied that the termination is illegal or wrongful or unjustified. Accordingly, the Bank refutes the claim of the workman for reinstatement with continuity of service or for full back wages.

5. On behalf of both the parties oral evidence was adduced, elaborate written arguments were filed. Subsequently, oral arguments also were addressed by representatives of both the parties. I have carefully perused the documents and heard the representatives at length. In so far as the facts are concerned, they are not such in dispute.

6. The Bank, in its Affidavit dated 20th May 1989, executed by its Deputy General Manager and Resident Representative and filed before this Tribunal has categorically stated that the workman was appointed against a "regular vacancy" of Driver-cum-Messenger. Thus, the appointment of the workman in the service of the Bank was not under a contract of employment. The workman entered the service of the Bank against a regular vacancy and hence the provisions of the Industrial Dispute Act would apply. Stated differently, the exception provided under clause (bb) of Section 2(oo) of the Act is not applicable in the present case. For this reason, the argument of the Bank that the termination of the workman would amount to "discharge simpliciter" holds no water.

6. The workman's appointment in the Bank is governed by the Letter of Appointment dated 31st July, 1985. This is a comprehensive 8-page document covering the following terms and conditions of service :

1. Package of Emoluments i.e. Basic Pay, Dearness Allowance, City Compensatory Allowance, House rent allowance.
2. Probation, Confirmation, Termination.
3. No Residential Accommodation.
4. Increments.
5. Leave i.e. Casual Leave, Privilege leave, Sick Leave.
6. Leave Travel Concession.

7. Medical Aid and Hospitalization i.e. Employee and family (Consisting of spouse and dependent parents and dependent children) covered under Bank's Health Insurance Scheme.
8. Uniforms.
9. Terminal Benefits i.e. Provident Fund, Gratuity.
10. Detailed enumeration of Duties and Responsibilities.

7. The Bank has admitted, in its Affidavit dated 13th January 1992, that there exist no rules and regulations as far as the workman staff are concerned and that all the workman are governed only by the terms and conditions of their Appointment Letters. It is clear from this, that we have to refer only to the Letter of Appointment dated 31st July, 1985 for the purpose of determining the rights and obligations of the workman and the Bank interest.

8. Paras 3 and 4 of the Letter of Appointment is relevant in this context. They are reproduced below :

- "3. You will be on probation for a period of one year. If your work and conduct are found satisfactory during the period of probation you will confirmed in the service of the Bank.
4. If your work conduct are not found satisfactory during the period of probation your services are liable to be terminated by one month's notice or on payment of emoluments for one month in lieu of notice."

A reading of clause 3 quoted above makes it clear that there exists no ambiguity that the period of probation the workman has to undergo is for a pre-determined period of one (1) year only. The Bank in terms of this clause has not reserved to itself any right or power to extend the probation period beyond the said 1 year's period. On the other hand the Bank is strictly required to make an assessment of his work and conduct at the end of the 1 year probation period, and if found satisfactory, it is incumbent on the Bank to confirm him; if not according to clause 4 (Supra), the Bank is at liberty to terminate his services on one month's notice or salary in lieu thereof.

9. The workman's probation was completed on 31-7-86. It is the admitted position of both the parties that on or before the date of completion of probation i.e. 31-7-1986 no action was taken by the Bank with respect to the confirmation in service of the workman. The Bank was not dissatisfied with the performance of the Workman all through out the probation period which explains why the Bank wrote to the workman on 24-3-86 that he will be given his increment on completion of 1 year but that the increment will be delayed by about 10 days. The Bank allowed the workman to continue in service even after the completion of the 1 year probation. He continued in service for a good 103 days after probation. Apparently, the Bank was satisfied with workman's services both during and after probation and so he was allowed to continue in the service of the Bank after probation. However, it was only on 11th November, 1986 i.e. a clear 103 days after the completion of the period of probation that the Bank issued a letter extending the period of probation by another 6 months and that too with retrospective effect.

10. The point for adjudication by this Tribunal is as to whether on completion of 1 years' probation the Bank has the power to extend the period of probation beyond the said 1 year period.

11. It is submitted on behalf of the Bank that the Bank has an absolute right to extend the probation if it is found that the services of the workman are not upto their satisfaction. There is no support for the proposition of extension of probation from the Bank's own Appointment Letter dated 31-7-1985. This letter has provided for a specific period of probation i.e. 1 year with no extensions built into clause (3). That no extensions are even contemplated by the Bank becomes obvious when the letter part of clause 3 (confirmation of service is of the said letter. The Bank

has either to confirm the workman in service if it is satisfied or terminate him if it is not satisfied, with the services of the workman. The Bank cannot resort to an extension of probation which is not permitted by either clause 3 or clause 4 quoted in para 8 above. In the light of this, I reject the argument advanced on behalf of the Bank that it has the right to extend probation of the workman contrary to the terms of the original Letter of Appointment.

12. The Learned representative for the Bank cited judgments to show that a workman's probation can be extended, being an inherent right of the Management. I have reviewed those judgments and they are not applicable to the present case as the facts in the present case are different from those in the cited cases.

13. In view of the above finding, I find that the 2 Letters of Extension dated 11th January 1986 and 27th January 1987 are illegal and have no force in law.

14. A plea was advanced on behalf of the Bank that as the workman has continued to serve the Bank on the basis of the said 2 Letters of Extension of Probation, the workman should be treated as only a probationer until his services were terminated on 31-7-1987. I do not find any merit in this argument as the two letters of Extension have no force in law in as much as, effective 1-8-1986, the workman continued in the services of the Bank after having satisfactorily completed the 1 year period of probation set forth in his original Letter of Appointment dated 31-7-1985. The workman's continuation in service after 31-7-1986 is not because of the Letters of Extension dated 11-8-1986 and 27-1-1987 but it rests on the Letter of Appointment itself.

15. On completion of workman's probation on 31-7-1986, no specific order of confirmation was passed but it is to be examined by the Tribunal as to whether, in the absence of a specific order of confirmation, the workman is to be treated as a confirmed employee or still on probation.

16. The counsel for the workman has submitted that after successful completion of probation of one (1) year as prescribed in the Letter of Appointment, the workman stood confirmed even though no formal order to this effect was passed. He relied upon a decision of the Supreme Court in State of Punjab Vs. Dharam Singh—1968 (II) SLR 247 in support of his contention that a formal order of confirmation is not necessary on the expiry of probation. After such confirmation, the Bank has no power to terminate the services of the workman on the ground of "Unsatisfactory Performance." Such an action on the part of the Bank amounts to "removal from service" which cannot be done without proper enquiry and without complying with rules of natural justice.

17. The Hon'ble Judges of the Supreme Court in State of Punjab Vs. Dharam Singh have specifically ruled that :

"formal order of confirmation is not necessary on expiry of maximum period of probation prescribed under the rules."

In the present case, clause 3 of the Letter of Appointment, provides that the maximum period of probation is one (1) year and the workman has successfully completed the maximum period and therefore the service of the workman automatically stood confirmed on 31-7-86.

18. In addition, the Learned representative for the Workman has drawn my attention to the decision of the Supreme Court in M. K. Aggarwal Vs. Gurgaon Gramin Bank, SLR 1988 (1) 791. The Learned Counsel has also placed before me a copy of the Appointment Letter dated 20-10-78 given to Mr. Aggarwal by his Employer, the Gurgaon Gramin Bank in the said M. K. Aggarwal's case to demonstrate as to how the facts in the present case are exactly similar to the facts in the above cited M. K. Aggarwal's case decided by the Supreme Court. The relevant clauses in the two letters of Appointment are shown in the Comparative Statement placed below :

Appointment Letter issued to More Singh in I. D. No. 84/88

3. You will be on probation for a period of one year. If four work and conduct are found satisfactory during the period of probation you will be confirmed in the service of the Bank.
4. If your work and conduct are not found satisfactory during the period of probation, your services are liable to be terminated by one month's notice or on payment of emoluments for one month in lieu of notice.

Appointment Letter issued to M. K. Aggarwal in M. K. Aggarwal Vs. Gurgaon Gramin Bank :

- Cl. 8 It at the end of the probationary period you are found suitable for the position of Branch Manager, You may be confirmed in the services of the Bank. Otherwise, your services will be dispensed with giving you 14 days notice or salary in lieu thereof.

19. On a careful review of clause 8 set forth above, the Supreme Court in paragraph 4 of its judgement has enunciated the law on the subject in the following words :

- "4. the limitation on the power of the employer to extend the probation beyond 18 months coupled with the further requirement that at the end of it the services of the Probationer should either be confirmed or discharged render the inference inescapable that if the probationer was not discharged at or before the expiry of the maximum period of probation then there would be an implied confirmation as there was no statutory indication as to what should follow in the absence of express confirmation at the end of even the maximum permissible limit of probation. In cases where, as here, these conditions coalesce, it has been held, there would be confirmation by implication (see State of Punjab Vs. Dharam Singh AIR 1968 SC 1210. Om Prakash Maurya Vs. U.P. Co-operative Sugar Factories Federation Lucknow, AIR 1986 SC 1844". (emphasis supplied)

20. The learned counsel for the workman has also drawn my attention to a more recent judgment delivered by the Delhi High Court in 1st August, 1991 in Jyotsna Raina Vs. Tamil Nadu Handicrafts Development Corporation and another in CWP No. 2415 of 1990. In this case, the Hon'ble High Court followed the decision of the Supreme Court in the Dharam Singh's case. Applying the principle of automatic confirmation enunciated in the Dharam Singh's case and followed by the Supreme Court in a later (1988) decision and as further applied by the Delhi High Court in the above 1991 decision, I hold that the workman stood automatically confirmed in service with effect from 1st August 1986.

21. The decision cited by the Counsel for the Management in K. A. Barot Vs. State of Gujarat—1990 (Suppl) Supreme Court cases 287 does not help the Bank. In the Barot case, the facts were quite different. Keeping in view the special facts and circumstances of the cited case, the Hon'ble Judge held that the probation does not transform itself into confirmation unless there is a specific order. The facts of the present case are similar to the case of M. K. Aggarwal Vs. Gurgaon Gramin Bank wherein it was specifically laid down that no formal order of confirmation was necessary when the maximum period of probation prescribed under the rules (i.e. Appointment Letter in the present case) had already expired.

22. The plea of the Bank that there is no maximum period of probation in the Appointment Letter is meaningless as it is against the record and as such not tenable.

23. The next point which needs determination is as to whether the Bank is justified in terminating the services of the workman who stood confirmed in the post of Driver-cum-Messenger by sending him a simple letter of termination.

It is the Bank's case that the workman was terminated for unsatisfactory performance of services. If his services were unsatisfactory during the probation period of 1 year, then the Bank could as well have terminated his services on or before 31-7-1986, but not thereafter. Once the workman is a confirmed employee, he cannot be terminated without compliance with the proper legal procedure such as charge sheet, enquiry, initiating necessary disciplinary action. The non-compliance with these procedures vitiates the letter of termination of the Bank as being illegal. Under the circumstances, the termination letter dated 31-7-87 issued by the Bank is illegal and deserve to be quashed.

24. At this stage, I propose to deal with the Bank's plea that as there is no vehicle in the Delhi Office of the Bank, he cannot be reinstated. The workman, by the terms of his Appointment Letter, was recruited in the service of the Bank and his services per se were not limited to the Bank's Delhi Office only. There is nothing on record to show that the workman's services are to be utilized only in Delhi. The Bank should reinstate the Workman either at its Head Office in Bombay or in Delhi or at any of its Offices Branches anywhere in India.

25. In view of the foregoing, I hold that the termination of the workman Shri More Singh from the service of the Export Import Bank of India not justified and the Bank should reinstate the Workman in the service of the Bank with continuity of service and 50% back wages with all consequential benefits such as increments, seniority etc. w.e.f. 1st August 1986.

26. Award passed accordingly.

Dated : 1st March, 1995.

GANPATI SHARMA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 9 मार्च, 1995

का.आ. 922.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 1947 का 14) की धारा 17 के अनुमर्ण में, केन्द्रीय सरकार म/स आर.सि.माहू के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, उड़ीसा भुवनेश्वर के पंचपद को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 8-3-95 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एन-26012/8/94-आईआर(विविध)]

बि.एम. डेविड, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 9th March, 1995

S.O. 922.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby published the award of the Central Government Industrial Tribunal, Orissa, Bhubaneswar, as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. R.C. Sahoo and their workmen, which was received by the Central Government on 8-3-95.

[No. L-26012/8/94-IR(Misc.)]

B. M. DAVID, Desk Officer

ANNEXURE

INDUSTRIAL TRIBUNAL : ORISSA :
BHUBANESHWAR

PRESENT :

Sri P. K. Tripathy, M.A.L.L.B., Presiding
Officer, Industrial Tribunal, Orissa,
Bhubaneswar.

INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO. 3 OF 1995
(CENTRAL)

Dated, Bhubaneswar, the 20th February, 1995
BETWEEN

The management of M/s. R. C. Sahoo, Con-
tractor Purunapani Limestone & Dolo-
mite Quarry of R.M.D., SAIL, At
P.O. Purunapani, Distt. : Sundergarh.

... First party-management

And

Their workmen Sri Soma and Smt. Puni re-
presented through Rourkela Shramik
Sangha, Purunapani Branch, At P.O.
Purunapani, Distt. : Sundergarh.

... Second party-workmen

APPEARANCE :

Sri S. K. Sahoo, Partner—For the first
first party-management.

Sri A. K. Pandey, Secretary of the Union.—
For the second party-workmen.

AWARD

The Government of India in the Ministry of
Labour in exercise of powers conferred upon
them by clause (d) of sub-section (1) and sub-
section (2A) of Section 10 of the Industrial Dis-
putes Act, 1947 (14 of 1947) have referred the
following dispute for adjudication vide their
Order No. L-26012/8/94-IR (Misc.) dated
29-12-90 :—

“Whether the action of M/s. R. C. Sahoo,
Contractor Purunapani Division, SAIL,
P.O. Purunapani, Distt., Sundergarh in
terminating the services of Sri Soma
and Smt. Puni from 1-7-92 is justi-
fied ? If not, what relief the work-
men are entitled to ?”

2. In this case, the representatives of both
the parties by filing a joint petition alongwith a
memorandum of settlement drawn-up in Form ‘H’,
prayed to pass an Award in terms of the settle-
ment arrived at between them. The terms of the
settlement are readover and explained to the
parties to which they admit to be true and correct.
The terms being fair, the settlement is recorded
644 GI/95—15

and an Award is passed in terms of the settle-
ment which do form part of the Award.

Dictated & corrected by me.

P: K. TRIPATHY, Presiding Officer

FORM H

FORM OF MEMORANDUM OF SETTLE-
MENT

Dated : 27th January, 1995

NAME OF THE PARTIES :

Representing the Manage-
ment

Representing the
Union/Workmen

- | | |
|--|--|
| 1. S. K. SAHOO,
Partner of M/s. R. C.
SAHOO, Contractor,
Purnapani. | 1. SRI A. K. PANDEY,
Secretary, Rourkela
Shramik Sangh,
Purnapani Branch. |
| | 2. SRI AJAMBAR
BARIK,
Secretary, Rourkela
Shramik Sangh
Purnapani
Branch. |
| | 3. SRI SOMA,
Workman. |
| | 4. SMT. PUNI,
Workman. |

Made part of the Award.

SHORT RECITAL OF THE CASE

The Secretary, Rourkela Shramik Sangh,
Purnapani Branch (herein called as Union) had
raised an Industrial Dispute against the Manage-
ment of M/s. R. C. Sahoo, Contractor Purnapani
Limestone and Dolomite Quarry, Raw Material
Division, Rourkela Zone, SAIL, PO : Purna-
pani, Distt. : Sundargarh Orissa (herein after
called as Management) over alleged illegal ter-
mination of Services of Sri Soma and Smt. Puni
w.e.f. 1-7-92 before the Assistant Labour Com-
missioner (Central), Rourkela. The dispute
was ended in failure of the conciliation report

sent by the Assistant Labour Commissioner (Central), Rourkela to the Secretary to the Govt. of India Ministry of Labour, New Delhi vide his letter No. 5(28)/93-RKL/A dt. 17-5-74. The Ministry of Labour Govt. of India considered the dispute and referred the matter to the Industrial Tribunal for adjudication as the following draft terms of reference.

“Whether the action of M/s. R. C. Sahoo contractor Purnapani Division, SAIL. PO : Purnapani, Distt. : Sundargarh terminating services of Sri Soma and Smt. Puni from 1-7-92 is justified ? If not what relief the workmen are entitled to ?”

Subsequently the union has filed the claim statement before the Honourable Industrial Tribunal, Orissa Bhubaneswar, which is still sub-judice. In the mean time again both the parties discussed the matter mutually and settled the issue amicably on the following terms.

TERMS OF SETTLEMENT

- (1) It is agreed by the parties that Sri Soma and Smt. Puni will be taken into roll in their existing capacity. (Miner-cum-Loader P.R.W.) w.e.f. 28th January, 1995.
- (2) It is agreed by the parties that for the period from 1-7-92 to 27-1-95 the workmen will not claim any amount of wages, salary or fringe benefits but they salary or fringe benefits but they will get continuity of service.
- (3) It is agreed by the parties that the workmen or the union will never raise any dispute or any court case before any authority in future and the matter will be settled for ever.
- (4) It is agreed by the parties that both the parties will file the copies of the settlement before the Hon'ble. Industrial Tribunal to close the matter and pass no any dispute award.
- (5) It is agreed by the parties that both the parties will maintain harmonious Industrial relation for the shake of better productivity and Industrial peace.

Signature of the Parties

Representing the Management Representing the Union/Workmen

Sd/-

(S. K. SAHOO)

WITNESS :

- | |
|---|
| 1. (BHAJU LOHAR) 1. (A. K. PANDEY)
Sd/- Sd/- |
| 2. (S. KANGARI) 2. (A. BARAIK)
Sd/- Sd/- |
| 3. (B. PRADHAN) 3. (SRI SOMA)
Sd/- Sd/- |
| 4. (SMT. PUNI) |

Copy forwarded for information and necessary action to :—

1. The Asstt. Labour Commissioner (Central), Rourkela.
2. The Regional Labour Commissioner (Central), Bhubaneswar.
3. The Chief Labour Commissioner (Central), New Delhi.
4. The Secretary to Govt. of India, Ministry of Labour, New Delhi.

For Workmen	For Management
(A. K. PANDEY)	(S. K. SAHOO)
Secretary, RSS Union	Partner
Purnapani Branch.	M/s. R. C. SAHOO.

नई दिल्ली, 9 मार्च, 1995

का.आ. 923.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बिहार स्टेट माईनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के प्रबंधकों के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नं. 2 धनबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 08-03-95 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-29011/16/91-आईआर (विधि)]

वि. एम. डेविड, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 9th March, 1995

S.O. 923.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby published the award of the Central Government Industrial Tribunal, (No. 2), Dhanbad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bihar State Mineral Development Corporation Ltd. and their work-

men, which was received by the Central Government on 08-03-95.

[No. L-29011/16/91-IR(Misc.)]
B. M. DAVID, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

Present :

Shri D. K. Nayak, Presiding Officer.

In the matter of an Industrial Dispute under
Section 10(1)(d) of the I. D. Act,
1947.

REFERENCE NO. 129 OF 1991

PARTIES :

Employers in relation to the management of
Bihar State Mineral Development Cor-
poration Ltd., Koderma and their work-
men.

Appearances :

On behalf of the workman : Shri Rameshwar
Modi, the concerned workman.

On behalf of the employers : Shri D. K.
Verma, Advocate.

STATE : Bihar INDUSTRY : Mica Mines
Dated, Dhanbad, the 28th February, 1995

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour
in exercise of the powers conferred on them under
Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 has re-
ferred the following dispute to this Tribunal for
adjudication vide their Order No. L-29011/16/91-
I.R. (Misc.) dated, the 9th September, 1991.

SCHEDULE

"Whether the action of the Zone Management
BSMDC Ltd., Kodarma Mica Unit, P.O.
Distt. Hazaribagh by terminating/dismis-
sing the services of Sri Rameshwar Modi
without observing the provisions of Sec.
25(F) of the I.D. Act, 1947 is legal and
justified ? If not, what relief the workman
concerned is entitled to ?"

2. Pursuant to the reference made above I am
to decide the case with reference to the Written
Statement filed by the parties (both management
and the workmen) the evidence on record and sub-
sequent development, if any.

3. The written statement was sent by the con-
cerned workman under his signature dt. 3-10-91 under

Regd. Post with A/D stating that the Govt. of Bihar.
Deptt. of Mines and Geology, Patna by its letter
No. 4565/M dt. 11-7-88 appointed him as Sales
Assistant, by the Bihar State Mineral Development
Corporation Ltd., Ranchi by its office Order No.
3572 dt. 8-8-1988 posting him at Kodarma Mica
Unit and he was assured by the Bihar Government
that his services would be regularised on suitable
pay scale.

4. The further case of the workmen in the Writ-
ten Statement is that for the completion of con-
tinuous work for a term of 14 months in he Cor-
poration dismissing him with effect from 4-10-89
without observing the relevant provisions of the
I. D. Act, 1947 it was illegal and thereby he was
reappointed by the Govt. of Bihar. However, even
after reappointment the order of said reappoint-
ment the order was implemented before 3rd April,
1991 and thereby he is entitled to the salary from
October, 1989 to 4th April, 1991 i.e. for the period
of wrongful termination of his services as alleged

5. The management in his Written Statement-
cum-rejoinder has submitted that the appointment
of the concerned workman Shri Modi was purely
temporary in the Unit concerned and the same was
terminated as a result of non-renewal of the con-
tract and the allegation of termination without ob-
serving the formalities of I.D. Act do not stand
thereby application of Section 25F is not sustain-
able of course he was reappointed pursuant to the
order of the Bihar Government and for the reasons
of his reappointment as it was not reinstatement by
the order of the competent authority, the concerned
workman is not entitled to get the salary from Octo-
ber, 1989 to 4-4-1991 which he has claimed.

6. The concerned workman in his rejoinder ag-
ainst the written statement of the management dt.
18-8-92 has stated that though it is a fact that he
was re-appointed as per order of Bihar Government
his service was not temporary nor he can be depr-
ived from the aid of Section 25F of the I. D. Act.
1947 for the reasons he rendered a continuous ser-
vice for 14 months in the management concerned.
It is stated further as he was retrenched he should
be dealt with under the relevant provision of I.D.
Act, 1947 and he is entitled to get the wages with
all benefits during the services to be continuous one
in respect of his idle period.

7. On perusal of the facts stated in the Written
Statement and on perusal of the documentary and
oral evidence one fact remains up-disputed that the
concerned workman was re-appointed on 4-10-89
by the Order of the Bihar Government which is the
annexure of this case dt. 11-7-88 bearing Memo
No. 4565 marked Ext. W-2. It is also not dispu-
ted that the concerned workman was reappointed
by letter marked as Ext. W-3 and by virtue of the
said letter he joined in the services on 4-10-88 and
till now he is working there.

8. Ext. W-1 also goes to show that the initial appointment of the concerned workman was absolutely temporary one for a term of 3 months of course it was extended from time to time.

9. No doubt if the concerned workman confines himself to get relief under I.D. Act the present matter could be dealt with in the ambit of the said Act and it could be held whether the dismissal was illegal or unjustified. But the thing which happened in the meantime and it was accepted by the concerned workman without any protest accepted the re-appointment as per order of the Govt. of Bihar so it cannot be presumed that he accepted his re-appointment with any reservation.

10. In this context let us come to the evidence on record of the concerned workman where he has stated that he joined in the post after order of re-appointment by the Govt. of Bihar under protest. But it is needless to say that there is no lots of materials on record to show that he joined in service with any protest or without prejudice his rights for earlier termination available to him.

11. Though there cannot be any estoppel against statute but the role of estoppel can be well played by the act of the parties concerned due to his omission or commission of certain acts.

12. The facts and circumstances clearly go to show that he opted to accept the re-appointment without claiming his prior wages or with having any reservation of his past right.

13. Moreover, it goes to show clearly that his services was of temporary nature and as per contract it was terminated. So he is not entitled to get the benefit which can be awarded under I.D. Act as his termination was not in compliance of Section 25F of the I.D. Act, 1947.

14. It is needless to say that already he was accepted the re-appointment in the post where he was and he is discharging his duties in the same post and in the same manner as he was in that case simply it can be accepted that he got new appointment on and from 4-10-1991 through the intervention of the Govt. of Bihar and at present it is futile to adjudicate whether the termination or dismissal of the concerned workman from the services without observing the provision of Section 25F of I.D. Act, 1947 was legal and justified as he relinquished the said claim in a way by accepting the re-appointment under the order of Bihar Government. Accordingly it is held that the first part of the reference about the legality and justifiability of the termination of the concerned workman calls for no decision and thus this part of reference is disposed off.

15. Now, I come to the next part of the reference which is connected and incidental to the

first part of the reference. The said point is whether the concerned workman is entitled to get the back wages for the period from 1-10-89 to 3-4-1991 i.e. for 18 months 3 days with compensation.

16. As I have already observed that he was not reinstated but re-appointed in the same post through the intervention of the Bihar Government without making any comment about the continuity of his services or back wages and when the concerned workman has accepted such re-appointment without any protest or without any reservation of his previous right this Tribunal is not inclined to hold that his services to be considered to be continuous one from the date of his first joining in the management concerned temporarily pursuant to the Ext. W-1 dated 8-8-88 nor he is entitled to get the back wages for the idle period i.e. for the period from 1-10-89 to 3-4-1991.

An Award is passed accordingly.

D. K. NAYAK, Presiding Officer

नई दिल्ली, 9 मार्च, 1995

का.आ. 924.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मैसर्स आर.सि.साहू के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, उड़ीसा भुवनेश्वर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 8-3-95 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-26012/30/93-आई आर (विविध)]

वि.एम. डेविड, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 9th March, 1995

S.O. 924.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby published the award of the Industrial Tribunal, Orissa, Bhubaneswar. As shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. R.C. Sahoo, and their workmen, which was received by the Central Government on 8-3-95.

[No. L-26012/30/93-IR(Misc.)]

B. M. DAVID, Desk Officer

1 ANNEXURE

INDUSTRIAL TRIBUNAL : ORISSA :
BHUBANESWAR

PRESENT :

Sri P. K. Tripathy, M.A.L.L.B., Presiding
Officer, Industrial Tribunal, Orissa,
Bhubaneswar.

INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO. 56
OF 1994 (CENTRAL)

Dated, Bhubaneswar, the 20th February, 1995

BETWEEN :

Dictated & corrected by me.

The management of M/s. B.C. Sahoo, contractor Purunapani Limestone & Dolomite Quarry of R.M.D., SAIL, At|P.O. Purunapani. Distt. : Sundergarh.
... First party-management.

P. K. TRIPATHY, Presiding Officer

And

Case No. ID-56/94C

FORM II

Their workmen Sri Ramdhan Lakwa, Sadhu Lakwa, Raghu Singh and Smt. Bahamani represented through Rourkela Shramik Sangha, Purunapani Branch, At|P.O. Purunapani, Distt. : Sundergarh.

FORM OF MEMORANDUM OF SETTLEMENT

Dated : 27th January, 1995

... Second party-workmen.

NAME OF THE PARTIES :
REPRESENTING THE
MANAGEMENT

APPEARANCES :

Sri S.K. Sahoo, Partner—For the First party—management.

Made part of the Award,

Sri A.K. Pandey, Secretary of the Union—
For the second party—workmen.

Sd/-
Presiding Officer.

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour in exercise of powers conferred upon them by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) have referred the following dispute for adjudication by this Tribunal vide their Order No. L-26012/30/93-1R (Misc.) dated 3-10-94 :—

“Whether the action of the management of M/s. R. C. Sahoo, Contractor, Purunapani Limestone & Dolomite Quarry, Raw Material Division, Rourkela Zone, Steel Authority of India Ltd., P.O. Purunapani, Distt., Sundergarh in terminating the services of Shri Ramdhan Lakwa, Sri Sadhu Lakwa, Sri Raghu Singh and Smt. Bahamani from 5-10-91 is Justified ? If not, to what relief the workmen are entitled ?

2. In this case, the representatives of both the parties by filing a joint petition alongwith a memorandum of settlement drawn-up in Form ‘H’, prayed to pass an award in terms of the settlement arrived at between them. The terms of the settlement are read over and explained to the parties to which they admit to be true and correct. The terms being fair, the settlement is recorded. Accordingly, an Award is passed in terms of the settlement which do form part of the Award.

644 GI/95—16.

REPRESENTING THE
UNION|WORKMEN

1. S. K. SAHOO,
Partner of M/s.
R. C. SAHOO,
Contractor, Purnapani.
1. SRI A.K. PANDEY,
Secretary, Rourkela
Shramik Sangh, Purnapani Branch.
2. SRI AJAMBAR BARIK,
Secretary, Rourkela
Shramik Sangh, Purnapani Branch.
3. SRI RAMDHAN LAKHWA,
Workmen.
4. SRI SADHU LAKHWA,
Workmen.
5. SRI RAGHU SINGH,
Workmen.
6. SMT. BAHAMANI,
Workmen.

SHORT RECITAL OF THE CASE

The Secretary, Rourkela Shramik Sangh, Purnapani Branch (herein called as Union) had raised an Industrial Dispute against the Management of M/s. R. C. Sahoo, Contractor Purnapani Limestone and Dolomite Quarry, Raw Material Division, Rourkela Zone, SAIL, P.O. : Purnapani, : Sundargarh, Orissa (herein after called as Management) over alleged illegal termination of services of 1. Sri Ramdhan Lakhwa, 2. Sri Sadhu Lakwa 3. Sri Raghu Singh 4. Smt. Bahamani w.e.f. 5-10-91 before the Assistant Labour Commissioner (Central), Rourkela. The dispute was ended in failure of the conciliation report sent by the Assistant Labour Commissioner (Central) (Rourkela to the Secretary to the Govt. of India Ministry of Labour, New Delhi vide his letter No. 5(139)/92-RKL/A dt. 17-11-93. The Ministry of Labour Govt. of India considered the dispute and referred the matter to the Industrial Tribunal for adjudication as the following draft terms of reference.

“Whether the action of Management of M/s. R. C. Sahoo Contractor Purnapani Limestone and Dolomite Quarry, Raw Material Division, Rourkela Zone, Steel Authority of India Ltd., PO : Purnapani, Distt. Sundargarh in terminating the services of Sri Ramdhan Lakhwa, Sri Sadhu Lakhwa, Sri Raghu Singh and Smt. Bahamani from 5-10-91 is justified ? If not, what relief the workmen are entitled ?

Subsequently the union has filed the claim statement before the Honourable Industrial Tribunal, Orissa Bhubaneswar, which is still sub-judice. In the mean time again both the parties discussed the matter mutually and settled the issue amicably on the following terms.

TERMS OF SETTLEMENT

(1) It is agreed by the parties that Sri Ramdhan Lakhwa, Sri Sadhu Lakhwa, Sri Raghu Singh and Smt. Bahamani will be taken into roll in their existing capacity. (Miner-cum-Loader P.R.W.) w.e.f. 28th January, 1995.

(2) It is agreed by the parties that for the period from 5-10-91 to 27-1-95 the

workmen will not claim any amount of wages, salary or fringe benefits but they salary or fringe benefits but they will get continuity of service.

(3) It is agreed by the parties that the workmen or the union will never raise any dispute or any court case before any authority in future and the matter will be settled for ever.

(4) It is agreed by the parties that both the parties will file the copies of the settlement before the Hon'ble Industrial Tribunal to close the matter and pass no any dispute award.

(5) It is agreed by the parties that both the parties will maintain harmonious Industrial relation for the shake of better productivity and Industrial peace.

Signature of the Parties

Representing the Management
Sd/-

(S. K. SAHOO)

Sd/-

Representing the Union/Workmen

1. (A.K. PANDEY)

Sd/-

2. (A. BARAIK)

L.T.I. of

3. (RAMDHAN LAKHWA)

L.T.I. of

4. (SADHU LAKHWA)

L.T.I. of

5. (RAGHU SINGH)

R.T.I. of

6. (SMT. BAHAMANI)

WITNESS :

Sd/-

1. (BHAJU LOHAR)

Sd/-

2. (S. KANGARI)

Copy forwarded for information and necessary action to :—

1. The Asstt. Labour Commissioner (Central), Rourkela.

2. The Regional Labour Commissioner (Central), Bhubaneswar.

3. The Chief Labour Commissioner (Central), New Delhi.

4. The Secretary to Govt. of India, Ministry of Labour, New Delhi.

For Workman

For Management

Sd/-

Sd/-

(A. K. PANDEY)

(S. K. SAHOO)

Secretary, RSS, Union,

Partner

Purnapani Branch.

M/s. R. C. SAHOO

नई दिल्ली, 10 मार्च, 1995

का.आ. 925.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 91क के साथ पठित धारा 88 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम प्रवर्तन से मैसर्स जैसा संलग्न सूची में दर्शाया गया है, में नियुक्त नियमित कर्मचारियों को 30-9-94 तक की जिसमें यह दिनांक भी सम्मिलित है की अवधि के लिए छूट प्रदान करती है।

2. पूर्वोक्त छूट की शर्तें निम्नलिखित हैं, अर्थात्:—

(1) पूर्वोक्त कारखाना, जिसमें कर्मचारी नियोजित है, एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें छूट प्राप्त कर्मचारियों के नाम और पदाभिधान दिखाये जायेंगे,

(2) इस छूट के होते हुए भी, कर्मचारी उक्त अधिनियम के अधीन ऐसी प्रविधाएं प्राप्त करते रहेंगे, जिनको पाने के लिए वे इस अधिमूचना द्वारा दी गई छूट के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व संदत्त अभिदायों के आधार पर हकदार हो जाते,

(3) छूट प्राप्त अवधि के लिए यदि कोई अभिदाय पहले ही किए जा चुके हों, तो वे वापस नहीं किए जाएंगे,

(4) उक्त कारखाने का नियोजक, उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवर्तमान था (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त अवधि" कहा गया है), ऐसी विवरणियां ऐसे प्रारूप में और ऐसा विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देती थी,

(5) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक, या निगम का इस, निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी:—

(i) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी की विशिष्टियों को मत्यापित करने के प्रयोजनार्थ,

(ii) यह अभि निश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा

यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं, या

(iii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी, नियोजक द्वारा दिये गए उन फायदों को, जिसके प्रतिफल स्वरूप इस अधिमूचना के अधीन छूट दी जा रही है नकद में और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं, या

(iv) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन किया गया था या नहीं, निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा:—

(क) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करने कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जिसे उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी आवश्यक समझता है,

(ख) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभोगाधीन किसी कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके प्रभारी से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय से संबंधित ऐसे लेखा, बहियां और अन्य दस्तावेज, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करे और उनकी परीक्षा करने दे, या उन्हें ऐसी जानकारी दें, जिसे वे आवश्यक समझते हैं, या

(ग) प्रधान या अव्यवहित नियोजक की, उसके अधिकर्ता या सेवक की, या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना, या

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल तैयार करना या उससे उद्धरण लेना।

अनुसूची

क्रमांक फैक्ट्री/संस्थान का नाम	दिनांक जिस दिन से छूट दी गयी
1. शाल दी यूनितस् आफ मैसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., बम्बई	
2. शाल दी यूनितस् आफ मैसर्स भारत पेट्रोलियम लि., बम्बई	

1	2	3	1	2	3
3.	मैसर्स मारुति उद्योग लि., गुडगावा, हरियाणा		21.	मैसर्स नेशनल इनवीरमेन्टल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नागपुर अन्डर दी सीएसआई आर	
4.	मैसर्स हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लि., लखनऊ		22.	मैसर्स नेशनल इंस्ट्रुमेंट्स लि., जाइवपुर (कलकत्ता)	
5.	मैसर्स हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लि., कानपुर		23.	मैसर्स कारपोरेट ऑफिस आफ मैसर्स नेशनल टैक्सटाईल कार- पोरेशन (यूपी) लि. कानपुर	
6.	मैसर्स हिन्दुस्तान जिक लि., उदयपुर		24.	कारपोरेट ऑफिस आफ मैसर्स एन.टी.सी. (दिल्ली, पंजाब एंड राजस्थान, नई दिल्ली)	
7.	मैसर्स नेशनल एल्युमीनियम कं. लि., विशाखापटनम		25.	कारपोरेट ऑफिस आफ मैसर्स हिन्दुस्तान लाटैक्स लि., त्रिवेन्द्रम (पूजापुरम)	
8.	मैसर्स इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोपरेटिव लि., कलौल डिस्ट्रिक्ट, गांधीनगर (गुजरात)		26.	मैसर्स सेन्ट्रल टूल रूम, लुधियाना	
9.	मैसर्स नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. भटिंडा		27.	मैसर्स सेन्ट्रल टूल रूम एंड सेन्टर कलकत्ता	
10.	मैसर्स इंस्ट्रुमेंटेशन लि., कोटा		28.	मैसर्स सेन्ट्रल रोड टेक्नोलॉजिकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैसूर	
11.	मैसर्स राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि., बम्बई		29.	ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लि., कानपुर (मुख्य कार्यालय)	
12.	मैसर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि., गाजियाबाद (उ.प्र. (क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली एण्ड लाईसन ऑफिसर, आगरा)				
13.	मैसर्स इंडियन टेलिफोन इन्स्टीट्यूट लि., रायबरेली				
14.	मैसर्स कम्प्यूटर सैन्ट्रेंस कारपोरेशन, नई दिल्ली				
15.	मैसर्स भारत गोल्ड साइन्स लि., कोलार गोल्ड फिल्ड्स, कर्नाटक				
16.	मैसर्स हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि. विशाखापटनम				
17.	मैसर्स कोचीन शिपयार्ड लि., कोचीन				
18.	मैसर्स फिल्ड वर्कशॉप एण्ड मैरीन वर्कशॉप आफ टुटीकोरीन पोर्ट ट्रस्ट, टुटीकोरीन				
19.	मैसर्स भारत हैवी पलेट्स एण्ड बीसेल्स लि., विशाखापटनम				
20.	मैसर्स इंस्टीट्यूट आफ डेसिग एण्ड इलेक्ट्रीकल मैसुरिंग इन्स्ट्रु- मेंट्स, बम्बई				

[संख्या एम-38014/10/94-एम.एस.-I]

जयप्रकाश शुक्ल, अवसर सचिव

(स्पष्टीकरण ज्ञापन)

इस मामले में छूट को भूतलक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है क्योंकि छूट के आवेदन पर कार्यवाही करने में समय लगा था, किन्तु यह प्रमाणित किया जाता है कि छूट को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

New Delhi, the 10th March, 1995

S.O. 925.—In exercise of the power conferred section 88 read with section 91-A of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby exempts the regular employees of the Factories/Establishments specified in the schedule hereto from the operation of the said Act for a period with effect from the 1st October, 1994 upto and inclusive of the 30th September, 1997.

2. The above exemption is subject to the following conditions namely :—

(1) The aforesaid establishment wherein the employees are employed shall maintain a

- register showing the name and designations of the exempted employees;
- (2) Notwithstanding this exemption, the employees shall continue to receive such benefits under the said Act which they might have become entitled to on the basis of the contributions paid prior to the date from which exemption granted by this notification operates;
 - (3) The contributions for the exempted period, if already paid, shall not be refunded;
 - (4) The employer of the said factory/establishment shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said act (hereinafter referred to as the said period) such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950;
 - (5) Any inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other official of the Corporation authorised in this behalf shall for the purpose of :—
 - (i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of Section 44 for the said period; or
 - (ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or
 - (iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or
 - (iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory to empowered to :
 - (a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary; or
 - (b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employee at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such inspector or other official and allow him to examine accounts, books and other documents relating to the employment of personnel and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or
 - (c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee; or
 - (d) make copies of or take extracts from any register, account book or other documents maintained in such factory, establishment, office or other premises.

SCHEDULE

Sl. No.	Name of the Establishment/Factory
1.	All the Units of M/s. Hindustan Petroleum Corporation Limited, Bombay.
2.	All the Units of M/s Bharat Petroleum Limited, Bombay.
3.	M/s. Maruti Udyog Limited, Gurgaon, Haryana.
4.	M/s. Hindustan Aeronautics Limited, Lucknow.
5.	M/s Hindustan Aeronautics Limited, Kanpur.
6.	M/s Hindustan Zinc Limited, Udaipur.
7.	M/s National Aluminium Company Limited, Visakhapatnam.
8.	M/s. Indian Farmers Fertilisers Cooperative Limited, Kalol District, Gandhinagar (Gujarat).
9.	M/s National Fertiliser Limited, Bhatinda.
10.	M/s Instrumentation Limited, Kota.
11.	M/s Rashtriya Chemicals & Fertilisers Limited, Bombay.
12.	M/s Bharat Electronics Limited, Ghaziabad (UP) (including their Regional Offices in New Delhi and liaison Officer at Agra).
13.	M/s Indian Telephone Industries Limited, Raibareli.
14.	M/s Computer Maintenance Corporation, New Delhi.
15.	M/s Bharat Gold Mines Limited, Kolar Gold Fields, Karnataka.

Sl. No. Name of the Establishment/Factory

16. M/s Hindustan Shipyard Limited, Vishakhapatnam.
17. M/s Cochin Shipyard Limited, Cochin.
18. M/s Field Workshop and Marine Workshop of Tuticorin Port Trust, Tuticorin.
19. M/s Bharat Heavy Plates and Vessels Limited, Visakhapatnam.
20. M/s Institute of Design and Electrical Measuring Instruments, Bombay.
21. M/s National Environmental Engineering Research Institute, Nagpur, under the CSIR.
22. M/s National Instruments Limited, Jadavpur (Calcutta).
23. M/s Corporate Office of M/s National Textile Corporation (UP) Limited, Kanpur.
24. Corporate Office of M/s N.T.C. (Delhi, Punjab & Rajasthan, New Delhi).
25. Corporate Office of M/s Hindustan Latex Limited, Trivandrum (Poojapuram).
26. M/s Central Tool Room, Ludhiana.
27. M/s Central Tool Room & Training Centre, Calcutta.
28. M/s Central Food Technological Research, Institute, Mysore.
29. British India Corporation Limited, Kanpur. (Head Office only).

[No. S-38014/10/94-SS-I]

J. P. SHUKLA, Under Secy.

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case as processing of the applications for exemption took time. However, it is certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of any body adversely.

नई दिल्ली, 29 मार्च, 1995

का.आ. 926.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार कन्टोन्मेंट बोर्ड के प्रबंधन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निहित औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, बम्बई नं. 2 के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 6/3/95 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल: 13012/3/89-डी 2(वी)]

के.वी.बी. उन्नी, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 29th March, 1995

S.O. 926.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal Bombay No. 2 as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to the management of Cantonment Board and their workmen, which was received by the Central Government on

[No. L-13012/3/89-D-2(B)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2 BOMBAY

PRESENT:

Shri S. B. Panse, Presiding Officer.

REFERENCE NO. CGIT-2/44 OF 1989

Employers in relation to the management of Ahmedabad Cantonment Board, Ahmedabad.

AND

Their Workmen

APPEARANCES:

For the Employers: Mr. A. N. Kulkarni Advocate

For the Workmen: Mr. H. R. Acharya Representative, Bombay, dated 23rd November, 1994

AWARD

Shri Rammilan B. Kori was appointed as a Chowkidar on daily wages in the month of September 1984 and was being paid the wages at the rate of Rs. 15 per day by the Opponent. The payment was made monthly. He continued in the services without any break and completed 240 days in a year. He performed his duties faithfully, diligently, properly and obediently to the satisfaction of his superiors. When he had been continued in the services, after the completion of 240 days of service, he made an oral request to the Ahmedabad Cantonment Board to take him in the regular vacancy. When he was not taken into the regular vacancy, he approached the union for redress.

2. The union contended that several efforts were made and the decision was taken by the Joint Consultation Machinery at the local level and at the command level wherein it was agreed to take the workman in a regular vacancy. But even then no orders were made and hence it raised an industrial dispute before the settlement Commissioner. He in turn sent a negative report of the same to the Labour Ministry. Ultimately it sent the reference to this Tribunal for adjudication. It is in the following terms:

"Whether the management of Ahmedabad Cantonment Board has deprived Shri Rammilan B. Kori from getting regular wages w.e.f. September 1984 and regular appointment as Chowkidar with all other consequential benefits?"

3. The Cantonment Board opposed the claim for appointment Shri Rammilan Kori in a regular vacancy of Chowkidar with effect from September 1984, and for payment of regular wages from the date with other consequential reliefs on the ground that he was not appointed through proper channel, i.e. from the employment exchange. It is averred that the decision taken by the Cantonment Board wilfully are not in respect of the case of the workman but they are of the general nature. It is further averred that the rules for appointments are mentioned in the Cantonment Board Service Rules 1937 and the relaxing authority is the Government of India and nobody else can relax the same. It is averred that unless the Government of India, Ministry of Defence, regularises the service of the workman who is the Competent Authority nobody else has the power to relax it. The Authority has no powers to relax a particular provision of the rules. Under such circumstance, it is submitted that the prayer of the workman cannot be granted.

4. My Learned Predecessor framed issue for determination at Exh. 5. The issues and my findings thereon are as under :

ISSUES	FINDINGS
1. Whether the management of Ahmedabad Cantonment Board has deprived Sri Rammilan Kori from getting regular wages w.e.f. Sept. 84 and regular appointments as Chowkidar with all other consequential benefits?	In the negative
2. If so, to what relief the workman is entitled?	Does not survive
3. What Award?	As per order below

REASONS

5. Shri K. M. Acharya, the General Secretary of the Ahmedabad Cantonment Board Employees Union had filed his affidavit at Exh. 7 and affirmed that Shri Rammilan Kori was working on a daily wage as a Chowkidar from September 1984 to January 15, 1985 and again from 7-2-85 to 28-2-86 as per the certificate issued by the C.E.O. dt. 16-3-1986. He admitted that a general decision was taken regarding the regularisation of the services of the employees who had worked for more than 240 days in the meeting of J.C.M. held on 13-6-1988, and not particularly in respect of the workman concerned. That clearly goes to show that the decision relating to regularisation of the services of the workman was not taken in one particular meeting. Shri G. S. Rajeshwaran (Exh. 8) the Executive Officer of the Ahmedabad Cantonment Board tried to affirm that the workman had not worked from September 1984 but had worked from November 1984 appears to be without any basis because the certificate issued by the Board which is on the record clearly goes against the version. He had affirmed that the Central Government had powers to relax the Mandatory regulation of appointment of only those candidates who are sponsored by the employment exchange. Admittedly Shri Rammilan B. Kori was not sponsored by the employment exchange. He had further affirmed that the Board had no powers to regularise his vacancy. Through his cross-examination, nothing is brought on the record to support the case of the workman.

6. Alongwith Exh. 6 a letter which was sent by the President of the Union to the Tribunal, letter sent by the Under Secretary to the Government of India, to the District General Director of Defence states, Ministry of Defence is produced on the record. It states as under :

"In relaxation of Rule 5-B(i) of the Cantonment Fund Servants Rules, 1987, I am directed to convey the sanction of the President to the regularisation of services of the Cantonment Board Employees of Ahmednagar Cantonment with effect from the dates shown against each in Annexure-I to this letter."

This clearly goes to show that the Government considers the case of the persons whose appointments are to be regularised. The case of the workman also falls under the same cadre. It is for the Government to decide whether his services has to be regularised or not. This document helps the management i.e. the Opponent than the workman.

7. On behalf of the Opponent reliance was placed on Delhi Development Horticulture Employees Union v/s. Delhi Administration, Delhi and Others 1992, 1, CLI 537. They say that the case wherein the workers who work on daily wages in some departments have claimed that they be appointed as regular labourers. Their contention was rejected while doing so THEIR LORDSHIPS in para 23 said that :

"Apart from the fact that the petitioners cannot be directed to be regularised for the reasons given above, we may, take note of the pernicious consequences to which the direction for regularisation of workmen on the only ground that they have put in work for 240 days or more days, has been leading. Although there is Employment Exchange Act which requires recruitment on the basis of registration in the Employment Exchange, it has become a common practice to ignore the Employment Exchange and the persons registered in the Employment Exchange, and to employ and get employed directly those who are either not registered with the Employment Exchange or though registered are lower in the long waiting list in the Employment Register. The Courts can take judicial notice of the fact that such employment is sought and given directly for various illegal considerations including money. The employment is given first for temporary periods with technical breaks to circumvent the relevant rules, and is continued for 240 or more days with a view to give the benefit of regularisation knowing the judicial trend that those who have completed 240 or more days are directed to be automatically regularised. A good deal of illegal employment market has developed resulting in a new source of corruption and frustration of those who are waiting at the Employment Exchange for years. Not all those who gain such back door entry in the employment are in need of the particular jobs. Though already employed elsewhere, they join the jobs for better and secured prospects. That is why most of the cases which comes to the courts are of employment in Government Departments, Public Undertakings or Agencies. Ultimately it is the people who bear the heavy burden of the surplus labour. The other equally injurious effect of indiscriminate regularisation has been that many of the agencies have stopped undertaking casual or temporary works though they are urgent or essential for fear that if those who are employed on such works are required to be continued for 240 or more days have to be absorbed as regular employees although the works are time-bound and there is no need of the workmen beyond the completion of the works undertaken. The public interests are thus jeopardised on both counts."

8. The observations made in this para is aptly applicable to the set of facts before me. The workman concerned was appointed on a daily wages as a Chowkidar without asking the Employment Exchange to send names for the said appointment. As this is so, while appointing the worker on daily wages the Appointing Authority has contravened the provisions relating to the appointments and now the workman cannot take the benefit of the fact that he worked for more than 240 days in a particular year and is entitled to get the service in a regular vacancy. Relying on the observations on the above said Authority I find that there is no justification in the case of the workman and I record my findings on the points accordingly and pass the following order :

ORDER

1. The management of Ahmedabad Cantonment Board has not deprived Shri Rammilan B. Kori from getting regular wages w.e.f. September 1984, and regular appointment as Chowkidar with all other consequential benefits illegally.

2. No order as to costs.

Dated : 23-11-1994.

S. B. PANSF, Presiding Officer

